हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

15 मार्च, 1988

खण्ड 1, अंक 2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 15 मार्च, 1988

पृष्ठ संख्या

शोक प्रस्ताव	(2)1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)2
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)22
वर्ष 1987– 88 के सप्लीमैंटरी ऐस्टिमेट्स (दूसरी किस्त)पेश करना	(2)36
ऐस्टिमेट्स कमेटी की वर्ष 1987– 88 के सप्लीमैंटरी ऐस्टिमेट्स (दूसरी किस्त) पर रिपोर्ट पेश करना	(2)36
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा	(2)37
बैठक का समय बढानों	(2)81
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(2)81

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 15 मार्च, 1988

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9—30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा)ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, यह सदन बिहार के भूतपूर्व राज्य मैली, श्री हेमन्त कुमार झा, के 14 मार्च, 1988 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री हेमन्त कुमार झा पहली बार, 1969 में बिहार विधान सभा के सदस्य चुने गए और उसके पश्चात् फिर 1972 तथा 1980 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनैतिक नेता, एक लोकप्रिय जन नेता तथा समाजवादी कार्यकर्ता से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक—संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: अब डा० मंगल सैन बोलेंगे।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, (शोर एवं विघ्न)

चौधरी तैयब हुसैन: स्पीकर साहब, अगर डा० साहब को बोलने का ज्यादा शौक है तो वे इधर आकर बैठ जाए। विरोधी

पार्टी का नेता होने की वजह से मेरा बोलने का पहला हक है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप इनके बाद बोल लेना क्योंकि मैं इनको काल अपौन कर चुका हू

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर साहब ने जो शोक प्रस्ताव रखा है मैं अपने आपको उसमें शामिल करता हूं। कल ही बिहार के भूतपूर्व राज्य मंत्री महोदय का निधन हुआ है और उसके लिए शोक व्यक्त किया गया है। मैं उसका समर्थन करते हुए, उस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

चौधरी तैयब हुसैन (तावडू): मोहतरिम स्पीकर साहब, पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर साहब ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं अपनी पार्टी को और अपने आपको उसके जजबात से जोड़ता हूं। स्पीकर साहब, झा साहब के निधन से मुल्क का काफी नुक्सान हुआ है। वे एक सक्रिय नेता थे। पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर ने जिन भावनाओं को प्रकट किया है, मैं अपने आपको उनके साथ जोड़ता हूं और दुःखी परिवार के साथ पूरी हमदर्दी प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, 24 घंटे के अन्दर अन्दर यह एक और शोक प्रस्ताव हाउस के सामने आया है मुझे इसका दुःख है। मैं विधान सभा की तरफ से दुःखी परिवार को आपका

सन्देश भेज दूंगा। अब मैं हाउस से रिक्वैस्ट करूंगा कि डिपार्टिड लीडर की याद में खड़े होकर दो मिनट की साइलैंस औबजर्व की जाए।

(इस समय दिवंगत नेता के सम्मान में सदन के सदस्यों ने खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Upgradation of 33 K.V. Sub-Station at Sagga and setting up of 33/66/132 K.V. Sub-Station in District Karnal.

***150. Shri Jai Singh Rana :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade 33 K.V. Sub-Station at sagga in District Karnal ;

(b) if so, the time by which the said Sub-Station is likely to be upgraded ;

(c) whether any new 33 K.V. or 66K.V. or 132 K.V. Sub-Stations in Nilokheri Constituency of district Karnal are proposed to be set up ; and

(d) if so, the location there& togetherwith the time by which such Sub-Stations are likely to be set up ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क)हां

(ख)2 वर्ष

(ग)तथा (घ)इसी प्रकार वर्ष 1990–91 तक 33 के० वी० सब–स्टेशन अमीन को भी अपग्रेड करना प्रस्तावित है।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने बताया है कि 33 के० वी० तब–स्टेशन अमीन को भी अपग्रेड करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है....

श्री अध्यक्ष: आर्य जी, मन्त्री जी ने जो कुछ कह दिया वह तो कह दिया। जो कुछ आप कहना चाहते हैं, वह कहें। रैपीटीशन की एक गल्त परम्परा पड़ जाती है। आप जो कुछ पूछना चाहते हैं वह पूछें।

श्री हीरा नन्द आर्य: क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि एक स्टेशन या सबस्टेशन को स्थापित करने का क्या आधार है और ऐसे आधार वा ने प्रदेश में कितने स्थान हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, किसी सब–स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए या उसकी कैपेसिटी औगमैट करने के लिये किसी जगह कितना लोड हो गया है यह क्राईटेरिया है। जब हम किसी जगह 33 के० वी० का सब–स्टेशन लगाते हैं तो वहां मैक्सीमम 12 एम०बी०ए० तक का लोड होना चाहिये। अगर 12

एम० बी० ए० से लोड बढ़ जाए तो उस सब–स्टेशन की अपग्रेडेशन के लिये सोचा जा सकता है। ज्यों– ज्यों कनैक्शंज बढ़ते रहते हैं वहां अपग्रेडेशन की जरूरत होती जाती है। यह कोई नहीं कह सकता कि किस एरिया का अपग्रेडेशन होगा और किस समय होगा। यह लोड की इंक्रीज पर डिपैन्ड करता है।

श्री जगपाल सिंह चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि शहजादपुर में 33 के० वी० का सबस्टेशन लगाने का काम कब तक पूरा हो जाएगा?

Mr. Speaker : It is not possible for the Minister to reply to this question as it does not arise out of the main question.

Sale of Adulterated Liquor

@*412. Shri Ranjit Singh : Will the Minister for Home be pleased to state—

(a) the total number of complaints received against the liqour vend owners (wine contractors) for selling adulterated liquor in the State, districtwise, during the period from 1st April, 1982 to 29th February, 1988;

(b) whether any complaints have been received from the villagers/ Village Panchayats regarding auctioning of country liquor vends in their villages ; if so, the number thereof togetherwith the action, if any, taken thereof ; and

(c) whether any complaints have also been received regarding violation of instructions in respect of

timings for opening of liquor shops in villages, towns and cities in the State during the period from 1st April, 1982 to 29th February, 1988; if so, the number thereof district-wise ?

Mr. Speaker : Extention has been asked for in respect of this question which has been granted. The communication received from the Minister concerned in this connection reads as under :-

Interim reply

अं०स०प०क्र०1061—अंक— 3— 88/874

मन्त्री गृह

विभाग, हरियाणा

सम्पत सिंह

चण्डीगढ़।

दिनांक 14— 3— 1988

विषयः— विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 412 जो श्री रणजीत सिंह विधायक द्वारा पूछा गया है, के बारे सूचना उपलब्ध करने सम्बन्धी।

प्रिय मैं आपको सूचित करता हूं कि तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 412 जो श्री रणजीत सिंह, विधायक द्वारा पूछा गया है, का उत्तर विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 15— 3— 1988 को देय है, किन्तु इस प्रश्न का उत्तर देने सम्बन्धी सूचना

जो वांछित है, वह अभी जिला कार्यालयों से प्रतीक्षित है। अतः मेरे विचार में इस प्रश्न का उत्तर दिनांक 15– 3– 1988 को देना सम्भव न होगा। इन परिस्थितियों में, मैं आभारी हूंगा यदि आप इस प्रश्न का उत्तर तैयार करने हेतु कम से कम 15 दिन की बढ़ोतरी दें।

सादर, आपका,

ह०/–

(सम्पत सिंह)

श्री एच०एस० चड्ढा

अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा,.

चण्डीगढ।

Opening of Army Recruiting Office at Rewari

***129. Shri Raghu Yadav :** Will the Chief Minister be pleased to state the steps, if any, taken or proposed to be taken by the State Government for having an Army Recruiting Office set-up at Rewari together with the time by which the said office is likely to start functioning ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : The question of opening an Army Recruiting Office at Rewari has been taken-up with the Government of India, Ministry of Defence, Kendriya Sainik Board, New Delhi. It is difficult to state as to when the said office is likely to be set-

up by them. Consequently, the time by which this will start functioning can not be specifically stated.

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, हमारे गुडगांव जिले में एक भर्ती दफ्तर था लेकिन आपात काल के दौरान चौधरी बन्सी लाल की सरकार ने उस भर्ती दफतर को वहां से बदलवा दिया था। क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह भर्ती दफतर जो हमारे इलाके की जरूरतों को पूरा करता था, उसको वहां से क्यों तबदील करवा दिया गया? इस्के क्या कारण थे? ऐसा करके हमारे इलाके के साथ क्यों अन्याय किया गया है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं?

श्री हीरा नन्द आर्यः मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि रिवाड़ी के अन्दर दोबारा भर्ती दफतर खोलने के लिए क्या भारत सरकार के साथ कोई पत्र व्यवहार किया गया है? अगर पत्र व्यवहार किया गया है तो उसका क्या उत्तर आया है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, पहली दफा नवम्बर में एक चिट्ठी लिखी गई थी उसके बाद चार पांच रिमाईडर भी भारत सरकार को दिये गये हैं लेकिन आज तक उनका कोई उत्तर नहीं आया।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इसी प्रकार के और भर्ती दफतर

हरियाणा के अन्दर किसी और जगह भी खोलने के लिये भारत सरकार से कोई पत्न–व्यवहार चल रहा है या नहीं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, डिफैन्स मिनिस्टरी का यह विचार है कि आज तक जितने भर्ती दफतर हरियाणा प्रान्त में हैं, वे पहले ही अधिक है औरों की आवश्यकता नहीं है।

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, अगर रक्षा मन्त्रालय का यह विचार है कि हरियाणा के अन्दर और नये भर्ती दफतरों की आवश्यकता नहीं है तो जो हमारे इलाके में पहले भर्ती दफतर था, क्या उस भर्ती दफतर को वहां पर वापिस उसी क्षेत्र में लाने के लिए राज्य सरकार कोई प्रयास करेगी? क्या इस बारे में भारत सरकार से पत्र व्यवहार करने का सरकार कोई विचार रखती है ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके?

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से रिवाड़ी के लिये प्रस्ताव भेज दिया गया है लेकिन आज तक जो भर्ती दफतर खोले जाते थे या पहले भी जो भर्ती दफतर खोले जाते रहे हैं वे सब डिफेन्स मिनिस्ट्री की ही ताकत में है वही सब कुछ करती है। हमारी सरकार का इसमें बहुत कम दखल है। बहुत कम क्या हमारा इसमें बिल्कुल दखल नहीं है। हम तो केवल इसके लिये रिक्वैस्ट ही कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह ट्रान्सफर करना यह डिफैन्स मिनिस्ट्री का ही काम है। यह सब काम उनके अपने क्राइटेरिया के अनुसार ही होते हैं।

Construction of Sehlanga-Dhalanwas Road

***132. Rao Ram Narain :** Will the Minister for P.W.D. (B & R) be pleased to state—

(a) whether Government is aware of the fact that the construction of the road from village Sehlanga to village Dhalanwas, in District Rohtak, which was started during the year 1977, has not so far been completed ; and

(b) if so, the reason thereof together with the time by which the construction work of the above said road is likely to be completed ?

लोक निर्माण मन्त्री (श्री ओम प्रकाश भारद्वाज):

(क)सेहलगा से ढलानवास सड़क सिवाये 0— 17 कि० मी० के जोकि रेलवे क्रौसिंग के पास कि० मी० 7 में है, पूरी हो चुकी है।

(ख)यह भाग पूरा नहीं हो सका क्योंकि इसके लिये भूमि अभी तक अभिग्रहण नहीं की जा सकी। भूमि अभिग्रहण संबंधी कार्यवाही जल्दी ही होने की संभावना है तथा यह गैप 1988—89 में पूरा कर लिया जाएगा।

राव राम नारायण: स्पीकर साहब, यह सड़क 1977 में शुरू हुई थी। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि अब तक इस छोटे से टुकड़े को कम्पलीट करने के लिये जमीन ऐक्वायर करने की प्रोसीडिंग्ज पूरी क्यों नही हुई?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, जमीन ऐक्यायर नही हुई थी इसलिए यह गैप रह गया।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस सड़क के लिये जो जमीन अधिग्रहण की जानी है वह अभी तक क्यों नहीं हुई और इस जमीन को अधिग्रहण करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, हजारों ऐसे केसिज पड़े हैं जिनमें अभी तक जमीन की ऐक्विजीशन नहीं हो पाई है।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस बारे में कोई कानूनी अड़चन है जिसके कारण वह जमीन ऐक्वायर नहीं हो पाई या किसी किसान ने स्टे ले लिया है? सरकार ने इस बारे में अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, इस जमीन को ऐक्वायर करने के लिए सैक्शन 6 के नोटिस हो चुके हैं और उम्मीद है कि अब यह काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया।

Mr. Speaker : Mr. Madan, the Minister has already given the -reply.

Centres for Educating Unemployed Youth

***137. Shri Durga Dutt Attri :** Will the Minister of State for Cooperation be pleased to state—

(a) whether any centres are proposed to be opened in the State during the year 1988-89 for educating the unemployed youth under the self-employment scheme ; and if so, the details of the scheme ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) :

(a) No, Sir.

(b) In view of (a) above, question does not arise.

Mr. Speaker : Mr. Madan, the Minister has already given the -reply.

Centres for Educating Unemployed Youth

***137. Shri Durga Dutt Attri :** Will the Minister of State for Cooperation be pleased to state—

(b) whether any centres are proposed to be opened in the State during the year 1988-89 for educating the unemployed youth under the self-employment scheme ; and if so, the details of the scheme ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) :

(c) No, Sir.

(d) In view of (a) above, question does not arise.

श्री दूर्गा दत्त अत्रीः स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के विचाराधीन कोई और ऐसी योजना है जिसके तहत बेरोजगारों को रोजगार दिलाया जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, सरकार समय समय पर रिक्त स्थानों की ऐडवर्टाइजमैंट करती रहती है और जौ लड़के लड़कियां जिस जिस नौकरी के लिये काबिल होते हैं उनको नौकरी में लगाया जाता है। अब काफी पोस्टों के लिए इन्टरव्यू चल रहे हैं। इसके अलावा बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये सरकार और भी कोशिश करेगी।

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, कल राज्यपाल के अभिभाषण में भी जिक्र आया था कि रोजगार विभाग के रिक्ति रजिस्टर में रोजगार हेतु आवेदकों की अत्यधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार विभाग के समस्त रिकार्ड को कम्पयूटर द्वारा रखने की व्यवस्था है। यानी ऐम्पलाय– मैट एक्सचेंजिज का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि बेरोजगारों को ऐम्पलायमैंट ऐक्सचेंजिज के जरिए नौकरी क्यों नहीं मिलती? क्या उनको कम्पयूटराइज करने के बाद सभी बेरोजगारों को एम्पलायमैंट एक्सचेंजिज के जरिये से ही नौकरी मिलेगी या वे रोजगार

कार्यालय ही बने रहेंगे जहां पर बेरोजगारों के नामों के रजिस्टरों की रद्दी इकट्ठी होती रहती हे?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, यह इंस्ट्रक्शंज हैं, इंस्ट्रक्शंज ही नहीं बल्कि ला है कि सभी नौकरियां ऐम्पलायमैंट ऐक्सचेंजिज के थू या पब्लिक सर्विस कमिशन या एस० एस० एस० बोर्ड के थ्रू दी जाती हैं। जहां तक ऐम्पलायमैट ऐक्सचेंजिज के आधुनिकीकरण की बात है वे बहुत अच्छे ढंग से चल रही हैं। ऐम्पलायमैंट ऐक्सचेंजिज के खिलाफ किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। अगर माननीय सदस्य के नोटिस में कोई शिकायत है तो बताएं। इस बारे में जो भी सुझाव ये देंगे सरकार बड़ी खुशी से उस बारे में विचार करेगी।

श्री कैलाश चन्द शर्माः स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सैल्फ ऐम्पलायमैंट के अन्तर्गत बेरोजगारों को अपने काम धंधे के लिये बैंकों से जो कर्जे की राशि दी जा रही है वह अपर्याप्त है। क्या उस राशि को बढ़ाने का कोई विचार **श्री अध्यक्षः** इस सवाल का मेन सवाल से कोई संबंध नहीं है। इसके लिये सैपरेट नोटिस चाहिए।

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, रोजगार कार्यालयों में काफी लड़कों के 10– 10 साल से नाम दर्ज हैं लेकिन उन्हें आज तक कोई भी काल नहीं आई है। काल न आने की वजह से जो लड़के किसी काम का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं और जब वे

अपना नया अनुभव दर्ज कराने के लिये रोजगार कार्यालयों में जाते हैं तो उनका अनुभव बगैर रिश्वत लिए दर्ज नहीं किया जाता। यह आम शिकायत सभी रोजगार कार्यालयों के बारे में सुनी जाती है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः जो बात इन्होंने कही है, वह ठीक नहीं है। इन्होंने एक बेरोजगार सेना बनाई हुई है और उस सेना के ये सेनापति हैं। स्पीकर साहब, जब दिल्ली से दक्षिण की ओर जाते हैं तो दीवारों पर लिखा होता है कि रिश्ते ही रिश्ते। उनके पास रिकार्ड होता है। इसी प्रकार से यादव साहब के पास बेरोजगार सेना का हिसाब–किताब होगा। (विघ्न)

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने बताया कि बेरोज– गारी को दूर करने के लिये लोगों को ऐम्पलायमैंट ऐक्सचेजिज और पब्लिक सर्विस कमीशन व एस० एस० एस० बोर्ड के जरिए रोजगार दिया जाता है। मुझे सारे हरियाणा के बारे में तो मालूम नहीं लेकिन फरीदाबाद में विभिन्न महकमों में जैसे हुड़ा कम्पलैक्स, जन–स्वास्थ्य या दूसरे महकमों में, सैकड़ों लोगों को बाहर से लाकर रोजगार दिया गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिला स्तर से बिना डिमान्ड आये इन लोगों को उपरलिखित नियमों की अवहेलना करके किस प्रकार लगाया गया और उन स्थानीय लोगों को जिनके नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज हैं तथा जिनका हक छीना गया है क्या उनको सरकार रोजगार देने की व्यवस्था करेगी?

Mr. Speaker : Chaudhri Mahender Partap Ji, this question relates to a number of departments. There seems to be no justification of raising such a supplementary on this question.

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः वैसे तो मेरा सप्लीमैंटरी इसी सवाल से संबंधित है। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि जो बात मैंने कही है वह सरकार के नोटिस में है या नहीं। यदि इनके नोटिस में बै तो ये बता दें ताकि वहां के लोगों को रोजगार में अपना हक मिल सके।

श्री अध्यक्षः इस सप्लीमैंटरी का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

Construction of Grain/Vegetable Market Gohana

***177. Shri Kishan Singh Sangwan :** Will the Minister of State for Agriculture be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the Grain/Vegetable Market at Gohana ; and

(b) if so, the time by which the work for the construction thereof is likely to be started/completed ?

कृषि राज्यमन्त्री (श्री बलबीर सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने साथी श्री किशन सिंह सांगवान साहब को बताना चाहूगा कि गोहाना में अनाज मण्डी और सब्जी मण्डी बनाने के लिये 50 एकड़ जमीन पर बहुत जल्दी ही काम शुरू होने वाला

है। इसके लिये 9– 3– 1988 को एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने भूमि का चयन कर लिया है और कल ही उस की रिपोर्ट मार्किटिंग बोर्ड के पास पहुंची है। मैं अपने साथी को विश्वास दिलाता हूं कि गोहाना में अनाज मण्डी और सब्जी मण्डी का निर्माण कार्य बहुत जल्दी शुरू हो जायेगा और ये दोनों मण्डियां 1992 तक बन कर तैयार हो जाएंगी।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार गोहाना में नई सब्जी मण्डी और अनाज मण्डी बनायी जायेगी क्या उसी प्रकार से कोई मण्डी हथीन में भी बनाये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि है तो कब तक बन जायेगी?

श्री बलवीर सिंहः स्पीकर साहब, इसके लिए ये अलग से नोटिस दें, जवाब दे दिया जायेगा।

श्री कैलाश चन्द शर्माः मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या नारनौल में भी कोई सब्जी गाडी बनाये जाने का विचार है?

श्री अध्यक्षः आप भी अलग से नोटिस दें।

तारांकित प्रश्न संख्या 160

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, श्री मोहिन्द्र सिंह दहिया, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Bridge on Drain No. 1 in Tehsil Panipat

***156. Shri Satbir Singh Kadian :** Will the Minister for P.W.D. (B & R) be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the road from Ahar to Atawala in Tehsil Panipat (District Karnal) was completed during the year 1983-84 ; and

(b) if so, whether the bridge on Tributary Drain No. 1 between the above said two villages has been constructed/completed ; if not, the reasons thereof ?

लोक निर्माण मन्त्री (श्री ओम प्रकाश भारद्वाज):

(क)जी हां, केवल ट्रिब्यूटरी ड्रेन नं० 1 पर पुल को छोड़ कर।

(ख)ट्रिब्यूटरी पर पुल पर्याप्त धन–राशि उपलब्ध न होने के कारण नहीं बनाया गया है।

श्री सतबीर सिंह कादयानः क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि कोई सड़क बनाने के साथ साथ पुल बनाने का भी ऐस्टीमेट बनाया जाता है या नहीं? अगर पुल का ऐस्टिमेट साथ ही बनाया जाता है तो यह पुल क्यों नहीं बना?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः अहर से अटावला तक पहले ही एक लिंक रोड बन चुकी है। अहर लिंक रोड के लिये धन पर्याप्त न होने के कारण पुल नहीं बन पाया। उसका ऐस्टीमेट बन

चुका है और एस० ई० करनाल को टैंडर मांगने के लिये कहा गया है। मैं समझता हू कि जल्दी ही यह बन जायेगा।

श्री सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, पिछले 6– 7 साल से यह सड़क बन चुकी है लेकिन पुल के बिना उस सड़क की कोई यूटिलिटी नहीं है। जब उस सड़क पर पुल बनाने का ऐस्टीमेट बना हुआ था तो वह पुल. क्यों नहीं बना? इसके लिए कौन जिम्मेवार है?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः फिलहाल पैदल चलने वालों के लिये और हल्की यातायात के लिये हयूम पाईप डाल कर चलने योग्य रास्ता बना दिया गया है।

श्री परमानन्दः स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस पुल को बनाने के लिये पैसा कब मांगा गया था? चार साल गुजर गये हैं। क्या वे बताएंगे कि किस कारण से पैसा नहीं मिला?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, मैंने पहले ही अर्ज किया है कि हयूम पाईप डाल कर रास्ता बना दिया गया है। पहले भी एक और सड़क है जो इन गांवों को मिलाती है। धन काफी न होने के कारण यह पुल नहीं बन पाया। अब जल्दी ही बन जायेगा।

श्री परमानन्दः स्पीकर साहब, मैंने मंत्री जी से यह पूछा था कि उन्होंने यह पैसा कब मांगा था और अब तक क्यों नहीं

मिला? उन्होंने कारण नहीं बताये इसलिये न मिलने का कारण बताने का कष्ट करें।

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, मैंने पहले ही बताया है कि धन काफी न होने के कारण इस पुल को बनाने का काम टेक अप नहीं किया गया। हयूम पाईप डाल कर लोगों की सुविधा के लिये रास्ता पहले ही बनाया जा चुका है।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी बड़ी सूझबूझ वाले हैं। वे अपना जवाब स्पष्ट कर दें कि हरियाणी में कितने ऐसे गांव है जिनको सड्कों से अभी तक नही जोड़ा गया है?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः टोटल गांव 6745 हैं जिन में से 6648 गांव सड्कों से जोड़े जा चुके हैं। बाकी 97 गांव ऐसे रहते हैं जिनको अभी सड्कों से जोड़ा जाना **चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः** स्पीकर साहब, कुछ सड़कें पिछली सरकार ने बनानी शुरु कर दी थीं लेकिन अभी तक वे कम्पलीट नहीं हुई हैं और बहुत सी ऐसी सड़कें भी हैं जिनको बनाने का निर्णय हो चुका है लेकिन सरकार ने अभी तक उन्हें बनाना शुरू ही नहीं किया है। क्या मन्दी महोदय बताएंगे कि इन सड़कों के बारे में सरकार की क्या पालिसी है? जो सड़कें पिछली सरकार ने बनाई हैं, उनका क्रैडिट तो कांग्रेस सरकार को जाता है, लेकिन जिन सड्कों पर अर्थ–वर्क वगैरा हो चुका है या शुरू की जानी हैं, उन को

कम्पलीट किये जाने की क्या आपको चिन्ता है? अगर है तो सरकार अपनी पालिसी स्पष्ट करे (व्यवधान)मेरे हल्के में एक सड़क ऐसी है जो इनकम्पलीट पड़ी हुई है.... (व्यवधान)

चौधरी तैयब हुसैनः अध्यक्ष महोदय, जब एक मैम्बर बोल रहा हो तो क्या कोई दूसरा मैम्बर उसको इन्ट्रप्ट कर सकता है?. (व्यवधान)

एक मैम्बरः आप क्या कर रहे हैं? क्या आप इन्ट्रप्ट नहीं कर रहे? .. (व्यवधान)

चौधरी गेल प्रताप सिंहः मैं यह सवाल कर रहा था कि जो पिछली सरकार ने नीति सम्बन्धी फैसला किया था, जिन सड्कों को पास करके काम शुरू कराया था क्या सरकार उनको पूरा करने का इरादा रखती है? यदि इरादा रखती है तो कब तक इन्हें पूरा कर देगी? स्पीकर साहब, मेरे हल्के में एक सड़क है जिस का अर्थ–वर्क भी कम्पलीट हो चुका है। यह केवल 2.50 किलोमीटर का टुकड़ा है जिससे 56 गांव सीधे शहर से जुडते हैं। ऐसा करने से सरकार को तथा जनता को फायदा है। मैं मन्दी जी से जानना चाहूंगा कि इस सड़क को, जो गांव हतौला से सीधे फरीदाबाद कचहरियों को जाती है कब तक पूरा करने का इरादा है?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, हमारी कोशिश यही है कि जब ऐडिक्वेट फन्डज उपलब्ध हो जाएंगे तो सभी सड्कों को, जो इनकम्पलीट पड़ी हैं, पूरा कर देंगे।

श्री भगवान सहाय रावतः स्पीकर साहब, मेरा व्यवस्था का प्रश्न भी है और एक सप्लीमैंटरी भी है।

श्री अध्यक्षः कवैश्चन आवर में आप केवल सप्लीमैंटरी ही पूछ सकते हैं।

श्री भगवान सहाय रावतः मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या राज्य में सड्कों के साथ साथ अनाज मण्डियां भी पूरी बनाई गई हैं?

श्री अध्यक्षः यह कोई सवाल नहीं है, आप बैठ जाइये।

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में पिछली कांग्रेस सरकारों ने पूरे देश के अन्दर ढोल पीटा कि हम ने तमाम गांवों को सड्कों से जोड़ दिया है। लेकिन मैं केवल अपने हल्के के बारे में बताना चाहता हूं कि मेरे हल्के में 5– 6 गांव अभी भी सड्कों से नहीं जुड़े हैं। स्पीकर साहब, पिछली कांग्रेसी सरकारें इस तरह से देश के लोगों की आयने में धूल झोंक रही थीं या फ्राड कर रही थी। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इन गांवों को सड्कों से जोड़ने के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, हमने इस वर्ष अब तक 7 गांवों को सड्कों से जोड़ दिया है जब कि हमारा टारगैट 10 गांवों को सड्कों से जोड़ने का था।

श्री लछमन सिंह कम्बोजः स्पीकर साहब, कई बार अकस्मात ऐसी बात होती है जैसे 1982 में कांग्रेस का राज आया और हम विरोधी पक्ष में थे। उस समय इन्दरी हल्के में टूटी हुई सड़कें थीं। उनकी रिपेयर पिछली सरकार ने नहीं करवाई और आज भी नहीं हुई। इस इलाके के अन्दर 20 गांव ऐसे हैं जिनमें कोई भी पक्की सड़क नही। क्या उन गांवों को पक्की सड्कों से जोड़ा जाएगा?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः जी हां, यदि यह गांव सरकार की नीति में कवर होते होंगे तो धन मिलने पर जोड़ा जाएगा।

10.00 बजे।

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय बड़ी सूझ बूझ वाले हैं, इनको बड़ी नालेज है और जनरल जवाब दे रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि मेरी कांस्टिचुएसी में सिरसा में रानिया से डबवाली सड़क है। उसके ऊपर एक ओटू पुल है। वह पुल खराब होने की वजह से दो सौ गांवों का रास्ता बन्द हो चुका है। वह रास्ता तकरीबन एक साल से बन्द है। मन्त्री जी को पता है कि उसकी मंजूरी भी दे दी गई थी और जब मैं पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी था तो उस पर काम भी

शुरू हो गया था लेकिन उसके बाद काम बन्द करवा दिया गया। क्या मन्त्री जी बताएंगे कि उस काम को कब तक चालू करवा देंगे? यह दो सौ गांवों का मसला है।

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, इस पर जल्दी ही काम चालू हो जाएगा।

श्री जगपाल सिंह चौधरीः स्पीकर साहब, क्या मन्त्री जी के नोटिस में है कि मोरनी हिल्ज के तीन सौ गांव बगैर सड्कों के हैं? क्या ये बताएंगे कि उनके बारे में ये क्या कर रहे दू?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, गवर्नमैंट की यह पालिसी है कि जो डायरैक्टरी विलेजिज हैं हम पहले उनको ही लेते हैं। हरियाणा में 98 प्रतिशत गांव सड्कों से जोड़े जा चुके हैं सिर्फ योग्य 37 गांव बाकी हैं जो आने वाले सालों में सड्कों से जोड़े जाएंगे।

उप मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मोरनी क्षेत्र के लिये तो एक स्पैशल डिवैल्पमैंट बोर्ड बनाया गया है जिसका नाम मोरनी हिल्ज डिवैल्पमैंट बोर्ड है। यह इसी उद्देश्य के लिये बनाया गया है कि वह सारे मोरनी एरिया का समुचित विकास करे।

Construction of a Minor from Barwala Branch

***165. Shri Atma Ram Godara :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Minor from Barwala Branch to irrigate non-command area of villages Khanpur, Sindhar, Singhwa Ragho, Masudpur and Majhod ; and

(b) if the reply to part (a) above be in the negative, the steps, if any, taken or proposed to be taken by the Govt. for providing irrigation facilities in the above said area ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) :

(a) No

(b) A scheme for constructing Singhwa Minor from RD. 0-23700; off-taking at RD. 9000-L Kharakheri Disty. and costing Rs. 65.50 lacs for the un-commanded areas of villages Khanpur Sindhar, Singhwa Ragho, Masudpur and Majhod has been sanctioned.

श्री आत्मा राम गोदाराः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने लिखित जवाब में खाराखेड़ी डिस्ट्रीव्यूटरी लिखा है और सदन में खरकड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी कहा है। मच्छी जी स्पष्ट करें कौन सा ठीक नाम है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः इसका नाम खरखेड़ी ही है। अगर आपके पास कोई और नाम हो तो इसे खरखेड़ी ही मान लें।

श्री आत्मा राम गोदाराः क्या इस डिस्ट्रीव्यूटरी की इतनी कैपेसिटी है कि इसमें से माइनर निकाली जा सकती है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः जी हां, बिल्कुल निकाली जा सकती है।

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न के बारे में सिंचाई मंत्री जी से एक जानकारी हासिल करना चाहता हूं। रिवाड़ी क्षेत्र के अन्दर कई ऐसे गांवों के समूह हैं जिनका भूमिगत जल खारा है अतः ट्यूबवैल्ज द्वारा वहां पर सिंचाई सम्भव नही है। इस बार जल की समस्या काफी गम्भीर है। ऐसे गांवों के समूह जो मेरे क्षेत्र में या और कही पर भी हरियाणा में हैं, क्या उनके लिये कोई विशेष सिंचाई सुविधा देने के लिये सरकार पग उठा रही हे?

श्री वीरेन्द्र सिंहः फिलहाल तो कोई पग विचाराधीन नहीं हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या 190

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, श्री वेद सिंह मलिक, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Imparting Health Education to Students in Hathin

***211. Shri Bhagwan Sahai Rawat :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to impart Health Education to the students in Government Schools in district Gurgaon in

Hathin constituency ; and

(b) if so, the details thereof togetherwith the steps, if any, taken or proposed to be taken by the Government for the said purpose ?

Education Minister (Shri Khurshid Ahmed) :

(a) There is already a scheme for Health Education in all the schools in the State.

(b) Question does not arise in view of (a) above.

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके नोटिस में एक बात लाना चाहूंगा। किस तरह मेरे प्रश्न में इररैगुलैरिटी हुई है, हो सकता है इसी तरह की दूसरे प्रश्नों में भी हुई होगी। मैंने प्रश्न पूछा था कि मैडिकल ऐजूकेशन के बारे में सरकार क्या करने जा रही है और यहां पर जो प्रश्न आया है वह हैल्थ ऐजूकेशन के बारे में है। साथ ही हथीन क्षेत्र को गुड़गांव के साथ जोड़ दिया गया है। इनको यह मालूम होना चाहिये कि हथीन गुड़गांव में नहीं पड़ता बल्कि हथीन तो फरीदाबाद जिले में पड़ता है। इसलिये मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि मेरे हथीन हल्के में बच्चों को मैडीकल ऐजूकेशन देने के बारे में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री खुरशीद अहमदः स्पीकर साहब, क्वैश्चन पढ़ने से साफ जाहिर है कि यह सवाल हैल्थ ऐजूकेशन के बारे में पूछा

गया है। इस बारे में कोई कन्फयूजन नहीं है। आप सवाल को पढ़ें—

"Whether there is any proposal under consideration of the Government to impart Health Education to the students in Government Schools in district Gurgaon in Hathin Constituency".

पहली बात तो यह है कि गुड़गांव हथीन कास्टीचुऐंसी में नहीं आता और हथीन कास्टिचुऐंसी गुडुगांव में नही आती। इस बात को छोड़ दें। दूसरी बात यह है कि हैल्थ ऐजूकेशन तो सिर्फ गवर्नमैंट स्कूल्ज में हो सकती है। Medical education is to be imparted only in the Medical Colleges. शायद यह कन्फयूजन इनको हो सकता है। स्कूलों में सिर्फ हैल्थ ऐजूकेशन हो सकती है। ऐन्वायरनमैट, हाईजीन और दूसरी —हैल्थ ऐजूकेशन की बातें आ सकती हैं। फिजीकल पी०टी० वगैरा आ जाती है। यही हैल्थ ऐजूकेशन होती है। स्कूलों में पी० टी० आईज० और डी० पी० ईज० होते है जो इसकी देखभाल करते हैं। हमारे गवर्नमैंट स्कूलों में तो यही ऐजूकेशन हो सकती है। इनमें मैडीकल ऐजूकेशन नहीं आती। जहां तक मैडीकल ऐजूकेशन का सवाल है, that is totally a separate question and I am unable to answer anything about medical education.

श्री भगवान सहाय रावतः मैंने हैल्थ ऐजूकेशन का कहीं सवाल नहीं दियय है.। मैंने तो होडल कालेज में मैडीकल

ऐजूकेशन के बारे में लिखा था। वह तो सैपरेट क्वैश्चन था। मुझे मालूम है कि हैल्थ ऐजूकेशन हमारे सारे स्कूलों में लगी है।

श्री खुरशीद अहमदः स्पीकर साहब, सवाल जहां तक छपा है, उसको अगर बार–बार भी पढ़ा जाए तो भी उसका जवाब वही निकलता है जो मैंने दे दिया है। इसको कितनी ही बार पढ़ लें। हैल्थ ऐजूकेशन कभी मैडीकल ऐजूकेशन नहीं बन सकती। किसी तरह से भी इन्टरप्रैट कर लें। इन्टरप्रेटेशन को हम चाहे कहीं पर खींच कर ले जाएं but it will be too far fetched to treat it as medical education.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, आप मैम्बर के ओरिजनल क्वैश्चन को देख लें कि उसमें क्या लिखा है?

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, मैंने ओरिजनल सवाल निकलवा लिया है उसमें लिखा है–

".....

"(a) the steps being taken by the Government for imparting health education to the students.

डाक्टर साहब, इसमें भी हैल्थ लिखा है।

श्री मंगल सैनः ठीक है जी।

श्री हीरा नन्द आर्यः मन्त्री महोदय ने बताया है कि हैल्थ ऐजूकेशन के लिए पी० टी० आईज० लगा रखे हैं। क्या

मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि प्राईमरी स्कूलों में भी हैल्थ ऐजूकेशन देने के लिए पी० टी० आईज० लगा रखे है?

श्री खुरशीद अहमदः स्पीकर साहब, प्राईमरी स्कूलों में जे० बी० टी० एक या दो होते हैं उन्हीं के जिम्मे यह काम होता है कि प्राईमरी स्कूलों में बच्चों की देखभाल करें। पहले कई स्कूलों में एक जे०बी०टी० होता था लेकिन अब दो करने जा रहे हैं।

श्री रघु यादवः क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक आहार देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री खुरशीद अहमदः स्पीकर साहब, पौष्टिक आहार देने के लिए न्यूट्रीशन प्रोग्राम का दूसरे विभागों के जरिए इन्तजाम होता है।

श्री परमानन्दः क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जे०बी०टी० टीचर्ज को जब जे०बी०टी० की ट्रेनिंग दी जाती है तो क्या उनको हैल्थ ऐजूकेशन देने की ट्रेनिंग भी दी जाती है?

श्री खुरशीद अहमदः जे०बी०टी० ट्रेनिंग में यह सब कुछ बताया जाता है कि बच्चों की सफाई कैसे रखते हैं क्योंकि प्राईमरी स्कूल में बच्चों के मुंह धोने की भी जरूरत पड़ जाती है।

***208. Seth Lachhman Das Bajaj : Will** the Minister for Health be pleased to state whether it is a fact that due attention has not been paid towards the encouragement of Ayurvedic and Unani System of medicine in the State during the last 15 years ; if so, the steps, if any, taken or proposed to be taken to encourage this system of medicine ?

स्वास्थ्य तथा आयुर्वेद मंत्री (श्रीमती कमला वर्मा): नहीं। आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिए पिछले 15 वर्षो के दौरान 184 आयुर्वेदिका यूनानी औषधालय, 2 आयुवैंदिक अस्पताल 45 बिस्तरों की क्षमता वाले खोले गए हैं। श्री कृष्ण राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, कुरुक्षेत्र के प्रबन्ध तथा कार्य को बेहतर बनाना सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार ने इसका प्रबन्ध तथा नियन्त्रण अपने अधीन ले लिया है। इस अवधि के दौरान आयुर्वेदिक विभाग का बजट प्रावधान 275.90 लाख रुपए बढ़ गया।

सेठ लछमन दास बजाज: क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि हरियाणा में आयुवेदिक तथा यूनानी प्रैक्टिश्नर्ज की रजिस्ट्रेशन करने का काम फिर करेंने? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगी कि अब तक कितने डाक्टर्ज ने रजिस् ट्रेशन के लिए प्रार्थना–पत्र दिए और उनमें से कितने स्वीकार किए गए हैं?

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, रजिस्ट्रेशन के लिए सैन्ट्रल ऐक्ट बना हुआ है। 3 1–3– 1970 को ऐक्सपीरियंस के

बेसिज पर रजिस्ट्रेशन शुरू की गई थी। रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 24–9–1970 को बना था। 24165 ऐप्लीकेशंज रजिस् ट्रेशन के लिए 30–6– 1972 तक आई थीं। 11012 ऐप्लीकैट्स को रजिस्टर किया था। 2635 ऐप्लीकेशंज जो कंडीशंज ले डाउन की गई थीं, उनके पूरी न होने के कारण, रिजैक्ट की गई। 10491 ऐप्लीकेशंज रजिस्ट्रार के सामने पेश न होने के कारण रिजैक्ट की गई थीं। इस समय तक 2686 उन लोगों की रजिस् ट्रेशन की गई है जोकि डिप्लोमा होल्डर्ज हैं और डिग्री होल्डर्ज हैं। अब कुल मिला कर 13676 आयुवैंदिक के रजिस्टर हैं और 1496 यूनानी सिस्टम में रजिस्टर हैं। स्पीकर साहब, इसके बाद सरकार ने निर्णय किया कि आइंदा उन्हीं लोगों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी जो डिप्लोमा होल्डर्ज और डिग्री होल्डर्ज हैं। ऐक्सपीरियंस के आधार पर रजिस्ट्रेशन नहीं की जाएगी।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि पिछले सालों में हरियाणा में कितने लोगों की रजिस्टेरशन हूई?

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए। वैसे तीन वर्ष में 200 आयुर्वेदिक ग्रेजुऐट डाक्टर्ज ने रजिस्ट्रेशन करवायी है।

श्री सतबीर सिंह कादयानः अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदया यह बतलाने की कृपा करेंगी कि करनाल जिले में आयुर्वेदिक व यूनानी हस्पताल कितने हैं और कहां–कहां हैं?

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, इस वक्त राज्य में 408 आयुवैंदिक व यूनानी डिसपैसंरीज हैं। पहले केवल 224 होती थीं। एक एक के बारे में अभी मेरे पास सूचना नहीं है। ये मेरे चौम्बर में आ जाएं मैं इनको सारी डिटेल बतला दूंगी।

सेठ लछमन दास बजाजः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति हिन्दुस्तान की किसी भी स्टेट से रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो क्या उसे कहीं भी प्रैक्टिस करने की आज्ञा होगी? क्या हरियाणा के अन्दर इसके लिए कोई बैन तो नहीं हे?

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, कोई आदमी कहीं से भी रजिस्ट्रेशन करवा लेता है चाहे वह पंजाब से हो या किसी और राज्य से हो और हरियाणा के अन्दर भी वह प्रैक्टिस कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बजाज साहब आयुर्वेद के प्रति विश्वास और गहरी रुचि रखते हैं लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूं कि 1977 में जब मैं स्वास्थ्य मन्त्री बनी थी तब से मैंने आयुर्वैदिक चिकित्सा के लिए बहुत सुधार करने की कोशिश की थी लेकिन कांग्रेस का राज आने के बाद वे सारी स्कीमें ठप्प हो गई थीं। 1977 में 12

जिलों में हमने जिला आयुर्वैदिक अफसर लगाने की योजना बनायी थी लेकिन कांग्रेस के राज में यह सब कुछ ठप्प हो गया। अब हमने आकर 6 जिलों में अधिकारी लगाए हैं। श्री कृष्ण राजकीय आयुर्वैदिक कालेज, कुरुक्षेत्र के प्रबन्ध तथा कार्य को बेहतर बनाना सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार ने इसका प्रबन्ध तथा नियन्त्रण अपने अधीन ले लिया है। इस कालेज को एक अच्छा कालेज बनाने हेतु इस सरकार ने 35 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की है। पहले वहां शिक्षकों कीं कमी थी, प्रिंसिपल नहीं था लेकिन अब हमने प्रिंसिपल, 4 प्रोफैसर्ज और 9 लैक्चरर्ज की पोस्टें सैक्शन करवाई हैं। इस तरह से जो जो प्रावधान हमने इस कालेज के लिए किए हैं, उन से यह एक बड़ा अच्छा कालेज होगा। इस कालेज में लड़के अच्छी शिक्षा हासिल कर सकेंगे और आगे चल कर अपना काम निपुणता के साथ कर सकेंगे।

श्री बलबीर पात्र शाहः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदया ने अपने जबाव में कहा है कि इस अवधि के दौरान आयुर्वैदिक विभाग का बजट प्रावधान 275.90 लाख रुपए बढ गया है। मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि इस से पहले वर्ष कितना बजट था और अब कितनी इसमें बढ़ौतरी की गयी है?

श्रीमती कमला वर्माः स्पीकर साहब, अभी मैंने बताया था कि पिछले 15 साल के दौरान कितने आयुर्वेदिक/यूनानी औषधालय खोले गए। वर्ष 1973– 74 में हमारा बजट 33 लाख रुपए था और अब हमने 3 करोड़ 9 लाख रुपए कर दिया है।

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब, हाउस में एक डाक्टर श्री रघुबीर सिंह हैं, एक डाक्टर मंगल सैन जी हैं और मन्त्री महोदया भी डाक्टर हैं। मैं मन्त्री महोदया से जानना चाहूंगा कि इनके पास और डा० मंगल सैन कैं पास आयुवैंदिक की डिग्री है या यूनानी की डिग्री है?

श्रीमती कमला वर्माः स्पीकर साहब, मुझे इस बारे में कुछ उत्तर नहीं देना लेकिन माननीय सदस्य से ज्यादा डिग्री मेरे पास है।

श्री टेक चन्दः स्पीकर साहब, अभी थोड़ी देर पहले मन्त्री महोदया ने बताया था कि 408 आयुर्वैदिक व यूनानी डिस्पैसरीज हैं। मैं मन्त्री महोदया से जानना चाहूंगा कि इनमें से कितनी डिस्पैसरीज ऐसी हैं जिनके अन्दर डाक्टर नहीं हैं?

श्रीमती कमला वर्माः स्पीकर साहब, 9 वैद्य रिटायर हो चुके हैं केवल वही जगह खाली हैं बाकी डिस्पैसंरीज में कोई जगह खाली नहीं है।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदया से जानना चाहूंगा कि जो 3 करोड 9 लाख रुपए का बजट बताया गया है, उसका ब्रेकअप क्या है? इसमें से कितना पैसा दवाइयों पर खर्च किया गया है और कितना पैसा सैलरीज पर खर्च किया गया है?

श्रीमती कमला वर्मा: स्पीकर साहब, इस समय मेरे पास दवाईयों पर कुल कितना पैसा खर्च किया गया है, उसकी फिगर्स अलग से नहीं है। लेकिन लगभग 3000 रुपए एक औषधालय में एक वर्ष में औषधि के लिए दिया जाता है। बजट की ब्रेक–अप इस प्रकार है:–

	Opening/continuation of Ayurvedic Dispensaries	Rs. 114.82 lakhs
	Construction of building for Ayurvedic Dispensaries	Rs. 10.00 lakhs
	Improvement of Ayurvedic /Unani Dispensaries	Rs. 15.66 lakhs
	Construction of building of Shri Krishana Govt. Ayurvedic College/Hospital, Kurukshetra	Rs. 35.00 lakhs
	Re-organisation of Ayurvedic Department at Hqrs.	Rs. 9.35 lakhs
	Improvement of Shri Krishna Govt. Ayurvedic College, Kurukshetra	Rs. 14.27 lakhs
	Establishment of District Ayurvedic offices	Rs. 48.62 lakhs
	Development of Private Ayurvedic Colleges	Rs. 15.00 lakhs
	Opening of Homoeopathic Dispensaries	Rs. 18.68 lakhs
	Appointment of 3rd doctor of ISM in PHCs	Rs. 18.60 lakhs
		Rs. 300.00 lakhs

श्री टेक चन्दः स्पीकर साहब, मैं यह जानना चाहता हूं कि हैल्थ डिपार्टमैंट की तरफ से एक मरीज के उपचार पर कितना खर्चा आता हे?

श्रीमती कमला वर्माः स्पीकर साहब, इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्दी महोदया को याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले दिनों इन्होंने कुरुक्षेत्र में एक होस्पिटल का शिलान्यास किया था। उस समय हमारे एक विधायक ने उस सभा में कहा था कि सरकारी हस्पताल की दवाइयां वहां के डाक्टर्ज द्वारा चोर–बाजारी में बेची जाती हैं।

श्रीमती कमला वर्माः हम इस केस की जांच करवा रहे हैं और उस पर ऐक्शन किया है।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः आपने क्या एक्शन लिया है?

श्रीमती कमला वर्माः वहां के सी० एम० ओ० का ट्रांसफर कर दिया है।

श्री हीरा नन्द आर्यः मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि अगर कोई गांव अपने पैसे से हस्पताल या डिस्पैसरी खोलने के लिए भवन बना कर दे दे तो क्या उस भवन को सरकार टेक ओवर करके वहां पर होस्पिटल या डिस्पैसंरी खोलने का विचार रखती है?

श्रीमती कमला वर्माः हमारे मुख्य मन्त्री जी ने यह घोषणा की हुई है कि यदि कोई अपनी बिल्डिग बना कर वहां पर डिस्पैसंरी खुलवाना चाहता है तो उस बिल्डिग को जरूर टेक–ओवर किया जाएगा।

उप मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): स्पीकर साहब, हम न केवल उस बिल्डिग को टेक–औवर करेंगे बल्कि उनको मैचिंग ग्रान्ट भी देते हैं।

श्री नर सिंह ढाण्डाः अभी मन्त्री महोदया ने बताया है कि वहां के सी० एम० ओ० को ट्रांसफर कर दिया गया है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस सी० एम० ओ० पर यह चार्ज लगाया गया था कि वहां पर दवाइयां सरे आम बाजार में बेची जाती हैं, क्या उस सी० एम० ओ० का ट्रांसफर कर दिया जाना ही काफी पनिशमेंट है?

श्रीमती कमला वर्माः हमने उस सी० एम० ओ० का ट्रांसफर इसलिए वहां से किया है ताकि इस केस की अच्छी प्रकार से व ठीक प्रकार से जांच करवाई जा सके। अभी इस केस की डिपार्टमैंटल जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट आने पर संबधित औफिसर्ज व कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

श्री रघु यादवः जिस औफिसर पर यह आरोप लगाया गया कि उसने दवाईयों की चोरी की है, क्या उसको ट्रांसफर ही करना काफी है?

श्रीमती कमला वर्मा: जब हमें सही पता लग पाएगा तभी हम उसके खिलाफ उचित कार्यवाही कर पाएंगे। इस केस में क्लास–1 औफिसर शामिल है इसलिए कई बातें ध्यान में रख कर ही कार्यवाही की जानी है। आरोपों के प्रति किसी ने भी लिखित में कोई रिपोर्ट या पत विभाग को नहीं लिखा, फिर भी जांच करवाई गई।

Shri Raghu Yadav : Transfer is no punishment.

Mr. Speaker : The allegation was vague and was levelled in a public meeting.

श्री परमानन्द: मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं कि हरियाणा की वर्तमान सरकार जब भ्रष्टाचार बन्द के लिए कार्य कर रही है तो इस केस में वैसी कार्यवाही क्यों नहीं की गई? किसी भी विभाग में दोषी पाए जाने वाले अधिकारी या कर्मचारी को पहले सस्पैन्ड किया जाता है और फिर जांच की जाती है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस केस में पहले संबंधित अधिकारी को सस्पैडं क्यों नहीं किया गया?

श्रीमती कमला वर्मा: स्पीकर साहब, वहां पर दवाइयां बेची नहीं गई थीं बल्कि दवाइयों वाली अलमारी को बाहर जाते हुए पकड़ा गया था। ऐसा माननीय सदस्य ने जबानी बताया है। जब तक केस की पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक हम आगे क्या कार्यवाही कर सकते हैं?

श्री नर सिंह ढाण्डा: अभी मन्त्री महोदया ने यह बताया है कि वहां पर दवाइयां बेची नहीं गई बल्कि अलमारी बाहर जाते हुए पकड़ी गई थी। इसलिए मैं मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या वहां के सी० एम० ओ० की यह जिम्मे– दारी नहीं बनती कि वे ऐसी बातों को देखते? क्या इतनी बड़ी घटना के बाद भी वहां के सी० एम० ओ० का ट्रांसफर करना ही काफी है, उसको सस्पैन्ड क्यों नहीं किया गया?

Shri Verender Singh : Without there being a prima facie case, how can one be suspended ? It would have been unjustified.

श्री नर सिंह ढाण्डा: जब सी० एम० ओ० के खिलाफ कोई बात हो गयी तो प्राइमा फेसायी केस बन गया।

Mr. Speaker : No, No, Mr. Dhanda. There is no prima facie case. There was only allegation. There is vast difference between a prima facie case and the allegation.

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि एम० एल० ए० मुझे लिखित में दें। प्राइमा फेसाई केस बनने पर ही ऐक्शन लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष: अब क्वैश्चन आवर खत्म होता है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Jind District Development Board

37. Shri Durga Daft Attri : Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state—

(a) whether any Development Board is proposed to be constituted for the development of historical villages in district Jind ; and

(b) if so, the time by which the above said Board is likely to be constituted ?

विकास मन्त्री (चौधरी हुक्म सिंह):

(क)जी नहीं।

(ख)प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

Haryana Tanneries Limited, Jind

38. Shri Durga Datt Attri : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) yearwise profit and loss account statement of Haryana Tanneries Limited, Jind, since the inception thereof ; and

(b) in case the said Tanneries is running in loss, steps, if any, taken or proposed to be taken for the rehabilitation thereof ?

उद्योग मन्त्री (डा०. किरपा राम पुनिया):

(क)जब से यह कम्पनी स्थापित हुई है, तब से घाटे में चल रही है। निम्न स्टेटमैंट इस कम्पनी का वर्षवार घाटा और एकत्रित घाटा दर्शाती है:—

वर्ष	लाभ (+)हानि(—)	एकत्रित लाभ (+)/हानि (—)
	(रुपए लाखों में)	(रुपए लाखों में)
1976-77	(—)4.97	(—)4.97
1977-78	(—) 34. 68	(—)39.65
1978-79	(—) 44.26	(—)83.91
1979-80	(—)43.93	(—) 127.84
1980-81	(—)34.06	(—)161.90
1981-82	(—)33.69	(—)195.59
1982-83	(—)50.32	(—)245.91
1983-84	(—)67.01	(—)312.92
1984-85	(—)60.23	(—)373.15
1985-86	(—)68.32	(—)441.47
1986-87	(—)75.48	(—)516.95

(ख)इस इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए कई बार प्रयत्न किए गए। वर्ष 1982 में मै० ए० बी० सी० कम्मलटैन्टस

प्राईवेट लि० को विस्तृत अध्ययन करने तथा इस इकाई को पुनर्जीवित करने के तौर तरीके बताने का कार्य सौंपा गया। वर्ष 1984 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैक को इस इकाई के पुनर्वास हेतु वित्तीय सहायता के लिए सम्पर्क किया गया। जो तरीके भिन्न– भिन्न संस्थाओं ने इसके पुनर्वास हेतु बताए, वे वित्तीय संस्थाओं बैकों ने नहीं माने। भारतीय रिजर्व बैक की अध्यक्षता में हुई मिली जुली मीटिंगों में इस इकाई के पुनर्वास की संभावना पर विचार किया गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट मार्च, 1987 में पेश की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस इकाई का जीवित रहना संदेहजनक है।

राज्य योजना बोर्ड ने उप–मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में राज्य की निगमों/ बोर्डों, जिसमें हरियाणा टैनरीज भी शामिल हैं, के कार्यों को रिव्यू करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। इसकी रिपोर्ट अतिशीघ्र आने की संभावना है।

Handicapped Persons

39. Shri Durga Daft Attri : Will the Chief Minister be pleased to state the total number of handicapped persons in the State as on 31-12-1987, togetherwith the details of the measures, if any, taken or proposed to be taken for their welfare ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी देवी लाल): राज्य में 31 – 12 – 87 को विकलांग व्यक्तियों की कुल संख्या संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी जनगणना रिपोर्ट 1981 के आधार पर राज्य में

पूर्णरूप से विकलांग व्यक्तियों की कुल संख्या 15843 है। विकलांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ उठाए गए एवं उठाए जाने वाले उपायों का विवरण परिशिष्ट क व ख पर है।

परिशिष्ट क

विकलांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ वर्तमान उपाय

1. श्रेणी तीन व चार के पदों में तीन. प्रतिशत आरक्षण। रोजगार में सुविधा हेतु इन पदों को हरियाणा अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल के कार्य क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है।

2. विकलांग व्यक्तियों को सरकारी सेवा में रोजगार प्रदान करने हेतु अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की बढ़ौतरी की गई है।

3. विकलांग सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन का दस प्रतिशत अथवा अधिकतम 75 रुपए प्रतिमास यातायात भत्ता।

4. विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर के विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति।

5. शिक्षित विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता।

6. विकलांग व्यक्तियों के लिए पैशन योजना।

7. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को मैडिकल चिकित्सा तथा पुनर्वास संबंधी सुविधाएं साकेत हस्पताल, चण्डी मन्दिर में उपलब्ध।

8. हरियाणा श्रवण वाणी विकलांग कल्याण समिति द्वारा मूक एवं बधिर व्यक्तियों को चिकित्सा की सुविधाएं राज्य के पांच जिलों में उपलब्ध।

9. हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड द्वारा मकानों की अलाटमैंट में विकलांग व्यक्तियों के लिए डेढ़ प्रतिशत आरक्षण।

10. स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा हेतु मुक्त टेप रिकार्ड तथा कैसट्स।

11. नेत्रहीन व्यक्तियों को राज्य में हरियाणा परिवहन बसों द्वारा मुफ्त यात्रा।

12. नेत्रहीन व्यक्तियों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु पानीपत तथा सोनीपत में राजकीय संस्थान।

13. राज्य के रोजगार कार्यालयों में दर्ज नेत्रहीन व्यक्तियों को रोजगार की सुविधा प्रदान करने हेतु 1987–88 में एक विशेष अभियान।

14. स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा नेत्रहीनों के कल्याणार्थ चलाई जा रही संस्थाओं को वित्तीय सहायता तथा नेत चिकित्सा हेतु शिविरों का आयोजन।

परिशिष्ट ख

विकलांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ उठाये जाने वाले प्रस्तावित उपाय

1. विकलांग व्यक्तियों के लिए विवाह अनुदान जहां एक सामान्य व्यक्ति एक विकलांग व्यक्ति से शादी करता है।

2. विकलांग व्यक्तियों को आमदनी बढ़ाने के साधन जुटाने हेतु सरकारी ऋण।

3. केनरज के 100 नए पद रिटेनरशिप आधार पर नेत्रहीन व्यक्तियों को रोजगार देकर भरे जाने प्रस्तावित हैं।

4. सभी वर्गों के विकलांग व्यक्तियों को जिला विकलांग केन्द्र, रोहतक एवं करनाल तथा जिला पुनर्वास केन्द्र, भिवानी में समुचित चिकित्सा एवं पूनर्वास की सुविधा दी जानी प्रस्तावित है।

Welfare of Blind Persons

40. Shri Durga Dutt Attri : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of blind persons in the State, as on 31st December, 1987 ;

(b) the total number of male and female teenager and under 12 years blind persons out of those referred to in part (a) above, separately ; and

(c) whether any scheme for the welfare of blind

persons belonging to the State of Haryana is under consideration of the Govern, ment and ; if so, details thereof ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी देवी लाल):

(क) तथा (ख) : सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग)नेत्रहीन व्यक्तियों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं:–

(1)सामान्य व्यक्ति द्वारा एक नेत्रहीन व्यक्ति या अन्य विंक लांग व्यक्ति से शादी करने के मामले में विकलांग व्यक्ति को शादी अनुदान,

(2)आय बढ़ाने वाली गतिविधियां प्रारम्भ करने के लिए नेत्रहीन व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों को ऋण।

Dilapidated condition of Bridges

41, Shri Kishan Singh Sangwan : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether it is a fact that the following five bridges are in a dilapidated condition on account of which the Haryana Roadways is not plying its buses thereon-

1	High Level Bridge on Bhaulot Sub Branch	Crossing Jasia Rithal Road
2	High Level Bridge on Bhaulot Sub Branch	Crossing Kasanda Saragthal Road

3	High Level Bridge on Bhaulot Sub Branch	Crossing Khanpur Moi Road
4	High Level Bridge on Khanpur Distributary	Crossing Gohana Baroda Juliana Road
5	High Level Bridge on Bhiwani Sub Branch	Crossing Gohana Baroda Road ; and

(b) if so, the steps, if any, taken or proposed to be taken to undertake repairs of the above said Bridges ?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क)हां जी।

(ख)मामला विचाराधीन है।

Construction of Roads in District Rohtak

42. Shri Kishan Singh Sangwan : Will the Minister for P.W.D. (Building & Roads) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct any of the following roads in District Rohtak-

	Link Road	Length
1	from village Giwana, Tehsil Gohana to village Kiloi	5 k.m.
2	from village Riwara (Gohana) to Gurukul Bhainswal	2 k.m.

3	from village Dodwa to Bhadi via Raulad	6 k.m.
	Mettalled Roads	
4	from Khanpur (Tehsil Gohana) to village Shamri,	3k.m.
5	from Kaiwal to lath	2 k.m.
6	from village Gamri to village Kailana,	3 k.m.
7	from village Gohna to village Farmana,	4 k.m.
8	from village Rithal to village Jasrana via Giwana,	6 k.m.
9	from village Mahra (Guhana) to Sikanderpur Majra via Rabhra,	3 k.m.
10	from Wajirpura (Gohana) to Baroda Road,	1 k.m.
11	from Kakana to village Sargathal,	3 k.m.
12	from Anyat to Kakana,	1 k.m.
13	from village Bhainswal Kalan to Bidhal,	3 k.m. ; and

(b) if so, details thereof togetherwith the time by which the above said roads are likely to be constructed ?

लोक निर्माण मन्त्री (श्री ओम प्रकाश भारद्वाज): (क)

1. जी हां, मामला विचाराधीन है, यदि इसके लिए धन राशि उपलब्ध हुई।

2. जी हां, मामला विचाराधीन है, यदि इसके लिए धनराशि उपलब्ध हुई।

3. जी नहीं। पक्की सड़क।

4. जी नहीं।

5. जी नहीं।

6. जी नहीं।

7. जी हां। प्रशासकीय अनुमति पहले ही जारी की जा चुकी है।

8. जी नहीं।

9. जी हां। प्रशासकीय अनुमति पहले ही जारी की जा चुकी

10. जी नहीं।

11. जी नहीं।

12. जी नहीं।

13. जी हां। प्रशासकीय अनुमति पहले ही जारी की जा चुकी है।

(ख)स्वीकृत सड्कों का निर्माण धन राशि उपलब्ध होने पर निर्भर करता है। इस समय कोई निश्चित समय अवधि नहीं बताई जा सकती।

Extension/Completion of Minors

43. Shri Kishan Singh Sangwan : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether any of the under-noted minors are proposed to be extended/completed :—

(i) Rithal Minor

(ii) Ghilor Minor (effecting village Ghilor Kalan, Tehsil
Gohana)

(iii) Bajewa Minor (village Shamri, Khanpur Kalan)

(iv) Lath Minor (upto village Katwal)

(v) Chidhana Minor (village Shamri, Khanpur Kalan and Gamri)

(vi) Incomplete work of Bichhpari Minor ; and

(b) if so, details thereof togetherwith the time by which the said minors are likely to be extended/completed ?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क)घिलोड माइनर, बजेवा माइनर तथा लाठ माइनर की बढ़ौतरी तथा का कोई प्रस्ताव नहीं है। रिठाल वित्रिका, चिढ़ाना माइनर

(ख)तथा बिचपडी माइनर की बढ़ौतरी से संबंधित कार्य प्रगति पर है और इसके मार्च, 1989 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

Sanctioning of Jeeps and Cars to various Departments

45. Shri Raghu Yadav : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the number of Jeeps and Cars sanctioned to various departments as on 31-12-1987 alongwith the designations of the officers for whom such vehicles have been sanctioned ?

उप मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): इस प्रश्न के उत्तर में सूचना एकत्रित करने में जितना समय तथा परिश्रम लगेगा उसके मुकाबले में जो लाभ होगा, वह बहुत ही कम होने की संभावना है।

Village Ponds in Mohindergarh District

47. Shri Raghu Yadav : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the names of the villages of sub-divisions Rewari and Narnaul of District Mohindergarh where the village ponds were filled with canal water, separately, during the period from the 17th June, 1987 to 25th August, 1987 ?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): रिवाड़ी उप–मण्डल जिला महेन्द्रगढ़ के 79 गांवों के जोहड़ों को, तथा नारनौल उप–मण्डल जिला महेन्द्रगढ़ के 19 गांवों के जोहड़ों को दिनांक 17– 6–87 से 25–8–87 तक की अवधि में नहर का पानी वितरण किया गया। इन गांवों की सूची संलग्न है।

सूची

रिवाड़ी सब डिवीजन

क्रंम संख्या गांव का नाम

1. लाला
2. नया गांव
3. ढोको
4. मुनढालिया
5. गोकलपुर
6. मुरकावास
7. भगवानपुर
8. कुम्भावास
9. बिरली खुरद

10. बुरोली

11. बालावास जामापुर

12. रसोली

13. गिनढोकर

14. किशनगढ

15. गुलाबपुरा

16. जाडरा

17. बालावास अहीर

18. लखनौर

19. खडगवास

20. चन्दावास

21. भटेरा

22. भोटावास अहीर

23. नंगल

24. फिडेरी

25. बलियर खुरद

28. खलिलपुर

27. मनढाईयां कलां

28. माजरा शियोरज

29. मुरादपुरी

30. महलावास

31. करनावास

32. मुन्दीखेड़ा

33. खिजूरी

34. दवाना

35. कठुवास

36. सालहावास

37. गुरदास माजना

38. बुढला

39. पंचोर

40. देवलावास

41 कमलपुर

42. भवानरी

43. जटुवास

44. ढोढाई

45. गुजरीवास

46. पदानीवास

47. शाहबाजपुर खालसा

48. ढलियावास

49. गसलवास

50. सुठाना

51. सुठानी

52. धनी सुठानी

53. जेटरावास

54. सुलखा

55. भारावास

56. ओलीआको

57. ठोठवालका

58. कसोली

59. मंगलेश्वर

60. गूजर माजरी

61. रूंध

62. कालरावास

63. माहम्मदपुर

64. बेनीपुर

65. पातुहेड़ा

66. जलियावास

67. जलालपुर

68. बावल

69. तिहाड़ा

70. रसियावास

71. ब्रहमपुर

72. नंगली परसपुर

73. दुलहेड़ा

74. दुलहेडा कलां

75. शाखर

76. नंगलतेजू

77. खेड़ी दुला सिंह

78. मोहनपुर

79. जयसिंहपुरा

नारनौल सब डिवीजन

1. नसीबपुर

2. मंडलाना

3. सलारपुर मेहता

4. निवाज नगर

5. हाजीपुर

6. कुतबापुर

7. सेहरापुर

8. खासपुर

9. नूनी आवल

10. बाछौद

11. छपरा सलीमपुर

12. सुराना

13. नीरपुर

14. सेका

15. खानपुर

16. कारोता

17. खातौली अहीर

18. खातौली जाट

19. गेहली

Remittance of loans of Haryana Backward Classes Corporation

57. Shri Raghu Yadav : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the districtwise number of persons belonging to Backward Classes who were given loans by the Haryana Backward Classes Corporation during the last five years in the State togetherwith the amount of loan given to them, separately ; and

(b) the district-wise number of persons, out of

those, as referred to in part (a) above, where loans have been remitted together-with the amount of loans remitted in each case ?

उद्योग मन्त्री (डा० किरपा राम पुनिया):

(क)हरियाणा पिछड़े वर्ग कल्याण निगम द्वारा 1–4–1982 से 3 1–3– 1987 तक दिए गए जिलावार ऋणों के लाभपालों की संख्या तथा इन की राशि का विवरण अनुबन्ध कं पर रखा है। (ख)ऋण माफ करने संबंधी प्रणाली को अभी पूर्ण किया जाना है।

अनुबन्ध क

क्रम संख्या	जिले का नाम	लाभपात्रों की संख्या	1982– 83 से 1986– 87 तक दिए गए कर्जे
1	2	3	4
		(राशि लाखों में)	(राशि लाखों में)
1.	अम्बाला	1679	19.52
2.	भिवानी	2118	24.95

3.	फरीदाबाद	1509	17.47
4.	गुड़गांव	1704	21.16
5.	हिसार	2203	23.95
6.	जीन्द	1934	20.18
7.	करनाल	1732	21.66
8.	कुरुक्षेत्र	1620	21.11
9.	नारनौल	1664	19.41
10.	रोहतक	1636	21.22
11.	सोनीपत	1297	15.07
12.	सिरसा	1670	22.53

Remittance of loans of Haryana Harijan Kalyan Nigam

58. Shri Raghu Yadav : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the district-wise number of persons belonging to Scheduled Castes who were given loans by the Haryana Harijan Kalyan Nigam during the last five years in the State togetherwith the amount of loan given to them, separately ; and

(b) the district-wise number of persons, out of

those referred to in part (a) above, whose loans have been remitted together-with the amount of loan remitted in each case ?

उद्योग मन्त्री (डा० किरपा राम पूनिया):

(क)हरियाणा हरिजन कल्याण निगम द्वारा 1–4– 1983 से 29–2–88 तक दिए गए जिलावार ऋणों के लाभपात्रों की संख्या तथा इन की राशि का विवरण अनुबन्ध क पर रखा है।

(ख)ऋण माफ करने संबंधी प्रणाली को अभी पूर्ण किया जाना है।

अनुबन्ध क

क्रम संख्या	जिले का नाम	लाभपात्रों की संख्या	1– 4– 83 से 29– 2– 88 तक दिए गए कर्जे
1	2	3	4
		(राशि लाखों में)	(राशि लाखों में)
1.	अम्बाला	10017	38.33
2.	भिवानी	10459	56.27

3.	फरीदाबाद	7890	32.50
4.	गुड़गांव	6790	37.66
5.	हिसार	11342	71.75
6.	जीन्द	8276	39.58
7.	करनाल	7959	30.16
8.	कुरुक्षेत्र	8696	31.41
9.	नारनौल	8721	47.65
10.	रोहतक	9490	43.77
11.	सोनीपत	7924	32.26
12.	सिरसा	7581	39.59

Closure /Setting up of Factories

46. Shri Harnam Singh : Will the Minister for Cooperation be pleased to state—

(a) the number of Factories which stood closed as on 1-1-1987 on account of lay off' and 'Lock outs' in the State ;

(b) the number of Factories out of those, as referred to in part (a) above, as have re-started functioning during the period from 1-1-1987 to 1-1-1988 ;

(c) the number of labourers rendered unemployed as a result of the closures of the factories , as referred to in part (a) above, which have not yet re-started functioning ; and

(d) the number of new factories, if any, set up in the State during the year 1987-88 todate and the number of labourers employed therein?

सहकारिता राज्य मन्त्री (डा० रघुवीर सिंह):

(क)शून्य।

(ख)उपरोक्त क पर दिए उत्तर के दृष्टिगत, सूचना शून्य समझी जाए।

(ग)उपरोक्त क पर दिए उत्तर के दृष्टिगत, सूचना शूल्य समझी जाए।

(घ)1– 1– 87 से 9– 3– 88 तक नए स्थापित कारखानों की संख्या (फैक्टरी एक्ट 1948 के अधीन दर्ज)– 213

उनमें लगाए गए श्रमिकों की संख्या– 11,660

Power House at Village Bohara Kalan

48. Shri Shiv Lal : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether any decision has been taken to set up a Power House at Village Bohara Kalan, Tehsil and District Gurgaon ; and

(b) if so, the time by which the construction of the said Power House is likely to be started ?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क)नहीं।

(ख)उपरोक्त (क)के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

Sohana Irrigation Lift Scheme

49. Shri Shiv Lal : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether Sohana Lift Irrigation Scheme was ever sanctioned ;

(b) whether it is a fact that the said scheme has been shelved ; if so, the rea sons thereof ; and

(c) -if the reply to part (b) above be in the affirmative, whether there is any proposal under consideration of the Govt. to revive the said scheme ?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क)नहीं जी।

(ख)तथा (न)प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

Recruitment made in Police Department

50. Shri Shiv Lal : Will the Minister for Home be pleased to state—

(a) the category-wise number of persons recruited in the Police Department from July, 1987 to 29-2-1988 ; and

(b) the number of persons, out of those referred to in-part (a) above, belonging to Scheduled Castes ?

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): वांछित सूचना निम्न प्रकार है:—

(क) पूछी गई अवधि में एक सहायक उप निरीक्षक, 2 क्लर्कस तथा तथा 1019 सिपाही भर्ती किए गए जिनमें से 256 सिपाही अनुसूचित

(ख)जाति के थे।

Embezzlement in Cooperative Banks/Societies

51. Shri Shiv Lal : Will the Minister of State for Cooperation be pleased to state the total uptodate embezzled amount—

(a) at the level of Primary Societies ;

(b) at the level of Central Cooperative Banks ; and

(c) at the level of Apex Societies, separately in the state ?

सहकारिता राज्य मन्त्री (डा० रघुवीर सिंह):

(क)मु० 306.26 लाख रु० (31— 12—87 तक)

(ख)मु० 1.1० लाख रु० (3 1— 1 2— 87 तक)

(न)मु० 51. 72 लाख रु० (3 1– 12–87 तक)

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब कहते के बारे में मेरी काल अटैन्शन मोशन थी। पहले कहतजदा एरिया में सरकार की ओर से फौडर सबसिडी दी जाती थी लेकिन भिवानी जिले में वह अब बन्द कर दी है। क्या आप बताएंगे कि उसका

श्री अध्यक्षः उसके बारे में गवर्नमैंट से कमैंटस मांगे हैं, जो अभी आए

वर्ष 1987– 88 के सप्लीमैटरी ऐस्टिमेट्स (दूसरी किस्त)पेश करना

श्री अध्यक्षः अब उप–मुख्य मप्यी जी वर्ष 1987–88 के सप्लीमेटरी ऐस्टिमेट्स (सैकिण्ड इंस्टालमेंट)प्रेजैन्ट करेंगे।

उप मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1987– 88 के अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त)पेश करता हूं।

ऐस्टीमेटस कमेटी की वर्ष 1987– 88 के सप्लीमैंटरी ऐस्टिमेट्स (दूसरी किस्त)पर रिपोर्ट पेश करना

श्री अध्यक्षः अब श्री हरि सिंह सैनी, चेयरमैन ऐस्टिमेट्स कमेटी, वर्ष 1987– 88 के सप्लीमैट्री ऐस्टिमेटस (सैकिण्ड इंस्टालमैंट)पर कमेटी की रिपोर्ट प्रेजैन्ट

श्री हरि सिंह सैनी (चेयरमैन, ऐस्टिमेटस कमेटी): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1987– 88 के अनुपूरक अनुमानों (द्वितीय किस्त)पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

राज्यपाल के अभि भाषण पर चर्चा

श्री अध्यक्ष: अब गवर्नर ऐडैरस पर डिस्कशन होगी। डा० मंगल सैन जी अपना मोशन मूव करें।

Shri Mangal Sein (Rohtak) : Sir, I beg to move—

'That an Address be presented to the Governor in the following terms :-

"That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 14th March. 1988".'

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, कल श्री हरि आनन्द बरारी, राज्यपाल महोदय यहां पधारे थे। उन्होंने जो यहां अभिभाषण दिया, उसका अनुमोदन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। पार्लियामैंटरी डैमोक्रेटिक सिस्टम के तकाजे के अनुसार बजट सैशन के पहले दिन राज्यपाल महोदय सरकार की नीतियों के बारे में घोषणा करते हैं। उनका अभिभाषण पालिसी स्टेटमैंट होता है। उन्होंने यहां आकर और अपना अभिभाषण देकर बड़ी कृपा की। स्पीकर साहब, राज्यपाल महोदय का भाषण एक ऐसा भाषण होता है जिसमें उन सभी सब्जैक्टस की चर्चा की जाती है जो स्टेट

लिस्ट में होते हैं और कंकरैंट लिस्ट पर भी होते हैं। स्पीकर साहब आप स्वयं अच्छे वकील हैं और आपके परिवार में इस पेशे के काफी लोग लें।

श्री अध्यक्षः मेरे परिवार में नहीं हैं।

श्री मंगल सैनः ठीक है, वे भूतपूर्व स्पीकर श्री तारा सिंह के परिवार में हैं। मैं आप से माफी चाहता हू, कभी कभी मैं स्लिप कर जाता हूं। स्पीकर साहब, बरारी साहब यहां तशरीफ लाये। नौन–हिन्दी प्रदेश के होते हुए भी उन्होंने हिन्दी में भाषण दिया। हमारे मु ख्य मन्त्री जी ने तो कहा था कि आप अपनी सुविधा अनुसार अंग्रेजी में पढ़ लीजिए लेकिन उन्होंने हिन्दी से प्रेम दिखाया। उन्होंने कहा कि मैं हिन्दी में ही पढूंगा। बरारी साहब बड़े सज्जन पुरूष हैं। उनकी नीयत के बारे में कुछ भी कहना गलत है। आपको पता ही होगा कि पिछले दिनों सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट छपी थी। जिस अखबार में छपी थी वह समाचार पत्र मेरे हाथ में है।

श्री अध्यक्षः मंगल सैन जी, आप गवर्नर ऐड्रैस पर ही बोलें। You are to speak on the Governor's Address. The report has not been laid on the Table of the House in the Parliament. It was a news in the newspapers.

Shri Mangal Sein : Sir, it is a statement of the Home Secretary, Government of India, which has been published in the newspaper. (Interruptions).

Mr. Speaker : Order please. Dr. Sahib, please be relevant.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं आपका हुक्म मानूंगा। I am the most obedient member of the House. मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारिया कमीशन की औबजर्वेशन है कि मुख्य मन्त्री की कंसलटेशन से गवर्नर साहब की नियुक्ति होनी चाहिए। बरारी साहब के बारे में या उनकी परसनैलेटी के बारे में मैं सदन में कोई मतभेद नहीं है। मेरे वरदी चीफ मिनिस्टर उनके बारे में बडे ऊंचे विचार रखते हैं लेकिन मेरी शिकायत दिल्ली में बैठे हुए लोगों के बारे में है। वे संघीय ढांचे को तहस नहस करना चाहते हैंय स्पीकर साहब, यह बडी अलारमिंग बात है, बड़ी खतरनाक बात है। गवर्नमैंट औफ इंडिया का जो ट्रैड चला आ रहा है वह बड़ा गलत है।

चौधरी तैयब हुसैनः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। विधान सभा के रुल्ज औफ प्रोसीजर एंड कन्डक्ट औफ बिजनैस के रुल 100 के तहत जो परसन्ज हाई अथौरिटी में हैं उनके बारे में यहां कुछ नही क्हा जा सकता लेकिन ये बार बार गवर्नर साहब को रैफर कर रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं रुल पढ़ दूं। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः आप बैठें।

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री राम बिलास शर्मा): आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, डाक्टर मंगल सैन जी ने

कैटेगौरिकली कहा है कि उनकी परसनैलिटी के बारे में हमारा कोई विरोध नही है। He is saying only about the procedural things. (शोर एवं विघ्न)

Chaudhri Tayyab Hussain : Sir. Rule 100(2) says—

"A member while speaking shall not reflect upon the conduct of persons in high authority

Mr. Speaker : But he is not reflecting upcn the conduct of the persons in high authorty. He is saying about the procedural things.

Shri Mangal Sein : I humbly submit, Sir, that I am within my right to express my views with regard to the procedure, which has been adopted by the Government of India. After all, in a federal structure there is autonomy of the State.अगर हम उसको यहां डिसकस नहीं करेंगे तो क्या चौपाल में करेंगे?

This is a proper forum for me 'to discuss it, Sir. It is an opportunity for me to express my views through you and through this august House.इससे सारे देश में पता चरर जाएगा कि हरियाणा की जनता क्या फील करती है। Therefore, Sir, I am simply performing my duties and I am within my right to say that the procedure adopted by the Government of India is absolutely wrong and highly objectionable. यह आज तक की परम्पराओं के बिल्कुल विपरीत है।

Mr. Speaker : The Governor is not appointed by the

Prime Minister or by any political party. He is appointed by the President of India. Now since he has been appointed by the President of India, it may not be proper to discuss his appointment here.

I may also refer to page 173 of the book "Practice and procedure of Parliameut" by Kaul & Shakdher, which says—

"On the day allotted for the discussion, the House is at liberty to discuss the matters referred to in the Address. The scope of discussion on the Address is very wide and the entire administration is thrown open for discussion. Even matters which are not specifically mentioned in the Address are brought into discussion through amendments to the motion of Thanks. The only limitations are that members cannot refer to matters which are not the direct responsibility of the Government of India and that the name of the President cannot be brought in during the debate since the Government and not the President is responsible for the contents of the Address".

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, आपकी औब्जर्वेशन और इस किताब में जो लिखा है वह बिल्कुल ठीक है लेकिन

Chaudhri Tayyab Hussain : Speaker Sahib Sarkaria Commissione's Report has not been accepted by the Government nor it has been laid on the Table of the House.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, आयोग ने यह भी कहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में संबंधित मुख्य मच्छी की

सलाह ली जानी चाहिए औंर उच्चन्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से की जाए।

Mr. Speaker : Dr. Sahib, I am very sorry to say that the Commission's Report to which you are referring to again and again has not yet been placed on the Table of the House i.e. Parliament Now, you go ahead.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, पेपर में यह होम सैक्रेटरी की तरफ से आया है। ये भाई यूं ही भड़क रहे हैं। हमें अपनी बात कहने का मौका कहां और संसे मिलेगा? खैर स्पीकर साहब गर्वनर साहब यहां तशरीफ लाए और उन्होंने बड़ी कृपा की कि सरकार की नीतियों का वर्णन किया लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि उन्होंने सरकार की उस नीति उस स्टाइल आफ फंकशनिंग जो अपनी किस्म से निराला है, का जिक्र नहीं किया। चौधरी देवी लाल जी ने जन हित को ध्यान में रख कर जनता दरबार लगाने का एलान किया। आप डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टरज पर जाएं और देखें कि डी० सीज लोगों की बात सुनते हैं। जब कांग्रेसियों का राज था तो लोग शहरों में धक्के खाकर लौट जाते थे। अब ये लोग तड़प रहे हैं। उस समय कोई मुट्ठी गरम कर देता था तो काम हो जाता था क्योंकि उस समय ऊपर से लेकर नीचे तक सारे भले आदमी ही इकट्ठे हो रहे थे। आप कहेंगे कि मैं अफसरों को भी बीच में ला रहा हूं। स्पीकर साहब, मन्त्रिपरिषद के फैसलों को ऐग्जीक्युट करना ब्यूरोक्रेसी का काम है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्यपाल महोदय को जो

स्वयं एक सीजन्ड अफसर रहे हैं यह बात नहीं बताई गई। अगर जनता दरबार के बारे में उनको बताया जाता तो वे अपने ऐडैरस में उसका जरूर जिक्र करते। स्पीकर साहब, गवर्नर महोदय ने अपने ऐडैरस में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि सांझे मोर्चे की सरकार सत्ता में आई। इधर ये भाई सिकुड़ कर चार रह गए। लेडी मैम्बर के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इनके नेताओं को यह बात गवारा नहीं हुई कि सांझे मोर्चे की सरकार क्यों बनी? स्पीकर साहब इनको बड़ा कष्ट हुआ कि यह क्या हो गया, हरियाणा की जनता हमारे झांसे में क्यों नही आई। हमारे प्रधान मन्त्री ने पलवल में कहा था कि हम 403 करोड़ रुपया हरियाणा को दे रहे हैं लेकिन अब तक एक नया पैसा भी नहीं भेजा। उन्होंने यह भी कहा था कि एस० वाई० एल० नहर को केन्द्रीय सरकार अपने खर्चे पर बनाएगी लेकिन अभी तक नहीं बनी। हरियाणा के किसानों की करोड़ों रुपए की फसलें बर्बाद हो रही हैं, किसान बेचारा परेशान है और खेत पानी के बिना प्यासे रह जाते हैं। स्पीकर साहब राज्यपाल महोदय ने ठीक फरमाया लेकिन इन मित्रों को वह बात अच्छी नहीं लगी है। दरियापुर नाम का एक गांव है। तहसील फतेहाबाद जिला हिसार से जाती हुई बस के यात्रियों की उग्रवादियों ने हत्या कर दी। 48 लोग मार दिये। अनेकों घायल कर दिये। उसका विरोध प्रतिशोध होना, गुस्से की लहर का दौड़ना स्वाभाविक था। उससे पहले लालडू में ऐसा हो चुका था। स्पीकर सर, सिरसा में, फतेहाबाद में और हिसार में इसके परिणामस्वरूप झगड़े हुए। लोगों का नुक्सान

हुआ। स्पीकर साहब, केन्द्र का एक मन्त्री टी० बी० की टीम लेकर वहां पर भागा आया हमदर्दी दिखाने के लिये। इलाके में घुसने का मकसद और था। मुझे बहुत अफसोस आता है कि हमारे सैटर में ऐसे मन्त्री हैं। पहले तो वह हवा को ठीक करने के लिये मन्दी थे लेकिन अब उनको कृषि मन्त्री बना दिया गया है। खैर यह तो प्रधान मन्त्री जी की मर्जी है कि वह चाहे किसी को खाना खिलाये या अपने हाथ से किसी को जलेबी खिलाये या लड्डू खिलाये लेकिन मेरा सिर आज अखबार पढ़कर शर्म से झुक गया। सवाल कुछ करते हैं और ये मन्त्री जी क्या कहते हैं, यह जरा सुनिये। सवाल नारियल की फसल की डिवैल्पमैंट के लिये जो कमेटी बनी हुई है, उसके मैम्बर्ज के नाम जानने के लिये पूछा गया था लेकिन मन्त्री जी उनका नाम नहीं बता सके। कहने लगे कि नारियल एक बहुत अच्छी चीज है जिसका तेल निकलता है और जिसकी चटनी भी बनती है। इस तरह से उन्होंने नारियल की तारीफ करनी शुरू कर दी।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): यह बैगन की तारीफ भी कर सकते हैं। (व्यवधान व शोर)।

श्री मंगल सैनः आपकी बात ठीक है, इसकी भी वे तारीफ कर सकते हैं।

श्री अध्यक्षः डा० साहब, यह बात गवर्नर ऐडैरस से तालुक नहीं रखती।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं तो आपके हुक्म का ताबेदार हूं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिससे मर्यादा भंग हो या मर्यादा से बाहर बात हो। मैं तो सिर्फ यह कह रहा था कि उस सरचार्जड ऐटमासफीयर को उन्होंने ऐक्सप्लायट करने की कोशिश की। यह कहा कि मेरे हटते ही यहां पर कत्ल हो गये। मैं होता तो नहीं होने देता। वह इन्दिरा गांधी को भी कहते थे कि अगर दिल्ली में एक भी सरदार चला जायेगा तो मैं पंखे पर लटका दूंगा। वे पता नहीं क्या क्या कहते रहे हैं। पिछले चुनाव में वे कहते थे कि अगर चौधरी देवी लाल मुख्य मन्त्री बन गया तो मैं फांसी ले लूंगा।

चौधरी तैयब हुसैनः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। जो आदमी हाउस में नहीं हे, उसको यह कैसे रैफर कर सकते हैं? A person who cannot defend himself in this House, his name cannot be referred to, Sir. A voice : Sir, he has not named anybody.

Mr. Speaker : Tayyab Sahib, he has not mentioned the nam u of the Minister. You please have your seat.

श्री मंगल सैंनः यहां उस जगह पर बैठने वाले एक और सज्जन थे।. श्री राजीव गांधी ने सोचा कि चौधरी भजन लाल तो हरियाणा में सफल नहीं हो पायेंगे इसलिये उनकी जगह पर चौधरी बंसी लाल जी को भेजा। वे कहते थे कि चौधरी देवी लाल को मैं कभी मुख्य मंत्री नहीं बनने दूंगा। लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से उनसे यह कहना चाहूंगा कि बंसी लाल जी, अब आप

कहां बैंठे हो? चौधरी देवी लाल तो दनदनाता हुआ हरियाणा का मुख्य मन्त्री बन बैठा है। स्पीकर साहब, यह तो जपता की रूचि की बात है। जिसको चाहे ताज पहना दे और जिसको चाहे सड़क पर खड़ा कर दे। स्पीकर साहब, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दरियापुर कांड का दुरुपयोग किया गया। केन्द्र के मंत्री महोदय ने कुछ राजनीतिज्ञों ने कुछ डिस्ग्रल्ड लोगों ने जो निराश हो चुके थे, इससे लाभ उठाने की कोशिश की। लेकिन हरियाणा पुलिस की मैं प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता। पुलिस के अफसरों और सिपाहियों ने उन आतंकवादियों को, जो हरियाणा में कत्ले आम करके भागे थे। पंजाब में जाकर पकड़ा है। हालांकि मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि पंजाब की पुलिस ने उनके साथ कोआप्रेट नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, हमारी पुलिस ने हिम्मत करके आज आतंकवादियों को पकड़ कर सलाखों के पीछे खड़ा कर रखा है। पंजाब की पुलिस उनको नहीं पकड़ पाई। मैं चौधरी देवी लाल से कहना चाहता हूं कि हमारे उन बहादुर अधिकारियों को और उन सिपाहियों को ईनाम देना चाहिये। स्पीकर साहब, हमारी पुलिस की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है। हमारी पुलिस ने भड़कती हुई आग को शान्ति दी है। प्रदेश के लिये उनकी बड़ी भारी सर्विस है। हरियाणा पुलिस ने भड़कते हुए माहौल को काबू किया और ला एंड आर्डर को मेनटेन किया है। आज पंजाब में रोज कत्ल हो रहे हैं। तैयब साहब को तो पता ही नहीं है कि आज पंजाब में क्या हो रहा है? सैन्ट्रल गवर्नमैंट, जिसके पास फौज है, जिसके पास करोड़ों रुपया है और सी० आई० डी० है, पंजाब में

अमन कायम नहीं कर पा रही है। आज हमारी सैकड़ों बहनें विधवा हो रही हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं और वे बूढ़े रो रहे हैं जिनकी लाठी का सहारा टूट गया है। आज उन लोगों को पंजाब आकर संतावना देने की राजीव गांधी की हिम्मत नहीं है। राजीव गांधी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह पंजाब जाकर उन दु:खी लोगों को ढांढस दे। स्पीकर साहब, राजीव गांधी में तो यह हिम्मत नहीं है लेकिन अटल बिहारी वाजपाई में हिम्मत है और लाल कृष्ण अडवाणी में हिम्मत है। ये लोग वहां गए और लोगों की हिम्मत बंधाई। स्पीकर साहब, ये लोग अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखें। राज्यपाल महोदय ने ठीक ही कहा है कि पड़ौस में तनावपूर्ण स्थिति के होते हुए भी इस नई सरकार ने अपने वायदों को भुलाया नहीं है। स्पीकर साहब, इस सरकार ने किसान, दस्तकार, पिछड़े जाति के लोग और दूसरे गरीब लोगों के कर्जे माफ किए हैं। इस सांझे मोर्चेकी सरकार ने यह सराहनीय काम किया है। ये हमारे कांग्रेस के भाई तो केवल चूड़ियां फोड़ते फिरते हैं। इनकी तो केन्द्रीय सरकार है। इनके पास सब कुछ है

चौधरी तैयब हुसैन: आप यह बताएं कि आपने क्या–क्या किया है? गल्तबयानी से क्या फायदा है और ढोल पीटने –से क्या फायदा है? आप जो कुछ आपने किया है वह बताएं। (शोर एवं व्यवधान)।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, आप इनको समझाएं कि रूल्ज क्या हैं? (शोर एवं व्यवधान)। जितने साल ये रहे हम इनके

नखरे सहते रहे। स्पीकर साहब, इनके हाथ में सैन्ट्रल गवर्नमैंट है, प्रदेश की सरकारें हैं वहां ये लोग कर्जा माफ करवा सकते हैं। अब तो हालत यह है कि हरियाणा की मिसाल देकर हिन्दुस्तान के लोग यह चाह रहे हैं कि कोई ऐसा प्रधान मंत्री आए जो हमारे कर्ज माफ कर दे। स्पीकर साहब, इतना ही नहीं, हरियाणा ने हिन्दुस्तान के अन्दर 65 साल के हर आदमी को पैन्शन देकर एक मिसाल कायम की है। किसान, व्यापारी और मजदूर जो भी 65 साल का है उसको सौ रूपया महीना पैन्शन मिलेगी न् (विघ्न)बलबीर पाल शाह जी, आप पहले एम० एल० ए० तो नही थे लेकिन आपके घर मीटिंग हुआ करती थीं। उस समय तो आप कुछ नहीं कर पाए लेकिन आज आप अपने आका को कह दें कि वह भी यह पैन्शन दे दे। हमारे नक्शे कदम पर चलते हुए हिन्दुस्तान के बूढ़ों को वह पैन्शन मन्जूर कर दे। यह बहुत अच्छी बात होगी। हम आपकी तारीफ करेंगे। स्पीकर साहब, ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया और जो कुछ इस समय किया जा रहा है वह तो इन्होंने पहले ही किया था। स्पीकर साहब मैं इनको बताना चाहता हूं कि अब तो ये पांच आकर बैठे भी हैं लेकिन अगली दफा इनकी पूरी नसबन्दी कर दी जाएगी। (हंसी)। स्पीकर साहब, मेरा इतना कहना है कि हमारी सरकार ने बुड्ढों की पैन्शन के साथ साथ विकास कार्य की ओर भी बहुत ध्यान दिया है। अग्रोहा जो कि महाराजा उग्रसैन जी की जन्म भूमि थी, जिनका वहां शासन था। उसकी डिवैल्प– मैट के लिये हमारी सरकार ने विकास बोर्ड बनाया है। वह बड़ा ही सराहनीय कदम है। आदरणीय मुख्यमंत्री

महोदय उसके चीफ पैट्रन हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, डिप्टी चेयरमैन हैं। यह सारी लिस्ट मैंने देखी है। लेकिन लिस्ट देखकर मुझे कुछ निराशा भी हुई हे। सारे बंसी लाल के वक्त के डम्मी इसमें भर्ती कर रखे हैं। आप, चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी इसमें और दूसरे लोग भी ले लीजियेगा जो कि इस सरकार के समर्थक रहे हैं। जो आपके साथ जेलों में तपड़ी बिछाकर बैठा करते थे उनमें से भी कुछ ले लीजियेगा। वैसे स्पीकर साहब, सरकार ने जो कदम उठाया है वह सचमुच बड़ा ही सराहनीय है।

अध्यक्ष महोदय, इससे आगे मैं यह कहना चाहता हूं कि कई बार हमें बंगलौर जाने का मौका मिला। उस शहर में पांच पांच इंजीनियरिंग कालेज हैं और उनका मालिक एक आदमी है इंडीविजुअल उनका मालिक है। मैं यहां पर इंडीविजुअलज की बात नहीं कहता। वैसे तो स्टैट गवर्नमैंट की ओर से कुरुक्षेत्र में एक इंजीनियरिंग कालेज चल रहा है। अब सरकार ने दीनबन्धु सर छोटू राम जी के नाम से एक इजी– नियरिंग कालेज सोनीपत में स्थापित किया है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी तैयब हुसैनः वह कालेज हमारी सरकार ने पिछले साल ही शुरु कर दिया था।

श्री मंगल सैनः तैयब हुसैन जी, आपने तो कागजों में वह कालेज शुरु किया होगा हमारी सरकार ने तो वहां लड़कों को पढ़ाना भी आरम्भ कर दिया है। (तालियां)स्पीकर साहब, मेरा

आपके द्वारा अपनी सरकार को यह कहना है कि और इजी–नियरिंग कालेजों की हरियाणा प्रान्त के अन्दर स्थापना की जानी चाहिये क्योंकि आज के जमाने की दौड़ में ग्रेजुएट्स व पोस्ट ग्रेजुएट्स को तो नौकरी मिलती नहीं और अगर नौकरी मिल भी जाये तो वे सफेद पोश काम नहीं करते। इसलिये अगर टैक्नीकल आदमियों की बढ़ौत्तरी हो जाए तो अच्छा है। यह तभी संभव हो सकता है जब हमारे हरियाणा प्रदेश में और इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना हो। आशा है कि राज्य सरकार इस ओर और अधिक ध्यान देगी।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में हमारे पड़ोसी पंजाब राज्य में जो तनाव बना हुआ है उसका जिकर भी किया है। इतना होते हुए भी हमारे हरियाणा प्रान्त के अन्दर पूरा अमन है। हमारे हरियाणा की एक करोड़ 40 लाख जनता है, वह शान्तिप्रिय है और हम हर हालत में शान्ति स्थापित करना चाहते हैं। गवर्नर साहब ने अपने ऐड्रैस में यह बात भी कही है कि राज्य की कानून व्यवस्था की हालत में व्यापक सुधार हुआ है। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर प्यार से रह रहे हैं। इस का सारा श्रेय हमारी ला एण्ड आर्डर की एजेन्सी को ही जाता है। यह हमारे लिये गर्व की बात है।

11. 00 बजे।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं, ये कांग्रेसी भले आदमी क्या क्या कर्म कर रहे हैं उन के बारे में यहां कुछ रोशनी डालूंगा। इस सूखे की स्थिति में भी हरियाणा राज्य के साथ पूरी तरह भारत सरकार की ओर से बेइन्साफी हो रही है। स्पीकर साहब, हमने भारत सरकार से जब कहा कि हमको सूखा राहत के लिये पैसा दो तो केन्द्र सरकार ने नागालैण्ड जोकि हरियाणा से छोटा राज्य है, उसको तो ज्यादा पैसा दे दिया गया। लेकिन हमें कम पैसा दिया। इसके बाद एस० वाई० एल० के बारे में भी मैं स्पीकर साहब कुछ जिकर करना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

स्पीकर साहब, मैं बद अदब से कहना चाहता हूं कि हरियाणा की एक करोड़ चालीस लाख जनता को सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने बार बार झांसा दिया कि एस० वाई० एल० नहर का पानी हरियाणा में आएगा हरियाणा के खेतों में आएगा लेकिन यह हरियाणा की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा था। उस समय के मुख्य मन्त्री ने एस० वाई० एल० नहर का पानी लाने के लिये हरियाणा की टैरीटरी में तो नहर खुदवा दी लेकिन पंजाब की टैरीटरी में वे नहर नहीं खुदवा सके। हरियाणा की . जनता के साथ उस नहर को खुदवा कर पानी लाने के बारे में कई वायदे हो चुके हैं। स्पीकर साहब, आपको भी इस बारे में पता होगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चौधरी भजन लाल, माथुर साहब और सरदार दरबारा सिंह को बुला कर यह कहा था कि दस्तखत करो। इन बेचारों ने अपने अपने दस्तखत कर दिए क्योंकि वायदे हो

चुके थे लेकिन एस० वाई० एल० नहर पंजाब एरिये में आज तक नहीं खुद सकी। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सैन्ट्रल गवर्नमैंट से पूछना चाहता हूं कि सैटर में किसकी सरकार है? क्या वहां पर सांझे मोर्चे की सरकार है या किसी और पोलिटीकल पार्टी की सरकार है? सैटंर में कांग्रेस आई० पार्टी की सरकार है अगर उसकी नीयत साफ हो तो एस० वाई० एल० नहर खुद सकती है लेकिन उस पार्टी की सरकार की नीयत पर बट्टे पड़े हुए है। वह सरकार इस नहर को जल्दी नहीं खुदवाना चाहती और हरियाणा की जनता को प्यासा रखना चाहती है। स्पीकर साहब, हरियाणा की जनता बहुत सयानी है। अगर हरियाणा की जनता के साथ कोई बेइनसाफी की गई तो उसका जवाब वह ईंट की बजाय पत्थर से देगी। स्पीकर साहब, इस बार हम लोग 85 जीत कर आए हैं और कांग्रेसी 5 जीतकर आए हैं लेकिन अगली बार इनमें से एक भी जीत कर नहीं आएगा।

स्पीकर साहब, राज्यपाल महोदय ने कुछ बातें बडी साफ फरमाई हैं। उन्होंने कहा है कि आज से पहले जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड हुआ करता था उसकी रिलीफ केवल चीफ मिनिस्टर को ही मिला करती थी और उनके पर्सनल काम में ही वह पैसा जाता था लेकिन हमारे मुख्य मन्त्री जी को ऐसा काम अच्छा नहीं लगता। हमारे मुख्य मन्त्री जी के रिलीफ फंड में इस बार 3.80 करोड़ रुपए आए हैं यह रिकार्ड है। यह बात हमारे मुख्य मन्त्री जी की इन्टेग्रिटी और सांझे मोर्चे की विश्वसनीयता को साबित करती

है। स्पीकर साहब, मैं यह बात भी कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने केवल खेतों में हल जोतने वाले किसानों का ही ध्यान नहीं किया बल्कि हरियाणा में बसने वाले हर वर्ग का ध्यान किया है। यह बात कहते हुए मुझे बहुत सन्तोष होता है कि परसों सोनीपत जिले में ओले पड़े थे और जिन जिन गांवों में ओले पडे हैं उन गांवों के दौरे पर आज हमारे आदरणीय मुख्य मन्त्री जी खुद गए हैं। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा है कि मैं चूंकि पहले किसान हूं और बाद में मुख्य मन्त्री, इसलिये पहले मुझे उन किसानों का दर्द बांटना है। मैं यह बात भी कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मन्त्री जी जहां किसानों के हमदर्द हैं उसके साथ साथ उन्होंने व्यापारियों का भी बहुत भला किया है। स्पीकर साहब, इन कांग्रेस भाईयों के राज में सेल्ज टैक्स की ऐग्जम्पशन के लिये कई कई फार्म हुआ करते थे। एक व्यापारी की आमदनी महीने में 300 रुपए हुआ करती थी मुनीम ही 500 रुपये जीम जाया करते थे। दफतरों के बारे में तो आप जानते ही हैं कि हालत क्या थी? मैं भाई सम्पत सिंह जी से कहना चाहूंगा कि कल मुझे इनके महकमे का एक आफिसर मिला मैं उसका नाम नहीं लूंगा और वह कहने लगा कि आपके शब्दों में हमारा महकमा वाकई में नटोरियस है। हमारा महकमा शुरू से ही बिगड़ा हुआ है। स्पीकर साहब, एक दिन में तो उस महकमें में बिगाड हुआ नहीं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस कल्चर ने सारे सिस्टम को स्पॉयल किया है। क्या कभी देश के प्रधान मन्त्री पर भी दलाली का इल्जाम लगा था? यह बात– मुझे बड़े शर्म के साथ कहनी पड़ रही है क्योंकि

मेरी भी लिमिट है और उससे आगे मैं नहीं जा सकता इसलिये मैं यह बात यहीं पर समाप्त करता हूं। लेकिन यह बात मैं जरूर कहूंगा कि कांग्रेस कल्चर ने सारे सिस्टम को स्पॉयल किया हुआ है। पहले कई प्रकार के फार्म हुआ करते थे लेकिन अब मन्त्री जी ने एक ऐडवाइजरी कमेटी बना कर उसको सिम्पलीफाई कर दिया है। जब किसी व्यापारी की टैक्स की असैसमैट हुआ करती थी तो उस समय असैसिंग अथौरिटी अपने आप ऐक्स पार्टी फैसला करती थी और व्यापारी को पैसा जमा करवाना पड़ता था लेकिन अब वह बात नहीं रही। अब यह हो गया है कि जो व्यापारी यह कहे कि मैंने खुद टैक्स असैस किया है, मेरा इतना टैक्स बनता है या मैंने इतना टैक्स वसूल किया है और उसे जमा करवा दे तथा बाकी टैक्स के लिये बैक गारंटी दे दे तो उसकी टैक्स रिकवरी सस्पैंड हो जाएगी। स्पीकर साहब, पिछले सत्र में कराधान मन्त्री महोदय मजबूरी में एक प्रस्ताव कम्बलों पर, हलवाइयों पर और ढाबों वालों पर टैक्स लगाने का लाये थे। इस प्रस्ताव के आने के बाद जनता ने कहा कि ऐसा मत कीजिए। हमारी सरकार लोकतन्त्र में चूंकि विश्वास रखती है। इसलिये हम ने जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वह सारा टैक्स वापस ले लिया। चाहे सरकार को कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हू कि शराब के जो ठेके हैं वहां पर अहाते न बनाये जायें क्योंकि उससे हमारे लोगों का काफी नुक्सान होगा। यह ठीक है कि शराब के ठेकों से सरकार को रैवेन्यू आता

है लेकिन उस रेवैन्यू का हम क्या करेंगे जिससे हमारे घर खराब हो जायें?

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को भी काफी रिलीफ दिया है। उनके भत्ते दुगने किये गए हैं। इस सरकार को बनाने में सरकारी कर्मचारियों का बड़ा हाथ रहा है। यहबात मैं सदन में खड़ा हो कर स्वीकार करता हूं.। अगर सरकारी कर्मचारी भाइयों का कुछ गिला–शिकवा रह गया है तो हमारे मन्त्री परिषद के जो सदस्य बैठे हैं वे उन्हें बुला कर समझायें और उनसे राय लेकर उनकी जो मांगे रह गई हैं उनको पूरी करने की कोशिश करें क्योंकि कोई भी सरकार सभी के सहयोग से ही अच्छी प्रकार से चल पाती है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः डा० साहब, उनकी सारी बातों के लिए एक कमेटी बनाई हुई है।

श्री मंगल सैनः इस सरकार ने कालेज टीचर्ज के लिये भी बहुत कुछ किया है। चुनावों के दौरान हमारी सरकार ने लोगों से वायदे किये थे कि बूढ़ों को पैन्शन दी जायेगी, कर्जे माफ किए जायेंगे और बेकार नौजवानों को इन्टरव्यू पर आने जाने के लिये बसों का किराया नही देना पड़ेगा। वे सभी वायदे भी इस सरकार ने पूरे किए है। इसी प्रकार से एक वायदा यह भी किया था कि हम लोकतन्त्र को बहाल करेंगे। हमारी सरकार ने सज्जा में आते ही म्यूनिसिपल कमेटीज के चुनाव करवाये। स्पीकर साहब, मैं

आदरणीय उप मु ख्य मन्त्री महोदय से और चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी से कहना चाहूंगा कि ब्लाक समितियों और जिला परिषदों के चुनाव भी जल्दी से जल्दी कराये जायें ताकि रुरल डैमोक्रेसी फिर से बहाल हो सके और हरियाणा में लोकतन्त्र राज ठीक प्रकार से चल सके। स्पीकर साहब, करनाल में जूते बनाने की एक लिबर्टी नाम की फर्म है। वहां के मजदूर उसके मालिकों से काफी परेशान हैं। इस बारे में मेरी संबंधित मन्त्री जी से प्रार्थना है कि वहां के मजदूरों को बुला कर उनकी वाजिब शिकायतों को दूर करवाये जाने की कोशिश करें। कांग्रेस के राज में मजदूरों के साथ हमेशा ही बेइन्साफी होती रही है। अब मेरी सरकार से प्रार्थना है कि किसी भी मजदूर के साथ बेइन्साफी नहीं होनी चाहिये। यह बात भी मैं कहना चाहूंगा कि कसिलिएशन–री–कंसीलिएशन हमेशा पूंजीपतियों की जेब में रहा है। स्पीकर साहब, कुल मिला कर इस सरकार को अभी 9 महीने होने जा रहे हैं। 9 महीने का शब्द सुन कर आप भी मुसकरा रहे हैं। (हंसी)स्पीकर साहब, इस थोडे से समय में हमारी सरकार ने सूखा होते हुए व सैन्ट्रल सरकार का ठीक रवैया न होते हुए भी किसानों, मजदूरों व व्यापारियों आदि के लिये बड़े सराहनीय काम किए हैं। इसलिये राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण सदन में दिया है, उनके कथन का पूरा समर्थन करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री अध्यक्षः अब श्री रणसिंह मान जी इस मोशन को सैकिंड करेंगे।

श्री रण सिंह मान (बाढड़ा): स्पीकर साहब, महामहिम राज्यपाल महोदय ने सदन में जो अभिभाषण दिया है, उस पर डा० मंगल सैन जी ने आज धन्यवाद का प्रस्ताव रखा शै। मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। स्पीकर साहब इस असैम्बली –का यह पहला बजट अधिवेशन है। इस बजट अधिवेशन पर न केवल हरियाणा की जनता बल्कि पूरे मुल्क की जनता बड़ा गौर फरमा रही है। उसकी वजह यह है कि इस असैम्बली में वे महानुभाव बैठे हुए हैं जिन्होंने हरियाणवी जनता को साथ ले कर एक लम्बे समय तक निश्चित आर्थिक मुद्दों को लेकर सुसंगठित, सुनियंत्रित और अहिंसक आदोलन को चलाया। इन्होंने चौधरी देवी लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा के आत्मगौरव और स्वाभिमान को नयी बुलन्दी तक पहुंचाया है। वे चुने हुए सदस्य इस सदन में बैठे हुए हैं। इस सरकार को नौ महीने तक काम करने का अभी तक समय मिला है। इस सरकार ने अब त्रक जो कुछ किया है और जिस दिशा में किया है वह इस अभिभाषण में दर्ज है। इस 28 पेज के दस्तावेज में पचास प्वायंटस में इस सरकार की उपलब्धियों को समेटा गया है। इसमें कुछ ऐसी बातें रह गयी हैं जो आनी चाहिए थीं लेकिन कोई नीयतन बाहर नहीं रखी गयी क्योंकि इस सरकार की उपलब्धियों की लिस्ट इतनी लम्बी है कि यह दस्तावेज बहुत बड़ा बन जाता। इसमें किसी अधिकारी का दोष नहीं है बल्कि यह दस्तावेज एक बस्ते के रूप में बन जाता। स्पीकर साहब, हरियाणा की समस्त जनता और माननीय सदस्यगण सरकार के फैसलों से वाकिफ हैं। मैं कुछ बिन्दुओं पर सरकार का विशेष

ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। स्पीकर साहब, बुढ़ापा पैन्शन के बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पेज 15 पर प्वायंट नम्बर 26 में कुछ थोड़ी सी रोशनी डाली गई है लेकिन इससे बढ़ कर जो हम सब के लिये विचारणीय विषय है, वह यह है कि हम लोग तकरीबन ग्रामीण क्षेत्रों से आये हैं। आप जानते हैं कि जिस आदमी की उम्र 65– 70 साल की हो गयी हो उसकी वर्तमान सामाजिक स्थिति क्या होती है? उससे आप सभी वाकिफ हैं। आज के हालात में अगर उसकी सौ रुपये पैन्शन हो जाये तो उसको बहुत सहारा हो जाता है। आज वह गरीब आदमी चाहे शहर में बसता है, चाहे गांव में बसता है, उसकी जीवन शैली में, उसकी सोच और व्यवहार में जो गुणात्मक अन्तर आया है, मुझे अफसोस है, उसे न तो मीडिया ने नोट किया और न ही मेरे कांग्रेसी भाईयों ने नोट किया है। राष्ट्रीय स्तर पर आज के राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में भी जहां कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ है, वहां जब कभी देश के हित में सामाजिक सुधार के लिए कोई बिल या योजना पेश की गई तो हमने हमेशा उसका समर्थन किया। बुढ़ापा पैन्शन योजना के बारे में हमने वर्ष 1980–81 में आवाज उठाई थी लेकिन कांग्रेसी भाईयों ने इस योजना को एप्रिशिएट नहीं किया था बल्कि उसका मखौल उड़ाया था। स्पीकर साहब, राजनैतिक महत्व के विषय के अलावा कुछ और भी सरकार की जिम्मेदारियां होती हैं जिनको सभी राजनैतिक पार्टियों को समाज कल्याण की भावना को सामने रखते हुए देखना चाहिए। स्पीकर साहब, मैं आशा करता हूं कि इस समय जो कांग्रेसी भाई सदन में बैठे हैं, वे इस

जिम्मेदारी को समझेंगे और ईमानदारी से सदन की बहस में भाग लेगे और पैन्शन योजना को ऐप्रिशियेट करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है जो कि इस सरकार ने किया हे, वह है सूखा राहत कार्य। सरकार की इच्छा काम करने की थी। तभी सरकार के कदम इस दिशा की ओर बढ़े हैं। स्पीकर साहब, इस साल सारे देश की जनता को भयानक अकाल का सामना करना पड़ा, लेकिन चौधरी देवी लाल की सरकार से लोगों को कोई शिकायत नहीं क्योंकि लोगों को सरकार की लिहाज थी, और सरकार ने अपना कर्त्तव्य समझते हुए व्यापक प्रबन्ध सूखे से निपटने के लिये किए। कांग्रेसी राज में, कहीं कोई ऐसा इन्सटान्स नहीं मिलता जिस को देख कर यह कहा जाये कि सूखे से निपटने के लिये सरकार ने स्वयं ही राहत कार्य किये हों। स्पीकर साहब, मैं स्वयं ऐसे इलाके से सम्बन्ध रखता हूं जहां सूखे की मार बहुत ज्यादा पड़ी। महेन्द्रगढ़ और भिवानी जिलों के अन्दर बड़े सुचारू ढंग से सूखा राहत दी गई बड़े, व्यवस्थित ढंग से पैसे का बंटवारा किया गया। एक भी कौड़ी न कहीं इधर से उधर गई और न किसी की जेब में गई। स्पीकर साहब, मुझे एक ही बात का गहरा अफसोस है कि राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त इलाकों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन कांग्रेसी मिलों ने इस दिशा मैं अपनी जिम्मेदारी का अहसास नहीं किया। मैं उनके नोटिस में लाना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में सूखे की मार कम नहीं थी। केन्द्रीय सरकार ने सूखा राहत स्कीम के तहत

गुजरात को 388 करोड़ रुपया, राजस्थान को 452 करोड़ रुपए की मदद की लेकिन हरियाणा राज्य को केबल 37.2 करोड़ रुपए की ही मदद दी। सबसे कम मदद हरियाणा को दी गई। केन्द्रीय सरकार का यह भेदभावपूर्ण व्यवहार अच्छा नहीं है। इन्होंने हमारे साथ सौतेली मां का व्यवहार किया है। हरियाणा के प्रशासनिक अधिकारियों ने तथा चौधरी देवी लाल ने केन्द्रीय सरकार को सूखा राहत बढ़ाने के लिए कहा था लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। स्पीकर साहब, मैं दावे के साथ कह सकता. हूं कि सूखा राहत कार्यों के लिए राज्यों को जो पैसा केन्द्रीय सरकार ने दिया है, उस का बटवारा भेदभावपूर्ण ढंग से किया गया है। गुजरात और राजस्थान जैसे इलाके को, जहां कांग्रेस का राज है, वहां पर्याप्त धनराशि दी गई, लेकिन हरियाणा के साथ भेदभाव बरता गया। आप मैम्बरों की एक कमेटी बना सकते हैं जो राजस्थान और गुजरात में जा कर देख सकती है कि जितना पैसा केन्द्र सरकार ने उनको सूखा राहत के लिए दिया था उसकी क्या उपयोगिता रही, कितना पैसा सूखा राहत कार्य के लिए खर्च हुआ है और कितना कांग्रेसियों की जेबों में गया। जैसे अभी डाक्टर साहब ने फरमाया कि पहले भी मुख्य मन्त्री सूखा राहत कोष बना हुआ था। पहले भी उस कोष में पैसे आते रहे हैं लेकिन मैं सदन में आकड़े पेश करना चाहता हूं के विभिन्न समयों में अलग–अलग मुख्य मन्त्रियों के सत्तासीन रहते हुए पैसा आया और उसकी अमाउंट क्या–क्या है? चौधरी देवी लाल 21–6–77 सें लेकर 23–6–79 तक मुख्य मन्त्री रहे। उस टाईम 1 करोड़ 61 लाख 944

रुपया सूखा राहत– के लिए कोष में आया। चौधरी भजन लाल का इस प्रदेश के व्यापारियों और महानुभावों पर कितना विश्वास था, इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं। वे सात साल के लगभग इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री रहे। उनके शासन काल में केवल 61 लाख 49 हजार 7–36 रुपए इस काम के लिए जमा हुए। कांग्रेस के टाईम में जो टोटल पैसा आया वह है एक करोड़ तीन लाख रुपया। श्री बंसी लाल जी एक साल सत्ता में रहे और उस टाईम में केवल 3 लाख 46 हजार 22 सौ रुपए आए। इस सरकार के लिए औंर इस प्रदेश की जनता के लिए यह बड़े फख्र की बात है कि यहां के व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने, दानी सज्जनों ने, विभिन्न कर्मचारी संगठनों तथा अन्य लोगों ने नई सरकार में जो विश्वास का परिचय दिया वह एक नई मिसाल है। आज तक मुख्य मन्त्री के सूखा राहत कोष में 3 करोड़ 11 लाख रुपए जमा हुए हैं। स्पीकर साहब, अभी जो रैली हुई वह हरियाणा से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर की गई थी। कांग्रेसी मिल सुन लें कि हमारे मुख्य मन्त्री की एक अपील पर और इतने शौर्ट नोटिस पर 1151 मनी आर्डर कल तक सिविल सचिवालय में उनके पते पर पहुंच चुके हैं। यह एक विश्वास का नमूना है। इस सरकार को भारी जन समर्थन प्राप्त है इसलिए केन्द्रीय सरकार इस पर वित्तीय अंकुश लगाने के बारे में तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। आपने भी अभी अखबारों में पढ़ा होगा कि जंगलात विभाग ने हमारे प्रदेश में जंगलों को बड़ी मेहनत से तैयार किया है। लेकिन जंगलात ओर शराब के जो ठेके हैं उन पर सैट्रल गवर्नमैंट ने एकु कल्पना

करके, प्रिजम्पशन करके, यह कर दिया कि अगर एक ठेका एक लाख रुपए का उठता है तो उसमें ठेकेदार को 60 हजार रुपए का मुनाफा होगा। उस 60 हजार रुपए पर 20 प्रतिशत टैक्स लगाने की तजवीज की गई है। यह पैसा भारत सरकार उन ठेकेदारों से वसूल नही करेगी बल्कि राज्य सरकार से वसूल करेगी। इस तरह से इन–डायरैक्ट रूप से राज्य के अधिकार क्षेत्र पर और उसके साधनों पर निर्दयता के साथ एक के बाद एक चोट कर रहे हैं। राज्यों द्वारा हिन्दुस्तान को एक रखने की महत्वपूर्ण भूमिका को नजर अन्दाज किया जा रहा है और नये संकटों को जन्म दिया जा रहा है। स्पीकर साहब, आपने हाल के बजट प्रोवीजन देखे होंगे। 127 ऐक्सपोर्ट कम्पनियों को 543 करोड रुपए की सीधी रियायत की घोषणा कर दी जबकि हरियाणा सरकार की कर्जा माफी की योजना को अखबारों के माध्यम से और दूसरे तरीकों से वे इस तरह रखते हैं जैसे जनता का इससे कोई वास्ता ही नहीं है।

मैं सदन के नोटिस में स्पीकर साहब, आपके माध्यम से एक बात यह भी लाना चाहता हू कि हरियाणा की वर्तमान सरकार की हरियाणा फाइनैंशीयल कारपोरेशन ने रिकार्ड तोड़ रिकवरी की है। आप हैरान होंगे कि इस बार रिकवरी के बारे में रिकार्ड स्थापित किया गया है। इतनी रिकवरी पिछले किसी भी साल में नहीं हुई थी जितनी इस साल हुई है। हरियाणा सरकार केन्द्रीय सरकार के पैसे की रिकवरी करवाने में कितनो रुचि ले रही है, यह इस बात का प्रमाण है जबकि केन्द्रीय सरकार मौजूदा हरियाणा

सरकार को जिसको जनसमर्थन प्राप्त है, कमजोर करने के लिए एक के बाद एक अंकुश लगाने के लिए कदम उठा रही है। हमारी सरकार के जनहितैशी कदमों को रोकने के लिए रोड खड़े कर रही है। स्पीकर साहब, आपने भी पढ़ा होगा। कृषि राज्य मन्त्री श्री शिवलाल यादव ने कल ही लोक सभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि जो गरीब और मंझोले किसान हैं, उनके कर्जे के ब्याज को समाप्त करने का कोई विचार नहीं है। एक तो वह सरकार है जो गरीब और मंझोले किसानों को रियायतें देने के लिए सब कुछ कर रही है। अपने साधनों का इस्तेमाल कर रही है और इसके लिए और भी नए साधन जुटाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ केन्द्रीय सरकार है जिसके पास घाटे को पूरा करने के लिए नोट छापने का प्रोवीजन है। वह केवल ब्याज का पैसा भी माफ करने से इन्कार कर रही है। यह है अलग–अलग सरकारों का रवैया जिसको मैं समझता हूं तैयब हुसैन जी नोट करेंगे।

अब मैं बिजली के बारे में भी कुछ कहूंगा। आपका भी बिजली से पूरा ताल्लुक है। चाहे हमारी सरकार से कोई विद्वेष भी रखता हो, आज सभी लोग इस बात की प्रशंसा करते हैं कि बिजली की कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए मैं चौधरी वीरेन्द्र जी को ऐप्रीशियेट किए बिना नहीं रहूंगा कि आज भयंकर सूखे से निपटने में ऐसी विरोधी परिस्थितियों में भी उन्होंने आज किसान को जिन्दा रखा है और बिजली सप्लाई को बनाए रखा है। मैं

हैरान हो गया। स्पीकर साहब, जब इस बार हम रैली की तैयारियों के लिए गांवों में गए तो एक चौंका देने वाली बात हो गयी। कांग्रेस के शासन के दौरान बिजली की पैदावार चाहे कितनी ही रही हो, किसानों ने कभी यह बात नहीं कही थी जो इस बार हम लोगों को किसानों ने कही। वे कहने लगे. कि भई, अब बिजली की सप्लाई को इन्चार्ज को कह कर कम करवा दो। हम टूट चुके हैं। ऐसी परिस्थितियों में कोई किसान बिजली सप्लाई के बारे में ऐसा नहीं कह सकता जैसी परिस्थितियां इस बार हुई हैं। संग–रौली का थर्मल पावर स्टेशन जोकि केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में है। उसमें हमारा हिस्सा घटाया गया और. भाखड़ा डैम के जल ग्रहण क्षेत्र में जहां पर पहले के मुकाबले में कम बरसात हुई और बिजली का उत्पादन भी कम हुआ इन सब बातों के बावजूद भी आज बिजली इस सरकार ने किसानों तक पहुंचाई है। जिन लोगों ने सरकार को चुना है, यह उन सब के लिए बड़े ही फख्र की बात है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। स्पीकर साहब, कुछ अन्य उपलब्धियां भी हैं जो इसमें समेटी नहीं जा सकी हैं जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है। बहुत थोड़े अर्से में इस सरकार ने जो काम किया है, वह न केवल प्रशंसनीय है, बल्कि देश के अन्य हिस्से की सरकारों और जनता के लिए भी अनुकरणीय है।

स्पीकर साहब, एक बात इस सरकार ने और की है। पहली दफा इस इस सरकार ने जो सामन्ती प्रथा थी, उसको खत्म किया है। प्रजातन्त्र में लोग अपने वोट का प्रयोग करके एक

निश्चित समय के लिए सरकार को चुनते हैं। स्पीकर साहब, सदन के सम्मानित सदस्य, उनके नेता और हरियाणा की जनता बधाई की पाल है क्योंकि इस सरकार ने ऐ सी सामन्ती प्रथा को ठोकर मार दी। वजीर जब जिला हैडक्वार्टर पर जाते थे तो पहले अफसरों की फौज, उनका काफिला और पुलिस उनकी सलामी के लिए खड़ी रहती थी लेकिन इस सरकार ने पहली दफा उस प्रथा को तिलान्जलि दे दी है यह कोई छोटी बात नहीं है। स्पीकर साहब, इस सरकार ने फैसला लिया है कि उसके अफसरान महीने में एक बार बसों में सफर करें जिससे उनको लोगों की दिक्कतों का आभास हो। स्पीकर साहब, पहले हरियाणा रोडवेज में महिलाओं के लिए रिजर्व सीट्स नहीं थी। इस सरकार ने उनके लिए हरियाणा रोजवेज की बसों में सीटें रिजर्व की हैं। यही नहीं पहले जब डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर पब्लिक ग्रिवैन्सिज कमेटी की मीटिंग होती थी तो तहसील लैवल और सब–डिविजनल लैवल के अफसरों की मोटरों का काफिला उस मीटिंग को अटैन्ड करने के लिए चलता था। सरकार ने इसको नोट किया और यह फैसला किया कि तीन चार अधिकारी मिलकर एक ही मोटर में सफर करेंगे। अलग– अलग मोटर में सफर करके पब्लिक गाड का दुरुपयोग नहीं करेंगे। स्पीकर साहब कांग्रेस के शासन में तहसील लैवल पर जो रजिस्ट्री होती थीं उनमें बड़ा भारी घोटाला होता था। सरकार ने उसको नोट किया और उन घोटालों को खत्म करने के बारे में विचार किया है और कर रही है। मैं सूरज भान जी से कहूंगा कि वे उन पर विचार करें ताकि सरकार की छवि

उभरे और लोगों की जो अपेक्षा है वह पूरी हो। कुछ ऐसी तजवीजें बैठकर सोची जाएं जिससे कि लोगों की लुटाई न हो।

स्पीकर साहब, इस सरकार का जो चुनाव घोषणा पत्र है जोकि एक पवित्र दस्तावेज है और उस घोषणा पत्र में जो वायदे जनता से किए थे उनको एक–एक करके पूरा करने की चेष्टा की जा रही है और उन वायदों के मुताबिक काम किया. जाएगा। यह इस सरकार के लिए काबिले तारीफ बात है। इस सरकार ने म्यूनिसिपल कमेटीज के चुनाव करवाए। स्पीकर साहब, चाहे म्यूनिसिपल कमेटीज हो और चाहे पंचायते हों, जब प्रजातन्त्र में हर स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधि हों, तभी वे ठीक ढंग से काम कर सकेंगी और लोगों की अपेक्षा के मुताबिक तभी काम कर सकेंगी जब उनके पास रिसोर्सिज होंगे। मेरी प्रार्थना है किं ऐसी कमेटी बिठाई जानी चाहिए कि जो उनको फाइनैंस जुटाने में नई तजवीज सरकार के सामने पेश करे। इसकी अहमियत को समझना चाहिए। मैं समझता हूं जब कि मुख्य मन्त्री जी यहां नहीं हैं उप मुख्य मन्त्री जी इस बात पर गौर करेंगे।

उप मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): नगरपालिकाओं के लिए रिसो– र्सिज कमेटी बना दी है।

श्री रण सिंह मानः स्पीकर साहब, अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि हम सब के लिए यह फख्र की बात है कि हरियाणा की वर्तमान सरकार का जनता को ऐसा नेतृत्व मिला है

जिसकी नियत ठीक है और जिसने ठीके नीति निर्धारित की है और जिसमे जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरुप फैसला लेने की हिम्मत और हौंसला है। स्पीकर साहब, मैं आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने मुख्य मन्त्री जी की ऐबसैन्स में दिए हैं उप–मुख्य मन्त्री महोदय उन पर गौर करेंगे। अन्त में, स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और डा० साहब ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव पेश हुआ–

कि गवर्नर साहब को एक ऐडैरस फौलोइंग टर्मज में प्रेजैन्ट किया जाए–

"That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which' he has been pleased to deliver to the House on the 14th March, 1988".'

चौधरी तैयब हुसैन (तावडू): मोहतरिम स्पीकर साहब, जो गवर्नर ऐड्रैस पेश किया गया है उसमें कोई खास बातें नहीं कही गयीं। उसमें केवल वही बातें कही गई हैं जोकि इस मौजूदा सरकार ने बागडोर संभालने के वक्त कहीं थीं। उन्हीं बातों का बार बार ढिंढोरा पीटा जा रहा है। मुझे खुशी तब होती अगर यहां पर सरकार द्वारा यह कहा जाता कि हम ने फलां फलां अचीवमैंटस की हैं। बहरहाल वे बातें हमारे ख्याल से नहीं कही गयीं। केवल फिगर्ज और आकड़ों की जादूगरी की बातें नहीं चलतीं क्योंकि

हरियाणा की जनता अच्छी तरवर से यह समझ चुकी है कि इस सरकार ने इलैक्शन से पहते लोगों के साथ जो वायदे किए थे, वे पूरे नहीं किए हैं.। यह बात आम आदमी की यहां पर कह रहा हूं। इस– लिए में यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो, बातें इस गवर्नर ऐडैरस में कही गयी हैं वही सारी बातें पिछले गवर्नर ऐडैरस में भी कहीं गयीं थीं, केवल उन्हीं को यहां पर दोहराया गया है या फाइनैन्स मिनिस्टर की स्पीच को तकरीबन दोहराया गया है। (शोर एवं व्यवधान)। इसमें चाहे तो टैक्नोलौजी को बढ़ावा देने की बात कही गयी है, चाहे ओवर ब्रिज की बात कही गई है या चार्श फ्रीडम फाईटर्ज की बात कही गई है लगभग सभी पुरानी हैं। यह ठीक है कि फ्रीडम फाईटर्न की पैन्शन में 50 रुपए की बढ़ौतरी कर दी गई है लेकिन जो जो फैसिलिटीज उनकी विधवाओं और पोते पोतियों आदि को दी गई हैं, वे पहले से ही मौजूद थीं। गालबन आपने एक अच्छा ऐड्रेस दोहराने के लिए पिछला पढ लिया। इसी तरह से मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि मुलाजिमों को फोरथ पे कमिशन के अनुसार जो पे देने की बात थी, वह हमारी सरकार ने पहले ही लागू कर दी थी। आज कर्मचारियों और आम जनता के अन्दर बड़ी मायूसी है क्योंकि इस सरकार ने जो जो वायदे किए थे, वे पूरी तरह से पूरे नहीं किए। जनता को धोखा दिया गए है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)डिप्टी स्पीकर साहब, इनकी बातों को हरियाणा. कीं जनता अच्छी तरह से समझ रही है। कुछ भाईयों ने म्यूनिसिपल कमेटीज के इलैक्शंज की बात कही। वह तो हाई कोर्ट का आर्डर था मौर यह इंस्ट्रक्शंज थी कि नई

सरकार के चुनाव के 75 दिन बाद म्यूनिसिपल कमेटीज के भी चुनाव करवा दिए जाएं। अब चाहे आप जीत कर आ गए तो आपने चुनाव करवा दिए यदि कोई और पार्टी आती तो वह भी चुनाव करवा देती।

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री राम विलास शर्मा): डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। चौधरी तैयब हुसैन जी बहुत पुराने सदस्य हैं। इन्होंने फरमा दिया कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में वही बातें है जो पहले के अभिभाषण में थीं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि स्वतन्त्रता सेनानियों की पैशन में जो 50 रुपए की बढ़ौतरी होगी वह इसी सरकार का फैसला है औंर उन्के पोते पोतियों कों जो रिजर्वेशन मिलेगी वह भी इसी सरकार का काम है। जो तथ्यपूर्ण बाते हैं वे इनको माननी चाहिएं।

चौधरी तैयब हुसैनः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं श्री. राम बिलास शर्मा जी को कहना चाहूंगा कि उस समय के गवर्नर ऐडैरस और फाईनैंस मिनिस्टर की स्पीच के समय आप सैशन में मौजूद नहीं थे। आपने उस समय सैशन का बहिष्कार किया हुआ था। यह मेरे पास पिछले साल का गवर्नर ऐड्रैस है, इसके पैरा 37 में जो लिखा है इसको मैं पढ़ देता हूं:–

"My Government has honoured freedomfighters, Ex-INA personnel and their widows belonging to Haryana. Presently, 3,455 freedom fighters including 2,438 Ex-INA personnel are getting financial assistance at the rate of Rs. 200 per month. Besides, medical facilities and assistance to

meet social obligations is given. Reservation has been made in admission to various professional courses for the children and grandchildren of freedom fighters and reservations will be given to them at the time of recruitment of government service also".

तो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इस गवर्नर ऐडैरस में जो बातें कही गई हैं वही बातें पिछले साल के गवर्नर ऐडैरस में कही गई हैं। करीब करीब उन्हीं बातों को दोहराया गया है।

डिप्टी स्पीकर साहब, दरियापुर काण्ड के सिलसिले में जिन मुलजिमों को पकड़ा गया है उसके लिए हमारी पुलिस मुबारिकबाद की मुस्तहक है। जो सही बात है उसको हम सही कहेंगे। इस बारे में जो कार्यवाही की गई वह सनाहनीय है। इस मामले की बाकी बातों को मैं रैफर नहीं करता। एक बात मैं यह भी अर्ज कर दूं कि हमारे माननीय सदस्य मास्टर शिव प्रसाद जी पर जो कातिलाना हमला किया गया उसके मुलजिम अभी तक नहीं पकड़े गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इस समय प्रदेश में सूखे की भयंकर स्थिति है। यहां पर श्री रण सिंह मान जी ने यह बात कही कि सैन्टर ने हरियाणा सरकार को उतनी मदद नहीं दी जितनी उसे मिलनी चाहिए थी। इस बारे में मैं तो यही समझता हूं कि जैसा केस बना कर भेजा होगा उसी हिसाब से आपको ग्रान्ट मिल गई होगी।

श्री वीरेन्द्र सिंहः हमने भारत सरकार को 400 करोड़ रुपए का केस बना कर भेजा था। जबकि हमें सिर्फ 37.50 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं।

चौधरी तैयब हुसैनः यह तो मुझे पता नहीं कि आपने किस हिसाब से केस भेजा था।

श्री बनारसी दास गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथी श्री तैयब हुसैन बड़े जिम्मेदार आदमी हैं। इनका यह कहना कि जैसा केस बना कर भेजा होगा वैसी ही ग्रान्ट मिल गई होगी, ठीक बात नहीं है। केन्द्र सरकार को जो केस हमने भेजा था उस बारे में ये हमारी सहायता करते उल्टे अब नुक्ताचीनी करने में लगे हैं। केन्द्र में इनकी पार्टी की सरकार बैठी है। ये अपना कोई डैपुटेशन लेकर केन्द्र सरकार से मिलते और जो 400 करोड़ रुपए हमने इनकी केन्द्र सरकार से मांगे थे उन्हें दिलवाने की कोशिश करते। हमने केन्द्र सरकार को पूरे तथ्यों सहित सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए 400 करोड़ रुपए का केस बना कर भेजा था। इन 400 करोड़ रुपयों में से हमें सिर्फ साढ़े 37 करोड़ रुपए ही मिले हैं। तैयब साहब ने, इनके नेताओं ने या इनके साथियों ने आज तक केन्द्र सरकार से यह बात नहीं कही कि हरियाणा सरकार को सूखे का सामना करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सहायता दी जाए।

चौधरीं तैयब हुसैनः आदरणीय उप–मुख्य मन्त्री जी ने अभी कहा है कि जो केस हरियाणा सरकार ने बना कर केन्द्र

सरकार को भेजा था, उसमें हमारी तरफ से कोई सहयोग नहीं दिया गया। मैं आप को बताना चाहूंगा कि जो हमसे हो सकता है वह हम करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात की तरफ मैं सरकार का ध्यान और दिलाना चाहूंगा। सूखे की स्थिति का सामना करते हुए सरकार ने जो चारा भेजा. है वह हमारे एरिया में ठीक नहीं गया। उस चारे में आधा रेत था और आधा चारा था। इस बारे में मेरी वर्त मान सरकार से गुजारिश है कि वहां पर जो चारा भेजा गया है उसकी इंक्वायरी करवाएं।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री धीर पाल सिंह): आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने लोगों को चारा खरीदने के लिए सबसिडी दी है। इसके अलावा चारे को जहां से लाया गया है और जहां पर ले जाया गया है उसकी लोडिंग और अन–लोडिंग का पैसा भी सरकार ने दिया है। इनके पास जो चारा गया है उसमें रेत कहां से आ गया यह बात समझ में नहीं आती। ये अभी तक कमिशन खाते रहे थे और हो सकता है कि इसमें भी कहीं से कमिशन खा गए हों। हमारी सरकार ने सभी को ठीक चारा सप्लाई किया है।

चौधरी तैयब हुसैन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल ठीक बात कह रहा हूं। हमारे यहां पर जो चारा गया है उसे गांव वाले नहीं लाए बल्कि ठेकेदार या और कोई लाए हैं। इस बारे में मेरी यही रिक्वैस्ट है कि जो मैं कह रहा हूं उसकी जांच करवा ली जाए।

राजस्व मन्त्री (श्री सूरजभान): आप लिख कर भिजवा दें, हम जांच करवा लेंगे।

चौधरी तैयब हुसैन: डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे यहां पानी की बड़ी समस्या है। इस बारे में गवर्नर ऐड्रैस में भी कहा गया है। पानी की समस्या हरियाणा में काफी गम्भीर है और खासतौर पर हमारे मेवात इलाके में तो और भी गम्भीर है। वहां नीचे भी अच्छा पानी नहीं है और नहर भी नहीं लगती है। वहां पर वाटर सप्लाई के जरिए ही पीने का पानी सप्लाई किया जा सकता है। इस तरफ पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर साहब को तव्ज्जाह देनी चाहिए। आगे मौसम भी ऐसा आने वाला है जिसके कारण पानी की बड़ी भारी समस्या हो जाएगी। हमारे इलाके में जोहड़ों में भी पानी नहीं होता है। इसलिए सरकार को मेवात के इलाके की ओर खास तवज्जाह देने की आवश्यक्ता है। अभी पिछले दिनों पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर साहब दौरा भी करके आए हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वे इस तरफ ध्यान देंगे।

जहां तक चीफ मिनिस्टर रिलीफ फण्ड की बात है, बड़ी अच्छी बात है कि अकाल की स्थिति में लोगों की मदद होनी चाहिए लेकिन चीफ. मिनिस्टर रिलीफ फण्ड के विषय में तरह तरह की बातें चलती हैं, जिन्हें सरकार को साफ करना चाहिए। जहां जहां से और जिस तरह से भी रुपया आया है उसकी रसीदें मोडे पर नहीं दी गयी हैं, ऐसी शिकायतें लोगों से आयी हैं। इसलिए मैं आपके जरिए निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने रिलीफ फण्ड में

पैसा दिया है उनकी लिस्टें पब्लिश की जाएं कि किन किन लोगों ने कितना कितना पैसा दिया है ताकि देने वाले का लोगों को पता चल सके।

श्री वीरेन्द्र सिंहः हमने बिना रसीद के कोई पैसा नहीं लिया है।

श्री बनारसी दास गुप्ताः आप ऐसे आदमियों की लिस्ट दे दें जिन्होंने चन्दा दिया है लेकिन उन्हें रसीद न दी गई हो।

चौधरी तैयब हुसैनः डिप्टी स्पीकर साहब काफी अफसरों ने नीचे के लैवल पर पैसा? इक्ट्ठा किया है। अगर ये लिस्ट छपवा दें तो सही बात का पता चरन जाएगा। (विघ्न)कम्बोज साहब अगर आपने कोई बात कहनी है तो आप खुद कहें, श्री अजमत खां द्वारा क्यों कहलवा रहे हो। (विष्य)अगर आप आज के दिन ब्रूट मैजोरिटी में हैं और आप समझते हो कि किसी की आवाजें को आप खामोश कर देंगे तो यह बात नहीं हो सकती। इस तरह की बात करने का यह कोई मौका नहीं है। (विम्ब)हम इस विधान सभा में पांव मैम्बर्ज कांग्रेस के हैं लेकिन आपके पार्लियामैंट में, 542 में से पांच भी नहीं हैं। (विघ्न एवं शोर)

शिक्षा मंत्री (चौधरी खुरशीद अहमद): पार्लियामैंट के इलैक्शन करवा लो। (विध्न)

चौधरी तैयब हुसैनः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी खुरशीद अहमद जी से आपके जरिए रिक्वैस्ट है कि कभी वे तावडू की तरह

फरीदाबाद से भी न भाग जाएं। उनसे आप कमिंटमैंट करवा लें कि ये वहां से नहीं भागेंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंहः इलैक्शन करवा लें। (विघ्न)

चौधरी तैजब हुसैनः हम तो चाहते हैं कि वहां जल्दी इलैक्शन हो जाए लेकिन खुरशीद जी आप अपने को मजबूत रखना और वहां से भागना नहीं।

श्री बनारसी दास गुप्ताः तैयब हुसैन जी ठीक नहीं कह रहै हैं। ये जल्दी से इलैक्शन नहीं करवाना चाहते हैं। कांग्रेस (ई)नहीं चाहती है कि उप–चुनाव जल्दी करवाए जाएं। हमारी सरकार ने तीन बार इलैक्शन कमीशन को लिखा है कि इलैक्शन जल्दी करवाए जाएं।

चौधरी तैयब हुसैनः डिप्टी स्पीकर साहब मेरी यही रिक्वैस्ट है कि जिन लोगों से रिलीफ फण्ड के लिए पैसा लिया है उनकी लिस्ट पब्लिश की जाए ताकि यह पता चल सके कि किन किन लोगों से और किन किन कम्पनियों से कितना कितना पैसा लिया है।

श्री जगन नाथः चौधरी बंसी लाल जी आजकल कहां हैं?

चौधरी तैयब हुसैनः यह तो आपको ज्यादा पता होगा क्यों कि आप खुद भिवानी के हैं। (शोर एवं विघ्न)आप तो यहां ...

..... की तरह से बिहेव कर रहे हैं। आप अपना मैडिकल चौक–अप करवाइए।

श्री सूरज भानः डिप्टी स्पीकर साहब, ... शब्द अन–पार्लियामैंटरी हैं। यह ऐक्सपंज होना चाहिए।

चौधरी तैयब हुसैनः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सूरजभान जी की बात मान लेता हूं कि यह अन–पार्लियामैंटरी है लेकिन आप यह भी देखिए कि ये किस तरह से बिहेव कर रहे हें। मैं हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से कहूंगा कि इनका मैडिकल चौक–अप करवाएं।

श्री उपाध्यक्षः पागल शब्द ऐक्सपंज कर दिया जाए।

चौधरी तैयब हुसैनः डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी देवी लाल ने भ्रष्टाचार बन्द करने का अच्छा प्रोग्राम बनाया है। हम भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार बन्द होना चाहिए लेकिन पिछले दिनों मैम्बर सैक्रेटरी ऐन्टी करप्शन बोर्ड ने किन कारणों से इस्तीफा दिया उसके बारे में पता लगना चाहिए। अगर उस बात का पता न चले तो भ्रष्टाचार बन्द करो वाली बात कुछ धुंधली पड़ जाती है। इसलिए मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त है कि उन सब्र बातों के बारे में यहां हाउस में खोल कर बताएं कि उन्होंने किन कारणों से इस्तीफा दिया था। इससे ऐसा लगता है कि किसी आदमी को शील्ड करने के लिए ऐसा हुआ हे। मैम्बर सैक्रेटरी की ईमानदारी के बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। इसलिए मेरी

प्रार्थना है कि चीफ मिनिस्टर साहब इस बारे में अवश्य रोशनी डालें।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं ओल्ड ऐज पैंशन के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। मेरी याददाश्त जरा कमजोर है... (व्यवधान)मैंने पिछले सैशन में भी कहा था कि ओल्ड एज पैशन के लिए उम्र 55 साल रख दी जाए। श्री जगननाथ जो ने भी कहा था कि 65 तक तो कोई हरिजन या गरीब आदमी शायद ही जिन्दा रहे। इसलिए पैशन देने की आयु 65 साल की बजाए 55 साल कर दी जाए। अब जो डैस्टीच्यूट पैंशन देने की बात की गई है, यह तो पहले से ही कांग्रेस सरकार द्वारा दी जा रही थी। जहां तक बुढापा पैंशन का ताल्लुक है, मैंने सुना है कि इस की दूसरी किश्त लोगों तक पहुंची ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों पर गलत पैंशन लेने के मुकदमे भी बने हें। आपने जीन्द जिले के बारे में पढ़ा होगा कि वहां पर कुछ लोगों ने गलत पैंशन ली है। यह बात अखबारों में भी छपी है। इसी प्रकार से काफी लोगों का फिरोजपुर झिरका में भी चालान हुआ है।

श्री राम बिलास शर्माः डिप्टी स्पीकर साहब, श्री तैयब हुसैन जी तो ऐसे फरमा रहे हैं जैसे इनकी सरकार ने सभी कैटेगरीज के लोगों को पैंशन दी हो, लेकिन ऐसा नहीं था। पहले तो ऐसे होता था कि चार हजार ऐप्लीकेशन आती थीं औरे उनमें से मुश्किल से सौ–डेढ़ सौ लोगों को पैंशन देते थे। यह इतिहास में एक मिसाल है जो चौधरी देवी लाल जी के नेतृत्व में कायम

की गई है कि 65 साल की आयु में पहुंचते ही सभी व्यक्तियों या औरतों को पैशन दी जाएगी। यह पैंशन इन के समय में कभी नही दी गई थी। श्री तैयब हुसैन जी अपनी आदत के मुताबिक आलोचना करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन दूसरे मायनों में चौधरी देवी लाल जी के नेतृत्व को यह स्वीकार करते हैं क्योंकि ये चोधरी देवी लाल जी के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ चुके हैं और चुनाव जीते भी हैं।

चौधरी तैयब हुसैनः डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक लोन माफ करने की बात है, यहां इस बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं अगर यह कह दूं कि आज तक एक भी पैसे का लोन माफ नहीं हुआ तो यह कोई गलत बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि लोगों के ऊपर जो गलत मुकदमें बनाए गए हैं उन्हें वापिस लिया जाए। कुछ केसिज में ऐसा भी हुआ है कि जो लोग सही मायनों में 65 साल के थे, वे पैशन वापिस दे आए क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके खिलाफ भी मुकदमें न बन जाएं।

12.00 बजे।

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, अब तक तो हम यही समझते थे कि गलत ब्यानी करने में चौधरी भजन लाल का कोई मुकाबिला नहीं है लेकिन ये आज उनको भी मात कर गए। (हंसी एवं शोर)

चौधरी तैयब हुसैनः डिप्टी स्पीकर साहब, कर्जा माफ करने का मतलब यह है कि बैक का पैसा कोई अदा कर दे क्योंकि बैक ने जो कर्जा दिया है उसकी जब तक अदायगी यहीं हो जाती उसे माफ कैसे कहेंगे? यह मेरी समझ से बाहर है। वीरेन्द्र सिंह जी तथा फाइनैसं मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं वे जरा इस बारे में बता दें। ये बताएं कि इन्होंने किस खाते को आज तक फारिग करवा दिया है। सिवाय इसके कि इन्होंने कुछ तो आर्बिट्रेरी डेट चुन ली और उसके बाद यह कह दिया कि हम यह कर देंगे। उसके बाद केवल पेपर ट्रांजैक्शन हुई है, अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ है। नतीजा यह हो रहा है कि लोगों का कोआप्रेटिव इंस्टीच्यूशंज से एतबार उठने की बात हो रही है। पर्टिकुलर दो डैट्स चुन ली गई एक असल के लिए और दूसरी ब्याज के लिए। पहले तो इन्होंने यह कहा था कि सभी के कर्जे माफ करेंगे। अगर वैसी बात होती तो ठीक था। फिर इन लोगों से भी आपने एक ऐफीडैविट लिखा लिया है कि हमें जब जरुरत महसूस होगी, हम आपसे वसूल कर लेंगे।

श्री बनारसी दास गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि हम इस बारे में जवाब दें। अगर ये चाहते हैं तो मैं इस बात का जवाब अभी दे देता हूं। जो कुछ ये कह रहे हैं, यह सब गलत है। ऐसी बात नहीं है। हमने बाकायदा कर्जे माफ किये हैं। उसके आपको बाकायदा आकड़े दिए जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात का खदशा है कि उस समय आप हाउस में हाजिर होंगे या नहीं।

चौधरी तैयब हुसैनः सांस आए या न आए यह तो कुदरत के हाथ में है।

श्री बनारसी दास गुप्ताः मेरे कहने का यह मतलब नहीं हे। है यह देख रहा हूंरू कि हमारे कांग्रेस के जो मित्र हैं वे गुम रहते हैं। पिछले सैशन में ये बिल्कुल ही नजर नहीं आए।

चौधरी तैयब हुसैनः जनाब पिछले सैशन में मैं विलिंगडन हस्पताल में दाखिल था। मेरा एम्बाई हरनिया का आप्रेशन हुआ था। इसलिए पिछले सैशन में नहीं आ सका था। अगर खुदा ने जिन्दगी दी तो हम आपका जवाब सुनेंगे। आपका जवाब माकूल होगा तो उसे जरुर सुनेंगे। यह नहीं कि जिस तरह से वीरेन्द्र सिंह जी ने कह दिया कि मैंने फलां को मात कर दिया। जो बात जनता महसूस करती है, अगर उस बात को यहां न कहा जाए तो वह भी उचित नहीं होगा। एक बात यहां पर ट्रैक्टर्ज के बारे में कही गई। अभी तक किसी के पास ट्रैक्टज के बारे में चिट्ठी नहीं पहुंची। टैरक्टर्ज के लिए सिर्फ लैड मारगेज बैंकस से ही लोन नही लिया गया बल्कि और बैंक्स से भी लिया गया है लेकिन उनका कोई जिक्र नही है। कर्जा तो तब माफ होगा जब किसानों के खाते में पैसा जमा करवा दिया जाएगा। सरकार अपने रिर्सोसिज से या जिस किसी भी तरीके से पैसा जमा करारा, तब माफ करने की बात हो सकती है।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हू। हुड्डा के डिवैल्पमैंट चार्जिज भी हमारी पहली सरकार ने मुकर्रर किए थे। उनको घटा दिया गया। उसके बारे में भी अखबारों में बहुत चर्चा आयी थी। मैं उस बारे में यह चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री महोदय बताएं कि यह कैसे हुआ? (व्यवधान व शोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः पिछली बार जब आप हाउस में नही थे, तब सारा जवाब दिया जा चुका है।

चौधरी तैयब हुसैनः मुझे तो पता नहीं।

श्री बीरेन्द्र सिंहः आपको जवाब की एक कापी भिजवा देंगे।

चौधरी तैयब हुसैनः एक बात दरख्तों की बाबत भी कही गयी थी। क्या ये बताएंगे कि कहां पर कितने गांवों में कितने दरख्तों की पेमैंट की गयी है? सड्कों के किनारे पर जो दरख्त लगे हुए हैं, उन के बारे में पिछली दफा गवर्नर साहब के ऐड्रैस में जिक्र आया था कि कुछ दरख्तों की किसानों को पेमैंट की जाएगी। मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि वे जरा यह बतलाने की तकलीफ करें कि कितने दरख्तों की पेमैंट कितने गांवों में कितने लोगों को दी गयी है और इससे कितना फायदा किसानों को हुआ है? पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के बारे में मैं भी अर्ज करना चाहूंगा। गुड़गांव में पिछले दिनों काफी गेहूं गया था लेकिन वह तकसीम प्रौपर्ली नहीं हुआ। फूड एण्ड सप्लाईज

मिनिस्टर महोदय से यह कहूंगा कि वह जरा इस बारे में सूचना मंगवा लें और दिखवा लें। वह सरकार की नीति के मुताबिक तकसीम नहीं हुआ है। यह बात वह अवश्य ही दिखवा लें।

मैं एक बात और अर्ज करना चाह रहा हूं। रैली के बारे में भो यहां पर कहा गया। इस सिलसिले में अब की दफा एक नयी चीज हुई है। पहले ट्रक तो इस्तेमाल होते ही थे लेकिन अब की दफा बसों का इस्तेमाल हुआ है। उनका कितना किराया दिया गया, कितनी सवारियां उसमें गयीं, और कितनी टिकटें कटी, इस बारे में वह जरा बताएं क्योंकि वहां पर आधी से भी कम टिकटें कटी हैं? उस दिन जो बसें गांवों में जाती थीं, उनमें ऐडजस्टमैंट हो गयी। एक बात मैं और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा। जो डिलक्स बसें लेट नाईट में चलती हैं, कम से कम उनमें तो रीट्रिडिंग किए हुए टायर न लगाएं। कम से कम उन पर तो नए टायर लगाएं। (व्यवधान व शोर)सवाल यह है कि जो लम्बे रुट्स पर बसें चलती हैं, उन पर रीट्रिडिग किए हुए टायर नहीं होने चाहिएं। मेरा अपना ऐक्सपीरियैंस है। एक दिन मैं रात को चण्डीगढ़ से जयपुर जाने वाली बस में जा रहा था। करनाल के पास जाकर वह बस खराब हो गयी। रात को टायर बदलवाना पड़ा। इस बात को जरा चौक कर लें। (व्यवधान व शोर)डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं ज्यादा न कहते हुए एक ही बात कहना चाहता हू कि जो जनता के हित की बात है, वह करनी चाहिए। ज्यादा ढिंढोरा पीटने की बजाए, उनको अमली जामा पहनाएं। जो

सही बात है, उसको सही मानें। इतना ही कह कर मैं अपनी जगह लेता हूं।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए और अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, तैयब हुसैन जी ने बुढ़ापा पैन्शन के बारे में काफी नुक्ता– चीनी की ओर कहा कि पैन्शन की उम्र 65 से 55 की जानी चाहिए। इन्होंने यह भी कहा कि यह काम तो पिछली सरकार कर गई थी। जिसका जवाब ये नही दे पाए उसके बारे में तैयब हुसैन ने कह दिया कि यह काम तो पिछली सरकार ने किया था। डिप्टी स्पीकर साहब, ये तो यह भी कहने लगेंगे कि लाल किला और ये पहाड़ भी कांग्रेस सरकार ने बनवाए थे। उपाध्यक्ष महोदय, तैयब हुसैन जी कर्जा माफी के बारे में भी बोले। मुझे यह समझ नहीं आया कि ये कर्जा माफी के हक में हैं या कर्जा माफी के खिलाफ हैं। उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव के वक्त तो ये कहते थे कि कर्जा माफ हो ही नहीं सकता और जब चौधरी देवी लाल की सरकार ने कर्जा माफ करने का काम शुरु कर दिया तो ये कहते हैं कि कर्जा ज्यादा माफ होना चाहिए था। इनकी सरकार के समय में जो लोग उस समय की सरकार के बहुत नजदीक थे उन्होंने एक–एक और डेढ़–डेढ़ करोड़ के कर्ज ले लिए थे और इस तरह से चौदह सौ पन्द्रह सौ करोड़ रुपए के कर्जे लोगों ने

ले लिए। ये चाहते हैं कि वे भी माफ हो जाएं। चौधरी देवी लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार तो वे भी माफ करने को तैयार है लेकिन आप दिल्ली की सरकार को कहें कि वह इस तरह का कदम उठाए। मेरा इनसे कहना है कि केन्द्र में जो कांग्रेस सरकार बैठी है उससे पहले इस रोड़े को दूर करवाएं। मेरा ख्याल है कि यह तैयब हुसैन के बस की बात नहीं है कि वह दिल्ली की सरकार से इस रोड़े को दूर करवा सकें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः यह ठीक बात नहीं है। जगन नाथ जी, आपको यह शोभा नहीं देता। आप तो सीनियर मैम्बर हैं। आप बीच में न बोलें।

श्री हीरा नन्द आर्यः उपाध्यक्ष महोदय, तैयब हुसैन ने कहत के बारे में कहा कि केन्द्र को ठीक केस बनाकर नहीं भेजा। है कहना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार ने अपनी तरफ से केस बना लिया होता। डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा के कुछ इलाके ऐसे है जहां पहली दफा कहत नहीं पड़ा। हरियाणा के रैवेन्यू रिकार्ड के मुताबिक पन्द्रहवीं बार वहां कहत पड़ा है। मैं पूछना चाहता हूं कि उस समय कितना बढ़िया केस बनाकर भेजा गया था। उस समय दिल्ली की सरकार ने कितनी मदद की थी? उपाध्यद महोदय, राजस्थान, हरियाणा के बोर्डर पर लगता है और वहां पर भी सूखा है। हमारी तो केन्द्रीय सरकार ने 35– 36 करोड़ की मदद की है और राजस्थान की 488 करोड़ की मदद की हे। मैं तैयब हुसैन को कहना चाहता हू कि वे हरियाणा के

पड़ोस राजस्थान में जाकर देखें। वहां के लोग एक–एक दो–दो क्विटल तूड़ी लेने की कोशिश करते हैं। हमसे लोगों ने शिकायत की कि राजस्थान के लोग दो मन तूड़ी चुराकर ले गए। हमने कहा कि जब हम राजस्थान से बहु बेटियों का लेनदेन करते हैं तो वे एक दो क्विटल तूड़ी ले गए तो कोई बात नही है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मजदूर हरियाणा में मजदूरी के लिए आते हें और हमारे यहां से तूड़ी लेने के लिए आते हैं तो ऐसी हालत में दिल्ली की सरकार राजस्थान को 488 करोड़ रुपया मदद के तौर पर देती है और हरियाणा को केवल 35–36 करोड़ रुपया देती है। उपाध्यक्ष महोदय, यह दिल्ली की कांग्रेस सरकार का सही नक्शा है, इससे उसकी नीयत का पता लगता है। उपाध्यक्ष महोदय, पहले चाहे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और चाहे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, ये शासक और प्रशासक जनता को लूटने की कोशिश करते रहे इसीलिए ये कठिनाइयां पैदा हुई हैं। आज चौधरी देवी लाल और हरियाणा सरकार इसके लिए बधाई की पाल हैं कि जो पिछले सात आठ सालों से हरियाणा के अन्दर कहत पड़ रहा है उसको सुधारने के लिए गरीब लोगों को और गरीब किसानों को काफी राहत दी हे। आज एक चौथाई पशु सरकार की मदद के कारण जीवित हैं। लोगों को इसके लिए सरकार ने सबसिडी दी है, वित्तीय सहायता दी है। पीने के लिए पानी मुहैया किया है। पशुओं के लिए चारे का प्रबन्ध किया गया है और पिछले सात आठ सालों से जिन नहरों और जोहड़ों में पानी नहीं था, वहां पर पानी का प्रबन्ध किया गया है। इस तरह

का काम पहली बार इसी सरकार ने करके दिखाया है जोकि पहले कभी किसी सरकार ने नहीं किया था। पिछली सरकार ने तो हर लिहाज से लोगों को गुमराह किया था। ये कहा करते थे कि फलां जगह सड़क बनाएंगे लेकिन किया कुछ नहीं। यदि केवल रोड़े सड्कों पर गिरा दिए तो कहना शुरु कर देते थे कि सरकार सड्कों की तरफ खास तवज्जोह दे रही है। असलियत में काम कुछ नहीं करवाए गए। इसी तरह से अगर कही पर बिजली पहुंचाने की बात कही तो कहीं तारे बिखेर दीं, कहीं खम्बे रखवा दिए लेकिन काम नाम की कोई बात ही नहीं की जिसका परिणाम आज इस हरियाणा की भोली भाली जनता भुगत रही है। इतना होते हुए भी हमारी इस लोकप्रिय सरकार ने लोगों की, गरीब किसानों की हर लिहाज से मदद की है जिससे लोग सुखी हैं और कुछ राहत महसूस कर रहे हैं। बुढापा पैन्शन, लोगों का कर्जा माफ करना और इस तरह की दूसरी कई सहूलियतें इस सरकार ने मुहैया की हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। इस के बावजूद भी जो ये विरोधी दल के चार मैम्बर बैठे हैं, इस सरकार की नुक्ताचीनी करते हैं बजाए इसके कि इस सरकार की नीतियों की सराहना करते। इनके पास तो सिवाए नुक्ताचीनी के और कुछ है नही।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार यह हरियाणा सरकार इन आर्थिक संकटों से घिरी हुई भी लोगों को मदद दे रही है। किसानों को मदद दे रही है। कर्म चारिये की पूरी तरह से

सहायता कर रही है। लोगों के कर्जे भी माफ किए गए। यह सब आप लोगों के सामने हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? अभी तैयब हुसैन जी बोलते हुए सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे कि इस सरकार ने क्या किया? मेरे विचार से उनको शायद इस गवर्नर ऐड्रैस में कुछ दिखाई नहीं देता। शायद उनकी नजर काम नहीं करती। उन्होंने कहा कि ये सारी बातें हमारी पहली सरकार ने की थीं, इस सरकार ने तो फालो की हैं। मैं उन से पूछता हूं कि पेड़ों की पहली दूसरी लाईनों वाली बात भी क्या इनको सरकार ने ही की थी? जो वृक्ष किसान के खेत के साथ लगता होगा उसका आधा हिस्सा किसान के दिया जाएगा। इस तरह की बातें इनके राज में कहां थीं? उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहूंगा कि सरकार ने और भी बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। जो हमारे साथ लगता हुआ पंजाब प्रदेश है वहां रोजाना अप्रिय घटनाएं हो रही हैं लेकिन हमारा हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां सिवाए एक दो छोटो मोटी घटनाओ को छोड्कर एक भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। लोग आपस में भाई चारे से रह रहे है। अगर यहां हरियाणा के अन्दर पिछली कांग्रेस सरकार होती शायद बहुत बुरा हाल होता लेकिन यह हरियाणा सरकार की तारीफ की बात है। जिन्होंने दरियापुर काण्ड किया था उन लोगों को हमारी पुलिस ने पंजाब में घुस कर पकड़ लिया और जेल की सलाखों में जकड़ दिया। उन लोगों को हमारे पुलिस अधिकारियों ने अपनी जान जोखिम में डाल कर पकडा है लेकिन फिर भी यह कहूंगा कि यह काम करने से ही हमारी पुलिस शुद्ध नही हो जाती। अभी पूलिस में और

सुधार लाने की आवश्यक्ता है। उस सुधार के लिए इस सरकार ने भ्रष्टाचार बन्द का नारा दिया था। उस भ्रष्टाचार को बन्द करने के लिए एक बोर्ड की स्थापना की गई है। वह बोर्ड जो कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है उसको पकड़ता है और उसके खिलाफ कार्यवाही करता है। उस बोर्ड की स्थापना से अच्छे परिणाम निकले हैं। इसी तरह का एक बोर्ड हरियाणा रोडवेज में स्थापित किया गया है। वह बोर्ड जो गलत ऐलीमैंटस हैं, यानी जो कोई गलत आदमी बिना टिकट याग करता है, उसको पकड़ता है और उसके खिलाफ कार्यवाही करता है। उस बोर्ड की स्थापना करने से भी अच्छे परिणाम निकले हैं।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस विभाग के बारे में एक बात और अपनी सरकार से कहना चाहूंगा कि पुलिस का काम ऐसा है कि उसको 24 घंटे तैनात रहना पड़ता है लेकिन अभी तक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए रहने के लिए ठीक प्रकार से मकान नही हैं। केवल उनके रिहायशी मकानों की ही बात नही है बल्कि उनके थानों के भवनों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। थानों की बिल्डिंगें टूटी फूटी पड़ी हैं या वे कि सी धर्मशाला में हैं या गांवों के अन्दर किसी बिल्डिंग में हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि पुलिस के लिए थानों की बिल्डिंगें ठीक ढंग से बनवाई जाऐं और गांवों के बीच में किसी मकान के अन्दर जो थाने हैं उनको गांवों से बाहर किसी साइड पर बिल्डिंग बना कर स्थापित किया जाए। मैं अपनी सरकार से यह भी कहना चाहूंगा

कि थानों की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि पुलिस कर्मचारी जिनकी 24 घंटे की ड्यूटी होती है उसे ठीक ढंग से सरअजाम दे सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात की भी चर्जा करना चाहूंगा। पिछले दिनों हरियाणा की जनता ने न्याय युद्ध के दौरान बहुत अच्छा काम किया है। जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र की जमीन पर महाभारत का युद्ध हुआ था जिसको हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में महाभारत युद्ध के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से हिन्दुस्तान के अन्दर हमारे आदरणीय नेता चौधरी देवी लाल जी के नेतृत्व में हिन्दुस्तान की जनता को एक नया रास्ता दिखाने के लिए न्याय युद्ध लड़ा गया। उस न्याय युद्ध के दौरान हमारे तीन नौजवान शहीद हो गए। वे तीनों नौजवान पुलिस की ज्यादतियों के कारण शहीद हुए और जिन पुलिस वालों ने यह ज्यादती की थी उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। उनके खिलाफ कमिशन बिठाया गया। जो तीन शहीद हुए थे उनके परिवारों को सहायता दी गई। इसी तरह की एक और बात की ओर भी मैं अपनी सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। वह 19 फरवरी 1981 की बात है। बिजली के बारे में किसानों का आन्दोलन चल रहा था। वह आन्दोलन मेरे हल्का लोहारू में चल रहा था। उस दिन पुलिस की गोली से एक महाबीर नाम का नौजवान शहीद हो गया लेकिन उस संबंध में आज तक न उस नौजवान के परिवार को कोई सहायता दी गई है और न ही इस मामले में जो पुलिस के आदमी

या अधिकारी संलिप्त थे उनके खिलाफ कोई कार्य वाही की गई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन पुलिस अधिकारियों या कर्मचारियों ने अपनी गोली से उस नौजवान को शहीद किया था उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए और उसके परिवार को कोई सहायता दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी तैयब हुसैन एक बात कह रहे थे कि कई लोगों के खिलाफ मुकदमें दर्ज किए जा रहे हैं लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमें दर्ज किए जा रहे हैं वे ठीक हैं, कोई गलत बात नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हें जिनके खिलाफ मुकदमें दर्ज किए जाने चाहिएं और उनके खिलाफ कार्य वाही की जानी चाहिए। उस समय की सरकार के टाईम पर हमने प्रधान मन्त्री को एक मैमोरेंडम दिया था लेकिन उसके कोई परिणाम नहीं निकले हैं। उस वक्त के जिन नोबल लोगों ने भ्रष्टाचार के काम किए थे और जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे उनके बारे में हमने प्रधान मन्त्री को मैमोरेडम दिया था लेकिन उसके कोई परिणाम नहीं निकले। उस समय जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे और जो अपनी फैक्ट्रियों की मशीनरी आसाम तक उठा कर ले गए उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। उस समय की सरकार के चाहे चौधरी बंसी लाल या चौधरी भजन लाल मुख्य मन्त्री रहे हों, वे सब भ्रष्टाचार में लिप्त थे। हमने उनके खिलाफ कमिशन बैठाने की बात कही थी। उन्होंने उस बारे में लीपापोती कर ली लेकिन हमारी मांग है कि हरियाणा की जनता ने आपको

सत्ता दी है इसलिए आप उनके खिलाफ कार्य वाही करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय उप मुख्य मन्त्री महोदय से यह आश्वासन चाहूंगा कि जिन लोगों ने गलत काम किए हैं उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज किए जाएं।

गृह मन्त्री (प्रो० सम्पत सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, जिसका ये जिकर कर रहे हैं उसके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः केस तो 1977 में भी दर्ज किए गए थे।

श्री हीरा नन्द आर्यः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि 1977 के बाद 1982 में जो केस विदड्रा हुए थे और जिन लोगों के खिलाफ कमिशन बैठाया गया था उन लोगों के खिलाफ दुबारा फिर से केस दर्ज कराए जाएं ताकि उनको सजा मिल सके। ऐसा होने पर उनको पता चल सकेगा कि किस प्रकार से जनता को लूटा जाता है। उन्हें भी पता चल सकेगा कि सजा क्या चीज होती है? जो दोषी हो उसके खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जाए, चाहे वह मुख्य मन्त्री रहा हो या केन्द्र सरकार में मन्त्री हो। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार की तरफ से व्यान आया था कि लोगों के तकावी कर्जे वगैरा सूखे और कहत के कारण पोस्टपोन कर दिए गए हैं। कर्जे माफी के बारे में मैं सरकार से जानकरी चाहूंगा कि जहां पर कई सालों से कहत पड़ता आ रहा

था और जिस की वजह से वे लोग कर्जे नहीं दे पा रहे थे, और जो अब डिफालटर्ज हें, उन लोगों की कोई विशेष इमदाद की गई हैं। फसल खराबी के कारण उनके तकावी लोन पोस्टपोन तो किए जाते रहे हैं लेकिन माफ नहीं किए गए हैं। ऐसे लोग जो कहत के मारे हुए हैं और डिफाल्टर्ज की परिभाषा में आते हैं। उन के कर्जे माफ होने चाहिएं। आपको भी पता होगा कि पिछले 7–8 सालों से लोहारू और महेन्द्रगढ़ के एरिया में कहत चला आ रहा है जिस की वजह से वहां पर कभी 50 परसैन्ट तो कभी 90 या 95 परसैन्ट तकावी लोन पोस्टपोन होते रहे हैं। वे सरकार ने इसलिए पोस्टपोन किए हैं कि वे लोग कर्जे देने की स्थिति में नहीं हैं। इन लोगों के बारे मे मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि वे सूखे की वजह से अपने बकाया कर्जे नहीं दे पा रहे थे। इसलिए उनको डिफाल्टर्ज के तौर पर न माना जाए और उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनके बकाया कर्जे माफ कर दिए जाएं ताकि उस एरिया के लोगों को भी जो 7–8 सालों से कहत की जद में चले आ रहे हैं कुछ राहत मिल सके। मैं यह भी चाहूंगा कि अगर ऐसा कोई नियम नहीं है तो लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा कर दिया जाये। अभी पिछले दिनों इस संबंध में एक केन्द्रीय मन्त्री का ब्यान भी आया था कि जहां पर लगातार 3 साल तक 50 परसैन्ट या इससे अधिक फसल खराब होती रही है उनके कर्जे पोस्टपोन किए जाने चाहिए। इस बारे में मेरी यह भी प्रार्थना है कि यदि इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से बात करनी हो तो वह भी कर ली जाये। इस के साथ साथ मैं आगे यह भी कहना

चाहूंगा कि जहां पर लगातार 4– 5– 6 सालों से कहत पड़ रहा हो उनके कर्जे पोस्टपोन करने की बजाये माफ कर दिए जाने चाहिए। ऐसा कोई प्रोवीजन सरकार को अवश्य करना चाहिए। यह खुशी की बात है कि अव की बार कुछ बारिश होने की वजह से वहां पर कुछ फसल अच्छी है। लेकिन यह भी सही नहीं है कि एक बार फसल अच्छी होने पर उनसे सारे कर्जे वसूल कर लिए जाएं। एक बार फसल अच्छी होने से ही यदि वे अपनी जमीन या मकान वगैरा नीलाम करा दें तो भी कर्जों का भुगतान नहीं कर सकते। जिस प्रकार से हमारी सरकार ने बूढ़े व्यक्तियों को पैन्शन दी है, चाहे वह रेहड़ी लगाता था या और कोई काम करता था उसी प्रकार से उन लोगों के भी कर्जे माफ किए जाने चाहिएं जिनके यहां पर पिछले कई सालों से कहत चला आ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात मैं मानता हूं कि इस समय हरियाणा सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जब भी आर्थिक स्थिति अगले साल या उससे अगले साल ठीक हो जाए तो उन लोगों के कर्जे माफ कर दिए जाने चाहिएं।

डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी स्टेट में स्प्रिंकलिग सैट्स के सिलसिले में पिछले कई सालों से धांधली मचती रही है उस धांधली के विषय में सरकार से कहना चाहूंगा कि हर साल तीन–चार हजार सैट्स भिवानी और महेन्द्रगढ़ जिले में लाये जाते हैं। पिछले कई सालों में स्प्रिकलिंग सैट्स में करोड़ों रुपये का घपला हुआ है। उन स्प्रिकलिंग सैट्स के बारे में आप यह जानकर

हैरान होंगे कि अगर कोई आदमी किसी किस्म की चीज लोन के द्वारा मार्किट से खरीदता है तो आमतौर पर वह मार्किट रेट से ज्यादा की मिलती है। हरियाणा सरकार ने दो करोड़ रुपये के स्प्रिंकलिंग सैट्स खरीदे थे। सरकार द्वारा खरीदे हुए और कर्जा ले कर किसानों द्वारा खरीदे हुए स्प्रिंकलिंग सैट्स के पाईपस की कीमत में काफी अन्तर है। जब किसान इस 20 फुट के पाईप और कपलर को खरीदता हे तो 92 रुपये 80 पैसे अधिक कीमत देनी पड़ती है। इस हिसाब से 45 परसैन्ट से ज्यादा अन्तर है। यह मैं अपनी सरकार के आने से पहले की बात कर रहा हूं। यह पिछले सालों की बात है। इन्हीं पाईपस के लिए एक और पार्टी ने 15 परसैन्ट कम का रेट दिया था, उस पार्टी को यह कह करु इन्कार कर दिया कि आप लेट आये हो। प्रदेश के खजाने से यह पैसा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि 15 परसैन्ट और 45 परसैन्ट को मिला कर वे 60 परसैन्ट ज्यादा पैसा किसानों से लेते हैं। आप विचार करिए कि किस प्रकार से प्रदेश के किसानों को लूटा गया है। ये पिछली सरकार के कारनामे हैं। है एक बात और सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि जब ये स्प्रिकलिंग सैट्स सप्लाई किये जाते हैं तो उसमें यह शर्त भी होती हें कि किसी किस्म की शिकायत आये या न आये लेकिन उसके बारे में कृषि विभाग ऐट रेंडम सैम्पल ले सकता है, लैबोरेटरी में टैस्ट करवा सकता है और अगर वह ठीक नहीं है तो उसकी कीमत सप्लायर से वसूल कर सकता है लेकिन यह कितनी हैरानी की बात है कि आज तक कहीं भी कृषि विभाग ने कोई सैम्पल नहीं लिया और न ही लैबोरेटरी में

टैस्ट करवाया। कई बार तो ये आई० एस० आई० मार्क भी नहीं होते हें। वे नकली चीजें सप्लाई करते रहे हैं। इस तरह से उन्होने बेतहासा लूट मचाई हुई है। स्प्रिंगलिग सैट्स की कीमत चूंकि हरियाणा सरकार तय करती है इसलिये बेचारा किसान क्या कर सकता है? दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को केन्द्रीय सरकार को ऐप्रोच करना चाहिए कि कर्जा सीधा दिया जाये क्योंकि तीसरी पार्टी वाले मामले में गवर्नमैंट आफ इंडिया की तरफ से दखल आता है। इसलिये केन्द्रीय सरकार को ऐप्रोच किया जाये कि हरियाणा के किसानों और मजदूरों के साथ इस प्रकार की लुटायी न होने दें। इस तरह से तो रेट अधिक और वेट में कम दोहरी किस्म की किसान की लुटाई हुई हे। अगर हम ऐसा कर दें तो डिप्टी स्पीकर साहब, इस देश और प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा फायदा होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस संबंध में हरियाणा सरकार उचित कार्यवाही करके इस सैशन के दौरान ही हरियाणा की जनता को यह बताएगी कि हरियाणा सरकार ने उन काली भेड़ों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है और क्या कार्यवाही करने जा रही है?

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक और दरखास्त आपके माध्यम से सरकार से करना चाहूंगा जो चारे के सिलसिले में है। अब तक हरियाणा सरकार ने कहत के कारण पशुओं के चारे के लिये हरियाणा के लोगों को बहुत राहत दी है लेकिन अब आर्थिक संकट को वजह से सरकार लोगों की मदद कुछ कम कर पा रही

है। मैं यह चाहूंगा कि सरकार किसी तरह से साधन जुटा कर कहत वाले इलाकों के लिये चारे की सबसिडी का और विशेष प्रबन्ध करने को कोशिश करे। उपाध्यक्ष महोदय, गांव के लोगों के लिये साण्ड और झोटे भी बहुत जरूरी हैं। मेरी प्रार्थना है कि उन साण्ड और झोटों को, जो ब्रीड पैदा करते हैं, बचाने के लिये हरियाणा सरकार विशेष रूप से मुफ्त चारे का प्रबन्ध करे, क्योंकि अकाल की वजह से जो लोग अपने पशुओं के लिए ही चारे का प्रबन्ध नहीं कर पा रहे तो वे सामूहिक साण्ड ओर झोटे के चारे का प्रबन्ध कैसे कर पाएंगे?

उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी देश और प्रदेश के लिये यदि योजना ठीक प्रकार से बना ली जाए तो देश और प्रदेश की जनता का विकास अच्छी प्रकार से हो सहता है। किसी भी देश या प्रदेश के लिये मूल आवश्यक चीज है शिक्षा और स्वास्थ्य। लेकिन शिक्षा बहुत ही जरूरी ओर महत्वपूर्ण है। डिप्टी स्पीकर साहब, किसी भी समाज के उत्थान के लिए लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा बहुत जरूरी है। हम एक लड़के को शिक्षा देते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति ही शिक्षित होता हे लेकिन जब हम एक लड़की को शिक्षा देते है तो उससे दो परिवार शिक्षित होते हैं। एक तो वह परिवार जिस में वह पैदा हुई और दूसरा वह परिवार जिस में उसकी शादी होती है। हमारी सरकार ने लड़कियों की शिक्षा के लिये विशेष प्रबन्ध किया है। यह बहुत ही सराहनीय बात है लड़कियों को शिक्षित करने के लिये आने वाले सालों में 200 नये

स्कूल खोले जा रहे हैं, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय कदम हे। आजादी के बाद देश और प्रदेश में शिक्षा की तरफ जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, दुर्भाग्य से वह नहीं दिया जा सका। डिप्टी स्पीकर साहब, 1966 से जब से हरियाणा बना हे पिछले कुछ सालों तक लगातार एक तिहाई अध्यापक अस्थाई तौर पर काम कर रहे थे। वर्ष 1978 तक करीब 35 प्रतिशत अध्यापक अस्थाई तौर पर काम कर रहे थे। जिस को यह तसल्ली ही न हों कि पता नहीं उसकी नौकरी रहेगी या नहीं, वह ठीक ढंग से कैसे काम कर सकताहै? शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामले में इस से बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? वर्ष 1977 में जब चौधरी देवी लाल की सरकार सत्ता में आई तो 15 हजार के करीब अध्यापकों को रैगुलर किया गया था और शिक्षा को ठीक लाईन पर चलाने, का प्रयत्न किया गया था। परन्तु दुर्भाग्य से हालात बदल गए और पहले जो क्रूर शासक थे वे फिर सत्ता में आ गए और जनता को फिर कष्ट भुगतना पड़ा। लेकिन हरियाना की जनता फिर नये सिरे से इस सरकार को सत्ता में लाई। मुझे विश्वास है कि शिक्षा के सम्बन्ध में विशेष रूप से जो कार्य हमारी सरकार कर रही है वह आगे भी करती रहेगी परन्तु इतना ही काफी नही। जब तक गुणात्मक चेन्ज नहीं करते, क्वालिटी में चेन्ज नही करते तब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा। हरियाणा की इस सरकार ने पिछली बार भी और इस बार भी नकल को रोकने के लिये प्रयत्न किए लेकिन यह कोढ़ की बीमारी कई सालों से काफी बढ़ गई है। सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और हर पहलू से समाज के जो अगुआ लोग हैं वे कहते

हैं कि बच्चे नकल करते हें। लेकिन मैं कहता हूं कि इसके लिये बच्चे दोषी नही हैं। इसके लिए अगर दोषो हैं तो समाज के अगुआ लोग है। नकल के बारे में बच्चों से जब पूछा गया कि वे नकल क्यों करते हैं तो उनका जवाब था कि जब राजनैतिक लोग इलैक्शन में बूथ कैपचरिंग करते हैं तो हम भी ऐग्जामिनेशन सैन्टर में नकल कैपचरिंग क्यों न करें? इस का कोई जवाब नहीं। हुस देश और प्रदेश का हर व्यक्ति शिक्षा फै मामले में यदि इस बात का ध्यान रखे कि हम ऐसा वातावरण तैयार करें जिससे हमारी शिक्षा के स्तर को बढावा मिले, तभी सुधार सम्भव है। मुझे पूरा भरोसा कि हरियाणा सरकार शिक्षा में सुधार लाने के लिए पूरी प्रयत्नशील है और वह अवश्य इसमें सफल रहेगी। शिक्षा एक मूल चीज है। कोई इंजीनियर हे, राजनैतिक नेता है या डाक्टर है या कोई भी व्यक्ति है, हम किसी को भी तब तक नहीं सुधार सकते जब तक हमारी शिक्षा में सुधार नही होग।। हमारे समाज की जड़ शिक्षा है। जैसे आप जब तक किसी पेडू की जड़ की सिंचाई नहीं करेंगे और उसमें खाद नहीं डालेंगे तब तक वह पेडू फले फूलेगा नही। इसलिये इस समाज के लिये भी यह जरूरी हे कि हम शिक्षा की तरफ विशेष रूप से ध्यान दें। अगर हम प्राइमरी स्टेज पर ही ठीक तरीके से शिक्षा नही दे पाएंगे तो ऊपर के स्तर पर अच्छे कैलिबर का आदमी कैसे जा पाएगा। इसलिये प्राइमरी विद्यालयों की तरफ सब से ज्यादा महत्व दिया जाए। अधिक से अधिक अध्यापकों का ध्यान बच्चों की तरफ जाना चाहिए। बहुत सी जगह हम देखते हैं कि शहरी स्कूलों में अध्यापक अपनी बदली करवाने

के लिये फर्जी बच्चों को भरती कर लेते हैं ताकि वहां और अध्यापक आ जाए तथा उसकी बदली हो जाए। मैं चौधरी खुरशीद अहमद से चाहूंगा कि वे इस चीज को चौक करवाएं। जब हम पूछते हैं कि नकली भरती क्यों होती है तो कहते हैं कि जिस बच्चे का नाम हमने एक बार लिख लिया उसको आगे की कलास में चढ़ाना हमारी मजबूरी है। बच्चों का ड्रौप आउट न हो इसलिये हम ऐसा करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे टाइम वेस्ट करने से क्या लाभ हैं? हम नये सिरे से ऐसी व्यवस्था कायम करें जिससे स्कूलों में सूधार आए। पुराने वक्त में स्कूलों की ड्न्स्पैक्शन होती थी उसी तरह से अब भी हो और उसके बाद उस इन्स्पैक्शन का फालो–अप ऐक्शन हो, आज खुशी की बात है कि हरियाणा सरकार इस तरफ विशेष रूप से ध्यान दे रही है। इसके अलावा हमारी सरकार किसानों, मजदूरों और हरियाणा की आम जनता की सेवा में भो जुटी हुई है। आज का जो घाटा है इसकी पूर्ति होने के बाद आने वाले वर्षों में सरकार जनता के साथ किए गए वायदों को भी पूरा करेगी। उन वायदों में से बहुत से तो पूरे हो चुके हैं लेकिन जो रहते हैं उनको भी पूरा करेगी। हरियाणा सरकार हिन्दुस्तान में एक आदर्श पेश करेगी ताकि सारे लोग देख सके कि तरक्की कैसे होती है? भ्रष्टाचार ऐलीमिनेट करने के लिये हमारी सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं। हमारे यहां चाहे मुख्य मंत्री का भाई हो या किसी मन्त्री का भाई हो, इस मामले में किसी के साथ रियायत नही बरती जाती। इन शब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री कैलाश चन्द शर्मा (नारनौल): उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने वर्तमान सरकार की नीतियों सम्बन्धी जो अभिभाषण हमारे सामने प्रस्तुत किया है , उसके लिये धन्यवाद करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। वास्तव में हमारे कांग्रेसी मित्र चौधरी तैयब हुसैन जी जब अपनी बात कह रहे थे, तो वे सही बात भूल गये। उन्होंने यह कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि वह गलत अनुभव कर रहे हैं। वास्तव में इस अभिभाषण में यह पहली बार हुआ होगा कि जहाँ पर सरकार की करनी और कथनी में कोई अन्तर नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी रण सिंह मान जी ठीक कह रहे थे कि जब हम रैली की तैयारी के लिये गांवों में गये तो किसान हमसे एक बात पूछते थे कि और सारी बातें तो आपकी ठीक हैं लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आयी कि अब बिजली कहां से आ गयी? पिछले 10 साल से 1977 से लेकर 1987 तक जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों में हर बार हमें आन्दोलन करना पड़ता था। बिजली के दफ्तर का घेराव हम लोग किया करते थे। हमें कांग्रेसी मिल कहा करते थे कि बिजली ऐसी चीज नहीं है जो स्टोर की जार सके। अब यह कहां से आ गयी? हम इस बात से बड़े हैरान हैं। हमारे जमींदार भाई हमसे यह सवाल करते हैं कि अब बताओ यह बिजली कहां से आ गयी है, जबकि इस बार सूखा भी पड़ा हुआ है, बारिश भी नहीं हुई और गोबिन्द सागर में पानी भी बहुत कम है? हमने उनसे कहा कि यह सवाल तुम कांग्रेसी मित्रों से पूछना। हमारे ये कांग्रेसी मिल कम से कम यह बात मानेंगे कि पिछले 10 सालों से

हरियाणा का किसान विशेषकर महेन्द्रगढ और भिवानी का, बिजली के लिये तड़पता रहा है। मैं एक बात के लिये अपने सिंचाई और बिजली मैली को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने महेन्द्रगढ़ जिले के लोगों को शायद यह पहली बार अनुभव कराया है कि वह भी हरियाणा का हिस्सा है, वे भी हरियाणा में रहते हैं वरना नहरी पानी का स्वाद उन्होंने देखा नहीं था। इस बार जिला महेन्द्रगढ़ में लोगों को जो नहरी पानी मिला, उससे लोगों ने कुछ हद तक तो सिचाई की व्यवस्था कर ली। लेकिन इसमें थोड़ी –सी गड़बड़ रह गयी। हमारा यह इलाका राजस्थान के साथ लगता हुआ है। महेन्द्रगढ़ जिले में मेरा क्षेत्र भी राजस्थान के साथ लगता हुआ है। वहां पर पम्प हाउस बने हुए हैं। परन्तु अभी तक उनको बिजली का कुनैक्शन नहीं दिया गया है। इस कारण से उन सारी नहरों का पानी नही दिया जा सका। इसका परिणाम यह हुआ है कि कुछ किसान इस सुविधा से वंचित रह गये। हरियाणा में एक कहावत है कि मेरी पड़ोसन खाये दही तो मुझसे कैसे जाये सही? यह बात यहां के लिये ठीक साबित हुई। वे बेचारे बेसहारा लोग हैं। अगर उनको भी पानी मिल जाये तो उनका भी कुछ फायदा हो जाये। इस जिले ने पहली बार पानी का फायदा महसूस किया है। वे यह सोचते थे कि इससे अच्छा तो यह होता कि हम राजस्थान में होते। परन्तु मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसने जिला महेन्द्रगढ़ के लोगों की दिक्कतों को पहली बार अनुभव किया है और वे यह महसूस करने लगे हैं कि हम हरियाणा

के रहने वाले हैं। हरियाणा सरकार की नजर पहली बार महेन्द्रगढ़ जिले की ओर गयो है।

इसके अलावा, मैं एक और बात अपने जिले के बारे में बताना चाहता हू। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सड्कों की बात है, आज ही प्रातः काल प्रश्नोत्तर काल के समय में भी यह बात कही गयी.। हमारे कांग्रेसी मित्र अखबारों में, रेडियो में इस बात का बड़ा ढिंढोरा पीटा करते थे, कि हमने हर गांव में सड़क पहुंचा दो है। हर गांव को सड़क से जोड़ दिया है। अभी तक कई गांव ऐसे हैं जो जुड़े हुए नहीं हैं। हमारे जिले में मेरा हल्का आखिरी लगता है और इसका नम्बर भी 90 पर आता है। शायद पिछली सरकार ने उसकी तरफ आखें हो नहीं की। आज भी वहाँ पर कई ऐसे गांव हैं जोकि नम्बर के गांव हैं लेकिन वहां पर सड़क कभी पहुंची ही नहीं है। इस तरह से इस जिले की उपेक्षा की गयी है। मैं अपनी सरकार से यह कहूंगा कि वह इस तरफ ध्यान दे। अब जिला महेन्द्रगढ का भी जल्दी ही कल्याण हो जायेगा, ऐसा मैं समझता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण. में अपने प्रदेश में दूध उत्पादन पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का और मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारा दुर्भाग्य रहा है कि जिला महेन्द्रगढ़ मे गल्ती से अगर कोई विकास का काम शुरु हो गया तो उसको बन्द करने की कोशिश की गई। दूध उत्पादन के

सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां के दूध में जो फैट है वह बहुत अच्छी है। वहां पर पहले एक चिलिंग सैन्टर होता था लेकिन पिछले साल उसको बन्द कर दिया था। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में रोजगार के विशेष साधन नहीं हैं। वहां पर कोई फैक्टरी नहीं है। जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। कुछ गरीब लोग एक या दो भैस रखकर और उसका दूध बेचकर गुजारा कर लेते थे। लेकिन जब से यह चिलिंग सैन्टर बन्द हुआ है वे अपना गुजारा करने की स्थिति में नहीं हैं। मेरी मन्त्री महोदय से प्रार्थना है कि जिला महेन्द्रगढ में चिलिंग सैन्टर को दुबारा शुरु करवाने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने सूखा पीड़ितों की सहायता करने का भरसक प्रयत्न किया है। इस सिलसिले में केन्द्रीय सरकार से बारबार बात आई और हमारे साथी कह रहे थे कि हरियाणा को अधिक पैसा दिया जाए तथा पूरा? पैसा दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कांग्रेसी मित्रों से कहूंगा कि अगर उनके मन में हरियाणा की भूमि के लिये जरा भी प्यार है तो कम से कम एक काम वे अवश्य करें। अब यहां पर कांग्रेस के चार विधायक हें, पांचवा विधायक नहीं है। ये चारों विधायक मिल– कर एक संयुक्त बयान जारी करके केन्द्रीय सरकार से मांग करें कि राजस्थान को 488 करोड़ रुपया दिया है और गुजरात को 382 करोड़ रुपया दिया है तो हरियाणा ने क्या गुनाह कर दिया कि उसको मामूली रुपया दिया गया है। अगर एक बार वोट नहीं दिया

तो क्या हुआ पहले तो वोट देते ही रहे हैं और आगे भी वोट लेने हैं। इसलिये हरियाणा की राशि को बढ़ाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार जिला महेन्द्रगढ में कुछ न कुछ सूखा राहत के मामले में काम करवा रही है। कहीं पर हरिजन चौपाल बन रही है, कहीं पर स्कूल की चारदीवारी बन रही है। कहीं पर जोहड़ की खुदाई हो रही है और कहीं पर गलियां पक्की हो रही हैं। कोई ही ऐसा अभागा गांव होगा जहां कुछ न कुछ काम न, हो रहा हो वरना सभी गांवों में कुछ न कुछ काम अवश्य हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान हमारे साथ लगता है। हमारी वहां पर रिश्तेदारी हैं। मेरी वहां पर सुसराल है। वहां पर हमें आना जाना पड़ता है। वहां पर गांव के लोग इकट्ठे हुए और कहने लगे कि आप हमें एक ट्रक तूड़ी भिजवा दो। वहां पर लोग तूड़ी के लिये तरसते हैं जबकि उनको 488 करोड़ रुपया सूखा राहत के लिये दिया गया है। इसके मुकाबले में जिला महेन्द्र गढ़ के प्रत्येक गांव में कुछ न कुछ काम सूखा राहत के नाम पर हो रहा है। मैं अपने कांग्रेसी भाइयों से कहना चाहता हूं कि खुले ह्रदय से उनको एक बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि सूखा राहत के मामले में हरियाणा के साथ भेदभाव बरता जा रहा है।

श्री उपाध्यक्षः शर्मा जो, जो लड़की वाले हैं वे तो कोई चीज मांगते नहीं हैं।

श्री कैलाश चन्द शर्मा: वे मांग नही रहे थे। वे तो आग्रह कर रहे थे कि हमें एक ट्रक तूड़ी भिजवा दो, हम पैसा दे देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक वृद्ध अवस्था पैन्शन का सम्बन्ध है इसके बारे में कांग्रेस के भाई कह रहे थे कि यह काम उन्होंने शुरु किया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं पहले गांव में एक दो आदमी को ही पैन्शन मिलती थी और लोगों को बड़ी भारी शिकायत होती थी। आज स्थिति यह है कि हरियाणा के अन्दर 65 साल का कोई भी आदमी सौ रुपया महीने के हिसाब से पैन्शन ले सकता है। मुझे 9 तारीख की रैली के सिलसिले में गांवों में जाना पड़ा। वहां पर बूडवाल गांव के लोग आए और उन्होंने कहा कि हम 290 रुपए का मनि आर्डर करवाना चाहते हैं आप हमें ऐड्रैस बताएं। वे कह रहे थे कि पहली किस्त मिल चुकी है और दूसरी तीन सौ रुपए की किस्त भी मिल चुकी है। लोग भाग भाग कर पैसा देने के लिये आ रहे थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि इस मामले में थोड़ी गड़बड़ है। पहले बहुत थोड़े मनीआर्डर्ज भेजे जाते थे लेकिन अब हजारों की तादाद में मनी आर्डर्ज भेजे जाते हैं। पोस्ट औफिस में स्टाफ कम होगा, मैंने उनसे इस बारे में बात की। उन्होने यही कहा कि पहले एक दो मनीआर्डर्ज होते थे–और अब एक–एक गांव में डेढ़ सौ या दो सौ मनीआर्डर्ज आते हैं। आप हमारी सहायता करें। उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार इस मामले

में सहायता नहीं कर रही है। जब हम गांवों में जाते हैं तो आमतौर पर यह शिकायत हमारे सामने आती है कि विधवाओं को जो पैन्शन पहले मिलती थी वह पांच छरू महीने से नहीं मिली है। मेरा इस बारे में एक सुझाव है कि सरकार अपनी तरफ से ऐसी व्यवस्था करे कि ओल्ड एज पैन्शन सरकार की किसी ऐजैन्सी के माध्यम से बंटवाए। ऐसा करने से मैं समझता हूं कि लोगों की यह शिकायत दूर हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार का एक सराहनीय कार्य है। अभी आर्य जी बोलते हुए यह कह रहे थे कि वास्तव में कई सालों के बाद विद्यार्थियों ने अनुभव किया है कि परीक्षाओं का क्या अर्थ होता है? पिछले पांच सात सालों के अन्दर इस राज्य का नक्ल के कारण माहौल सा खराब हो गया था। अब इस सरकार ने इसमें काफी सुधार किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में प्राईमरी स्कूलों के बारे में काफी विस्तार से कहा गया है। और भी प्राईमरी स्कूलों की खोलने की व्यवस्था की जा रही है। वर्ष 1988– 89 में लड़कियों के लिये ही और 200 स्कूल खोलने का उपबन्ध किया गया है। यह एक बहुत अच्छा कदम है। इसके साथ साथ मैं शिक्षा मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि शहरों में कई जगहों पर प्राईमरी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। कई प्राईमरी स्कूल्ज ऐसे हैं जहां पर केवल एक ही कमरा है और पाच पांच क्लासिज लगती हैं। पांच पांच टीचर्ज वहां काम करते हैं। नारनौल में भी

एक ऐसा स्कूल है जहां पर पांच अध्यापक काम कर रहे हैं लेकिन वहां पर कमरा केवल एक ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सूखा राहत स्कीम के अन्तर्गत कुछेक कमरों का निर्माण हुआ है लेकिन बच्चों की शिक्षा के लिये कमरों का प्रावधान किया जाना चाहिये। इसके लिये सरकार को पूरा सर्वे करवाना चाहिये और प्राईमरी ऐजुकेशन की ओर सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिये। अगर ज्यादा कमरों की व्यवस्था न हो पाये तो कम से कम एक कमरे के स्थान पर दो तीन कमरे हरेक स्कूल में होने चाहियें ताकि बच्चों की पढ़ाई अच्छे ढग से और रूचि के साथ हो सके। लड़कियों की ऐजुकेशन की तरफ खास ध्यान दिया गय। है और इस बजट में भी लड़कियों के स्कूलों की व्यवस्था की गई शै। यह बहुत ही अच्छी बात है। नारनौल डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में एक कालेज है वहां 600 लड़कियां है। लड़कियों की क्लासिज की व्यवस्था तो कर दी गई है। और बिल्डिग भी दे दी गई है। लेकिन अगर लड़कियो के लिये अलग से कालेज की व्यवस्था कर दी जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। इसके साथ साथ उस कालेज की अध्यापिकाएं भी महिलायें होनी चाहिये। अगर सरकार विशेष तौर पर मेरे इन सुझावों पर गौर करेगी तो शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये एक विशेष योगदान होगा।

डिप्टी स्पीकर साहब, इस से अगली बात मैं नारनौल डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर एक पर्यटक केन्द्र स्थापित करने के लिये कहना चाहता हूं। जिस प्रकार राज्य के अन्दर हर जिला मे कम से

कम एक एक पर्यटक केन्द्र स्थापित किया हुआ है उसी तरह से नारनौल में भी एक पर्यटक केन्द्र बनाया जाना चाहिये। नारनौल एक ऐतिहासिक स्थान है। वह बीरबल की भूमि है। वहां के ऐतिहासिक स्थल जल महल को डिवैल्प किया जा सकता है। उसमें नहर का पानी डाल कर उसको रमणीक बनाया जा सकता है। इसी तरह से बीरवल का छत्ता है उसको भी डिवैल्प करके पर्यटक स्थान वनाया जा सकता है। मेरी प्रार्थना है कि नारनौल की ओर भी इस बारे में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे अगली बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है वहां प्रदेश के किसानों की ओर भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये क्योंकि आज गरीब किसानों के साथ वड़ी भेदभाव की नीति वरती जा रही है जिससे इस प्रदेश का भोला भाला किसान लुट रहा है। अभी आर्य साहब ने बोलते हुए कहा कि किसानों को फव्वारा सैट्स बेचने और खरीदने में काफी दिक्कतें आती है। मैं इस बारे में एक स्कैण्डल आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। रेट्स वगैरह मे किसानों को बुरी तरह से लूटा जाता है। बीज की एजेसियां किसानों कौ धोखा देती हैं। उनको पूरा माल नहीं दिया जाता। नांगल चौधरी मैं कम से कम 50 किसानों ने अपने दस्तखत करके थाने में रपट दर्ज करवाई है कि उन से पैसे तो ले लिये गये लेकिन फव्वारा सैट्स नहीं दिये गये। वे लोग आज कचहरियों के चक्कर काट रहे है। जो बिचौले है, वे किसानों को

बुरी तरह से लूट रहे है। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना कि वे इस ओर विशेष ध्यान दें और किसानो कौ इस तरह की खरीद के मामलों में बिचौलों से बचायें, तभी सरकार की सही नीति का लोग लाभ उठा सकेंगे नही तो इस हरियाणा का गरीब किसान बुरी तरह से पिस जाएगा। आशा है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और इसकी जांच करवाई जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब ने अपने ऐडैरस में पिछली सरकार का हवाला देते हुए इस सरकार की नीतियों और रीतियों का वर्णन बहुत ही अच्छे ढंग से किया है और आज हरियाणा की आम जनता यह महसूस करती है कि राज्य के खजाने में उनका भी कुछ हिस्सा है। इन शब्दों के साथ मैं गवर्नर साहब के अभिभाषण के लिये हाउस के सामने रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

13.00 बजे।

श्री परमानन्द (जीद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गवर्नर साहब ने कल इस सदन के सामने जो अभिभाषण पेश किया था, मैं उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय गवर्नर साहब ने जो यह ऐड्रैस इस सरकार के सम्मुख पेश किया है यह उनका इस सरकार के सम्मुख बजट सैशन का पहला ऐडैरस था। गवर्नर साहब ने इस ऐडैरस के जरिए न्याय युद्ध लड़ने वालों की जन आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाली

सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और कार्य क्षमताओं का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। यह वास्तव में एक सराहनीय ऐडैरस है। इस ऐड्रैस के बारे में हमारे एक कांग्रेसी भाई ने यह कहा कि मुझे तो इस ऐड्रैस में ऐसी कोई बात नई नजर नहीं आती, कोई खास बात नजर नहीं आती। वही पुरानी बातें हैं। मैं सदन को यह कहना चाहूंगा कि हुमारे कांग्रेसी भाई ने तो वह बात कर दी जैसे एक नट की लड़की तो बांस पर चढ़ जाती है और वहां पर एक अंगूठे पर खड़ी हो जाती है लेकिन नीचे खड़ा हुआ नट फिर भी कहता है कि अभी कमी री गई। उन्होंने तो यह बात कर दी। इस सरकार की जो जनहित नीतियां हैं, जी आम आदमी को फायदा पहुंचाने के कार्यक्रम हैं और हरियाणा की जनता को आगे ले जाने के जो प्रोग्राम हैं उन सबको देखते हुए यह ऐड्रैस एक सराहनीय ऐड्रैस दै। इस एडैरस के अन्दर सबसे पहले कानून और व्यवस्था का जिक्र करते हुए दरिया– पुर काण्ड का जिक्र आया है। दरियापुर काण्ड के दोषियों को पुलिस ने हिम्मत करके पंजाब के अन्दर जा कर पकड़ा इस काम के लिये हमारी पुलिस सराहने योग्य णै। लेकिन साथ साथ यह बात भी सोचने वाली है कि भारतवर्ष के अन्दर दूसरे प्रान्तों में पुलिस क्या कर रही है? वह पंडरिया जैसे काण्ड करती है और कमजोर वर्गो पर जुल्म ढाती है। कुछ समय पहले वहां की पुलिस ने एक शीला नाम की लड़की की इज्जत लूटी। इसलिये जहां पुलिस आतंकवादियों को पकड़ने की हिम्मत करती है उसके साथ साथ उसको अपना भी सुधार करना चाहिये। हमारे प्रान्त के अन्दर ला एंड आर्डर की स्थिति को

सुधारने की जो पुलिस की भावना है उसके लिए पुलिस बधाई की पात्र हे। हरियाणा के अन्दर जो वातावरण बिगड़ा हुआ था उसको इसने बड़े अच्छे ढंग से ठीक किया है।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि खरीफ फसल के टाईम पर जो भयंकर सूखा पड़ा था, उस सूखे के लिये राहत देने के बारे में हमारी सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 400 करोड़ रुपए की मांग की थी लेकिन उसके बदले में केन्द्रीय सरकार ने केवल 37 करोड़ 22 लाख रुपए दे कर किसानों के दुखों पर नमक छिड़का है। यह कोई राहत देने वाली बात नहीं है बल्कि और भी चुबने वालो बाते है। हमारी सरकार ने तो केवल 400 करोड़ रुपए की मांग की थी जबकि हरियाणा के किसानों का 700 करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ है लेकिन उसके बदले में केन्द्रीय सरकार ने केवल 37 करोड़ 22 लाख रुपए ही दिए हैं। दूसरी तरफ एक छोटा सा प्रान्त है, जिसकी आबादी केवल साढ़े सात लाख के करीब होगी, उस प्रान्त में केवल वोट बटोरने के लिये 36 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर दी गई हालांकि वहां पर अकाल नाम को कोई बात नही थी। इसके अलावा राजस्थान प्रान्त को 488 करोड़ रुपए मिला है और गुजरात को 352 करोड़ रुपए मिला है लेकिन हरियाणा को केवल 37.22 करोड़ रुपए दे कर बहुत बड़ा मजाक किया गया है। ऐसी हालत में भी, हरियाणा में सूखे की स्थिति होते हुए भी इस सरकार ने न केवल हरियाणा के लोगों के लिये काम किए हैं बल्कि राजस्थान

के वासियों और पशुओं को भो सहायता पहुँचाई जा रही है। इस भंयकर सूखे के कारण जहां लोग अपना पेट नहीं भर पा रहे थे वहां पर वे लोग अपने पशुओं का पेट कैसे भर पाते इसलिए राजस्थान के लोगों ने हरियाणा की सीमा पर अपनी गउएं या दूसरे पशु छोड़ दिए हैं। आप राजस्थान मे निकल जाएं तो आपको अनेक स्थानों पर मरे हुए पशुओं की हड्डियां ही हड्डियां नजर आएंगी। जो पशु राजस्थान से हरियाणा की सीमा में आये है उन्हें जीवित रखने के लिये यहां के लोगों ने गऊशालाऐं वगैरा बनाई है ताकि उनको जीवित रखा जा सके.। इस काम में हरियाणा सरकार ने भी ऐसी गउशालाओं को सहायता देकर एक अच्छा काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय जहां हरियाणा सरकार अपने लोगों को रोजगार के साधन दे रही है, वहां दूसरे कार्यों की तरफ भी ध्यान दे रही हे। राजस्थान की औरतें अपने हाथों में हाथी दांत के कड़े वगैरा पहने हुए मिलती हैं उनकी सरकार को केन्द्र ने 488 करोड़ रुपये दिए जबकि हरियाणा सरकार को सिर्फ 37 करोड़ 22 लाख रुपए ही दिए गए। इसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने अपने लोगों का ख्याल रखा है और राजस्थान के लोगों का भी ख्याल रखा है। इस सूखे के कारण जहां सरकार ने पशुओं के पीने के पानी के लिए जोहड़ वगैरा भरवाये हैं, वहां 500 क्यूसिक्स पानी भी सिंचाई और पीने के पानी के लिये अतिरिक्त उपलब्ध करवाया है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि सूखा राहत के नाम पर इस सरकार ने बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं जहां तक किसानों, भूमिहीनों, और मजदूरों की बात है, उनके लिए भी

इस सरकार ने बहुत काम किए हैं। इन लोगों को राहत पहुंचाने के लिये 56 लाख मैनडेज क्रिएट किए गए हैं। जिनके द्वारा भूमिहीनो, पिछड़े वर्ग और मजदूरों को रोजगार मिला है। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मुख्य मन्त्री राहत कोष से भी मैचिंग ग्रान्ट दी जाती रही है। उपाध्यक्ष महोदय, हर क्षेत्र में इस सरकार ने एक नई दिशा दी है। जहां गांवों के अन्दर कुल आबादी का 80 प्रतिशत हिस्सा रहता है वहां आज तक बजट का 50 प्रतिशत से अधिक पैसा कभी खर्च नहीं किया गया। हमारी वर्तमान सरकार 55 प्रतिशत बजट का पैसा गांवों में लगाये जाने की योजना रखती है। यह एक अच्छी बात है। मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि जहां पर हमारी सरकार विकास कायों की तरफ उचित ध्यान दे रही है वहां पर साथ ही साथ सामाजिक सेवाओं की तरफ भी कम ध्यान नही दे रही। हमारी सरकार ने 600 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट में से विकास कार्यों पर 440 करोड़ रुपये और 160 करोड़ रुपये स्वास्थ्य सेवाओ सामाजिक कल्याण कार्यों आदि पर ग्बर्च करने के लिए रखे हैं। हमारी सरकार ने पिछड़े वर्ग के लोगो, मजदूरों, गर्भवती महिलाओं और दूध पीते बच्चों के लिये भी अलग से धन रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चादद्वगा कि हरिजन बच्चों की स्कूल–कालेज की व इम्तहान की फीस माफी जारी रखते हुए हरिजन कल्याण निगम और पिछड़े वर्ग कल्याण निगम के द्वारा इन लोगों को रोजगार तक देने की कोशिश को गई है। यहां पर मैं एक बात उप–मुख्य मन्त्री जो के द्वारा मुख्य मन्त्री तक पहुंचाना चाहुंगा। हरिजन

कल्याण निगम द्वारा वर्ष 1987– 88 के दौरान 11784 व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध करवा कर रोजगार के साधन जुटाये गये हैं लेकिन पिछडे वर्ग कल्याण निगम द्वारा केवल 921 व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध करवा कर रोजगार के साधन उपलब्ध कराये गये। इस लिए मैं मुख्य मन्त्री जो से प्रार्थना करूंगा कि वे पिछड़े वर्ग कल्याण निगम को अधिक वित्तीय सहायता दें ताकि रोजगार देने का ज्यादा प्रबन्ध हो सके। इस समाज का भारत मैं सदियों से यानी अंग्रेजों के टाईम से ही शोषण होता रहा है और पिछड़े. वर्ग में भी दस्तकार वर्ग का अधिक शोषण हुआ है। पिछले चालीस सालों में भी लगातार सैन्टर के अन्दर और अन्य प्रांतों में जहां जहा कांग्रेस की सरकार थी उसी नीति पर चलते हुए पूंजीपतियों को पाला गया और दस्तकार वर्ग कों बेकार करके राख दिया गया आध दस्तकार लोग बेकार हैं, उन्हें दोबारा से रोजगार देने के लिए विशेश ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिये आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना है कि पिछड़े वर्ग कल्याण निगम को अधिक वित्तीय सहायता दे कर लोगों को रोजगार के अधिक साधन उपलब्ध कराये जायें।

डिप्टी स्पीकर साहब, अन्त में एक प्रार्थना करके बैठना चाहूंगा कि जहां प्रांत के अन्दर कहीं इंजीनियरिंग कालेज, कही कम्पुटर, कहा रिसर्च सैन्टर और कही पर सौर ऊर्जा सैंटर खोल दिये गए हैं वहां जिला जीन्द में जो हरियाणा के केन्द्रीय भाग में स्थित है, कोई इस प्रकार की विकास योजना का लाभ नहीं दिया

गया है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि वहां पर भी कोई न कोई विकास केन्द्र शुरु किया जाये ताकि इस जिले की भी उन्नति हो सके। जिला जीन्द चूंकि न्याय युद्ध में हमेशा अग्रणी रहा है इसलिये उसे आगे बढने का अवसर अवश्य मिलना चाहिये और वहां पर कोई न कोई इस प्रकार की विकास योजना आरम्भ की जानी चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, जो बुढ़ापा पैन्शन दी गई है इसको कोई उदार पैन्शन कहता है और कोई सार्वजनिक पैन्शन कहता है। चौधरी देवी लाल और इस वर्तमान सरकार ने लोगों की भावनाओं की तरफ जो देखा है यह बडी बात है। कांग्रेस राज में हजारों लोगों को पैन्शन मिलती थी लेकिन आज की सरकार साढ़े छरू लाख लोगों को पैन्शन दे रही है। यह पैन्शन केवल मात्र अनुदान, सहायता के नाम पर या दया करके नहीं दी गई है बल्कि इस सरकार की भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है, डिगनिटी औफ लेबर। जिस प्रकार इस समाज के अन्दर सरकारी कर्मचारी 58 वर्ष की नौकरी पूरी करने के याद पैन्शन का अधिकारी हो जाता है उसी प्रकार से दस्तकार, किसान भी 65 वर्ष के बाद अधिकारी हो जाता है। इन सारी बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं अन्त में आपका धन्यवाद करते हुए माननीय सदस्य द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रत्न लाल कटारिया (रादौर, अनुसूचित जाति): मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, राज्य पाल महोदय ने हरियाणा की

नीतियों के बारे में जो अभिभाषण सदन में रखा है उस की चर्चा में भाग लेते हुए मैं अर्ज करूगा कि हिसार जिले में दरियापुर के पास सात जुलाई को आतंकवादियों ने हरियाणा की इस लोकप्रिय सरकार को, जो चौधरी देवी लाल के नेतृत्व में बनी है, हिलाने के लिए कार्यवाही की थी लेकिन इस सरकार को इस बात का श्रेय जाता है कि हुस ने वक्त पर सारी स्थिति को नियन्त्रण में किया है। सरकार ने उन आतंकवादियों को पकड कर सारी स्यिति पर काबू पा लिया।

डिप्टी स्पीकर साहब, इस अभिभाषण मे रास्ता रोको शहीदों के बारे में भी कहा गया है यानी जिन्होने न्याय युद्ध के दौरान अपनी जान की बाजी लगायी, उनके नाम पर कुछ सड्कों के नाम जोड़ दिए गए हैं लेकिन केवल इससे काम नही चलेगा। उनके नाम पर तो कोई बहुत अच्छी यादगार बनायी जानी चाहिए। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में कहा गया है कि इस वर्ष बहुत भंयकर सूखा पड़ा। हरियाणा सरकार नें केन्द्र सरकार से 443 करोड़ रुपए की राशि सूखा राहत कार्यों के लिए मांगी। केन्द्र सरकार ने हरियाणा के प्रति अपनी बदनीयती रखते हुए केवल मात्र 38 करोड़ की राशि सूखा राहत कार्यों के लिए दी। परन्तु फिर भी इस सरकार ने अपने सीमित साधनों से हरियाणा प्रदेश मे नगर– नगर और गांव गांव के अन्दर कई प्रकार की योजनाए चलाई। गांवों मैं सड्कों का निर्माण किया गया और कई स्कूल बनाए गए। गाव की गलियों को पक्का किया

गया और केन्द्र सरकार की इतनी बुरी नजर होते हुए भी हरियाणा प्रदेश ने न केवल अपने प्रदेश के लोगों को राहत दी बल्कि राजस्थान से जो हजारों ऊंटों के झुण्ड आए जिन्हें आप ने सड्कों पर देखा होगा, उनको भो चारा प्रदान किया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्रधान मन्त्री कांग्रेसी राज्य उड़ीसा के अन्दर कालाहाण्डी गए थे और वहां जाकर उन्होंने देखा था कि किस तरह ले 21––21 दिन तक लोगो को भोजन नहीं मिला और किस तरह से कई व्यक्ति भूख के मारे दम तोड़ गए। हरियाणा प्रदेश देश भर में एक ऐसा प्रदेश है जिस ने सूखे का मुकाबला बिना केन्द्र की किसी सहायता के अपने पांव पर खड़े रह कर इस संकट की स्थिति में डटकर किया है।

स्पीकर साहब, इस अभिभाषण में हरियाणा में हरिजनों के लिए मकान बनाने के बारे में कहा गया है। मैं इस के बारे में कहना चाहूंगा कि काग्रेस सरकार के समय में हरिजनों के लिए जो मकान बनाए गए थे, वे इन्सानों के रहने के काबिल नहीं थे। करनाल जिला के अन्दर रम्भा गांव मै सैकड़ों मकान बनाए गए हैं लेकिन 8–10 सालों के अन्दर उन मकानों में कोई भी हरिजन जाने को तैयार नहीं हुआ क्योंकि वे मकान इन्सानों के रहने के काबिल ही नहीं थे। मैं अपनी सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह हरिजनों को ऐसे मकान बनाकर दे जिनके अन्दर वे अपना जीवन व्यतीत कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले गुरु रविदास जी महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर बोलते हुए हरियाणा के आदरणीय मुख्य मन्त्री चौधरी देवी लाल जो ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अन्दर डाक्टर अम्बेदकर चेयर के वारे में कहा। मैं सदन में अध्यक्ष जी के माध्यम से यह चाहूंगा कि शिक्षा का जो अगला सैशन शुरु होने वाला है उसके अन्दर डा० अम्बेदकर के नाम के ऊपर यह चेयर चालू की जानी चाहिए।

स्पीकर साहब, इस अभिभाषण के अन्दर कहा गया है कि हरियाणा प्रदेश में दस हजार के लगभग आगनवाड़ी केन्द्र खोले जाएंगे। इसके बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस टाथ के समय में आगनवाडियो में धांधलियां होती रही हैं उस तरह से अब नहीं होनी चाहिए। राशन आता था परन्तु वह राशन उन छोटे छोटे बच्चों के मुंह में पहुंच नही पाता था। वहां पर जो कर्मचारी या प्रबन्धक थे, वही उन बच्चों के मुंह से सारे का सारा राशन छीन कर बाजार के अन्दर बेच देते थे। इस बारे में ध्यान दिया जाए। ऐसा नही होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश ही भारत में एक मात्र ऐसा राज्य था जहां पिछले 20 सालों से नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं हुए थे। इस प्रदेश की सरकार को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने सरकार बनते ही प्रदेश के अन्दर नगरपालिकाओं के चुनाव करवाए और जो डैमोक्रेटिक सिस्टम है उसका पालन करते हुए

शहरों के वाशिन्दों को यह हक दिया कि वह अपनी मन–मर्जी से अपने शहरों की व्यवस्था चला सकें।

इसी तरह से ओल्ड एज पैंशन की बात है जो कि इस सरकार ने अपने राज्य के वृद्ध लोगों को दी है और जिस की चर्चा सारे भारत के अन्दर हो रही है। पूरे हिन्दुस्तान में चौधरी देवी लाल जी ही एक मात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने ऐसा काम करके दिखाया जो आज तक नहीं हुआ था। इसी तरह से किसानों के बारे में उन्होंने जो कुछ करके दिखाया वह भी अपने आप में एक मिसाल ही है। हम लोग जब रात को टेलीविजन देखते हैं तो भारत के प्रधान मन्त्री किसान का नाम लेते हैं और उसके हितों की बात करते हैं। भारत के अन्दर किसान के साथ आज तक बहुत अन्याय होता आया था। लेकिन इस बात का श्रेय भी चौधरी देवी लाल की डायनेमिक लीडरशिप को ही जाता है कि उन्होंने किसान के साथ हो रहे इस अन्याय को दूर करवाया और जिस के फलस्वरूप आज हर प्रदेश में किसानों की भलाई करने की होड़ लगी है। सभी लीडर कहते हैं कि हम भी किसानों के हमदर्द हैं। इस का सारा श्रेय चौधरी देवी लाल जी को जाता है।

स्पीकर साहब, अभिभाषण में ओल्ड एज पैशन के अलावा विधवाओं और अपंगों को दी जाने वाली राहत के बारे में भी कहा गया है। मैं चाहूंगा कि उन्हें भी यह राहत मिलती रहनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, पीछे जो बरसात हुई उससे मेरे रादौर क्षेत्र के अन्दर ओलावृष्टि की वजह से जबरदस्त नुकसान हुआ और 50 प्रतिशत गांवों के अन्दर तो फसल सौ परसैटं डैमेज हो गई। इसके बारे में मैं कहूंगा कि वहां विशेष राहत दी जाए। आदरणीय मुख्य मन्त्री जी ने चार सौ रुपए पर एकड़ देने की घोषणा वैसे तो अगले ही दिन कर दी थी लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चार सौ रुपए प्रति एकड़ की राहत आज के मंहगाई के जमाने में बहुत कम है। इसको कम से कम दो हजार रुपए एकड़ कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, अम्बाला और कुरुक्षेत्र की बैल्ट गन्ने की है। वहां ओलों से इस फसल का बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए मेरी प्रार्थना हे कि जो दो स्पैशल कोटे किसानों को पर्ची के लिए दिए जाते हैं वे अवश्य दिए जाएं। अध्यक्ष महोदय, अम्बाला और कुरुक्षेत्र जिलों के लिए दादुपुर नलवी नहर की योजना है। मैं चाहूंगा कि इस नहर का निर्माण शीघ्र करें ताकि इन जिलों की 25 लाख जनता को राहत मिल सके। धन्यवाद।

डा० बृज मोहन (जगाधरी): स्पीकर साहब, मैं भी गवर्नर साहब के ऐड्रैस पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे कांग्रेसी भाई यहां से उठ कर चले गए हैं केवल एक भाई बैठा है। मैं सब से पहले ओलों की बात से शुरु करता हूं। मार्च, 1986 में हमारे इलाके में बड़े भारी ओले पड़े थे जिसकी वजह से कई दोस्त तो बिल्कुल तबाह हो गए थे। कई जगह सौ परसैंट फसल डैमेज हो गई थी। बदकिस्मती की वात

यह है उस नुकसान का मुआवजा इनकी सरकार नहीं दे सकी। पटवारी ने वहां की गिरदावरी ठीक नहीं की थी और तहसीलदार ने अटैस्टेशन नहीं की थी। ओलों से मरे हुए किसान आज भी दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। उनको अभी तक भी पैसा नहीं मिला है। पैसा न मिलने का कारण यही है कि उनकी गिरदावरी और तसदीक ठीक नही हुई। हमारे मन्त्री जी भी कोशिश कर रहे हैं कि जिनका नुकसान हुआ है उनको पैसे कैसे दिए जाएं, हालांकि उसके लिए हमारे पास पैसा है लेकिन गिर– दावरी ठीक न होने की वजह से यह पैसा उनको नही दिया गया। अब की बार जो ओले पड़े हैं उनसे जगाधरी का भी थोड़ा सा इलाका प्रभावित हुआ है। उसकी गिरदावरी हो गई है और उम्मीद है कि मुआवजा जल्दी ही दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं ला एण्ड आर्डर की बात सुनाता हूं। लालड़ और दरियापुर के केस करीबन साथ साथ ही हुए। यह घटना होनी तो एक ही दिन थी लेकिन कुछ देर हो गई। जो उनकी तैयारी थी या जो उनका प्रोग्राम था उसमें डिले हो गई। उनमें से लालडू वाले मुजरिमों की तो पहचान हो गई है और कुछ पकड़ भी गए है तथा कुछ पकड़े भी जा रहे है। दरियापुर के तकरीबन सारे मुलजिम वहां पर पकड़ लिए गए या उन पर काबू पा लिया गया। आप देखें इनके जमाने में मेरे यहां जगाधरी में 1983 में थाने की बिल्डिग गिरी थी। इन्होंने थाने का कब्जा धर्मशाला पर करवा दिया। सन 1987 तक यह लोग पावर मे रहे लेकिन ये लौग थाना नहीं बनवा सके। आज भी उस धर्मशाला पर इनका कब्जा है। (व्यवधान व शोर)हम तो उसको वहां से

हटाएंगे। इसके लिए हम कोशिश करेंगे और कब्जा हटवाएंगे। यह तो थाना भी नही बनवा सके। गिरे हुए थाने की रिपेयर भी नही करवा सके। कम से कम यह तो देख लें कि चार साल के अन्दर इन्होंने क्या किया? यह उसकी रिपेयर भी नही करवा सकै। चार साल का अर्सा क्या थोडा होता है? चार साल तक यह कुछ भी नही कर सके। थाना 1982 में अपग्रेड हुआ था। मैंने ही अपग्रेड कराया था। लेकिन उस थाने की बिल्डिग 4– 5 साल तक नहीं बनवा सके। वह तो हम ही बनवाएंगे। शिफ्ट भी हम ही करेंगे। वह धर्मशाला जो गरीब लोगों के काम आती थी, वहा पर इन्होंने कब्जा कैसे किया? अगस्त के महीने में रात को थोड़ा सा शैल्टर लेने के बहाने से हुछ सिपाही सिविलियन ड्रैस में वहां पर गए और वहां पर कब्जा कर लिया। ऐसा तो नही होना चाहिए था। हम इनके कब्जे को खाली करवाएंगे। (व्यवधान व शोर)

स्पीकर साहब, ला एण्ड आर्डर और पैंशन के वारे में भी यहा पर जिक्र आया। मेरे एक साथों इलैक्शन्ज के बारे में कह रहे थे। वह म्यूनिसिपल कमेटी के इलैक्शनों के बारे में कह रहे थे। वह तो हमने करवा दिए। आप सब को पता है कि पहले भी हाई–कोर्ट द्वारा कई दफा डेट्स मुकर्रर हुई थीं फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ अपील में वह आर्डर क्वैश करवा दिए। अन्त में जब कोई चारा नही रहा तो 75 दिन वाली बात आयी। हमने 75 दिन से पहले ही इलैक्शन करवा दिए। ये लोग इलैक्शन क्यों नही करवा सके? अब यह इलैक्शन कैसे हो गया? इसका एक

कारण था। सारी म्यूनिसिपल कमेटीज पर इनका कब्जा था। उनमें पूरा–पूरा घोटाला होता था। खाने–पीने का धन्धा बना रखा था। सारा ऐडमिनिस्ट्रेशन एक आदमी के हाथ में होता था। जो वहां का लोकल एम० एल० ए० होता था उसै भी पूछा नहो जाता था। ये इलैक्शंज 19 साल के बाद हुए हैं। इलैक्शन के बाद वहां पर पब्लिक के रिप्रेजैटेटिज पहुंचे हैं। उन्होंने वहां पर जीकर छानबीन की है, तब उनको पता चला है कि यह इलैक्शन क्यों नहीं करवा रहे थे?

बैठक का समय बढ़ाना

सिचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, 5 मिनट तक हाउस बढ़ा लीजिए ताकि माननीय मैम्बर अपनी बात आज ही खत्म कर लें।

Mr. Speaker : He can continue tomorrow.

श्री वीरेन्द्र सिंहः नही जी, ये आज ही कन्क्रल्यूड कर लेंगे। कल नैकस्ट आदमी बोल लेगा।

श्री अध्यक्षः यदि हाउस की सैसं हो तो हाउस की सिटिंग 5 मिनट के लिए बढ़ा दी जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

Mr. Speaker : The time of the sitting is extended by five minutes.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

डा० बृज मोहनः वे इलैक्शन इसलिए नही कराते थे कि वहां पर इनकी चलनी बन्द हो जाएगी। ये शहरों में कोई अच्छा काम नहीं कर सके। सारे शहरों में गन्दगी है। पानी की व्यवस्था ठीक नहीं, सीवरेज की व्यवस्था ठीक नहीं, कोई गलियां ठीक नहीं, कोई नालियां नहीं। शहरों की बुरी हालत थी। इसी प्रकार देहातों की भी बुरी हालत थी। इसको ठीक करने के लिए अभी तो हमने शहरों में इलैक्शन करवा कर रिप्रेजैंटेटिव्ज भेजे हैं। देहातों में भी जरूर पंचायत के इलैक्शन होंगे जो कि डयू है। सरकार का यह बड़ा ही प्रशंसनीय काम है जो उसने लोगे के डैमोक्रेटिक राईट्स को रैस्टोर किया है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के अन्दर इन सरकार ने एक और बहुत ही अच्छा काम किया है और वह है सेल्ज टैक्स में कभी। ऐसा करके इस सरकार ने छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी और हर किस्म के व्यापारियों को राहत दी है और मैं यह कह सकता हूं कि हरियाणा ने ऐसा करके सारे देश में एक मिसाल कायम की है और कम से कम हमारे शहर के लिए तो यह एक फख्र की बात है। तीन परसैन्ट लोकल सेल्ज टैक्स और सेन्ट्रल सेल्ज टैक्स सारे देश के अन्दर कहीं नहीं है। यह बहुत ही काबिले तारीफ बात है लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसको एक जनवरी से लागू करवा दिया जाए क्योंकि इसको लागू करने की तारीख अभी निश्चित नहीं हुई है। मैं अनुरोध करूंगा कि इसको एक जनवरी से लागू करवा दिया जाए। इस सरकार ने

जितना अच्छा काम किया है उसकी सारे देश के अन्दर तारीफ हो रही है और तारीफ करनी भी चाहिए। जगाधरी जो भारत में बर्तनों की सब से बड़ी मण्डी है, सरकार के ऐसा करने से वहां पर और व्यापारी आएंगे। इसलिए मेरी फिर प्रार्थना है कि इसको जल्दी से जल्दी लागू करवा दिया जाए। ऐसी करने से सरकार को फायदा होगा और लोगों को भी फायदा होगा.। मैंने वहां पर अपने तौर पर कहा था कि अगर यह टैक्स पूरा आया तो और भी टैक्स घटाया जा सकता है। इससे जगाधरी जो मैटल इंडस्ट्री का गढ़ है उसको राहत मिलेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा और हरियाणा भी ज्यादा फले फूलेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ सरकार ने और भी बहुत काम किए हैं लेकिन उनके बारे में कहा गया कि कुछ काम नहीं किया गया। स्पीकर साहब, मैं समझता हू कि सूखे में जोहड़ खुदवाना, जोहड़ों में पानी लाना, पैदावार से चारा तैयार करना या मंगवाना यह कोई छोटा काम नहीं है। यह बहुत ही जरुरत का काम था। हम तो अम्बाला में बैठे हैं। अम्बाला में तो ट्यूबवैल्ज लगे हुए हैं और हमें पता है कि अम्बाला में सूखे का असर कम है। महेन्द्रगढ़, जींद, नारनौल और भिवानी में तो पानी बहुत कम है। लेकिन वहां भी पानी पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहां सूखा राहत के नाम से देहातों के अन्दर काफी काम हो रहा है और लोगों को काफी मजदूरी मुहैया की जा रही है। यह सरकार के बड़े ही प्रशंसनीय कार्य हैं जिनकी जितनी तारीफ की

जाए उतनी थोड़ी है। स्पीकर साहब, वैसे तो मेरे बोलने का समय समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं एक दो बातें और कह कर अपना स्थान लूंगा।

श्री अध्यक्षः अब आप जल्दी वाइंड–अप कीजिए क्योंकि हाउस का समय समाप्त होने जा रहा है।

डा० बृज मोहनः हमारे यमुनानगर के अन्दर किसी प्राइवेट संस्था द्वारा डैंटल कालेज खोला गया है और वह भारत वर्ष में अपनी ही किस्म का पहला कालेज होगा। वैसे होता यह है कि पहले मैडीकल कालेज खोला जाता बै उसके बाद डैन्टल कालेज खुलता है लेकिन यह दूसरा कालेज है जोकि मैडीकल कालेज से पहले खुला है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से रिक्वैस्ट है कि यमुनानगर के अन्दर एक मैडीकल कालेज की स्थापना की जाए ताकि उस इलाके के लोगों को राहत मिल सके।

श्री अध्यक्षः अब आप बैठिए। अब हाउस कल प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

13.35 बजे।

(तत्पश्चात सदन बुधवार, दिनांक 16–3–1988 को प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थगित हुआ)।